

# वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अंदर और बाहर की कहानी



**GST**  
Goods & Services Tax

[f @gstsite](#)

[t @gstsite](#)

[i @gstsite](#)

[#GSTsiteIndia](#)

[www.gstsiteindia.com](#)

[contact@gstsiteindia.com](#)





## सामग्री

1	GST क्या है और इसे भारत में कैसे पेश किया गया था?.....	6
1.1	सबसे पहले, आइए हम GST शब्द को कम करने की कोशिश करें.....	6
1.2	GST के व्यापक लाभ क्या हैं?.....	8
2	भारत में GST की आवश्यकता क्यों थी- GST परिषद का परिचय।.....	10
2.1	GST परिषद और इसके कार्य क्या हैं?.....	11
2.2	GST परिषद की संरचना कैसे की जाती है?.....	11
3	GST के तहत अब किन सभी प्रकार के करों और शुल्कों को शामिल किया गया है? .....	15
4	GST वास्तव में कैसे काम करता है! GST के प्रकार!.....	19
4.1	CGST - केंद्रीय वस्तु और सेवा कर.....	22
4.2	SGST - राज्य माल और सेवा कर.....	22
4.3	IGST - एकीकृत माल और सेवा कर.....	23
4.4	UTGST - भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर .....	23
5	GST संशोधन विधेयक क्या है? .....	25
5.1	समाप्ति.....	28
6	GST के तहत व्यापार प्रथाओं को फिर से परिभाषित किया गया!.....	29
6.1	व्यापार करने का तरीका: GST से पहले .....	30
7	भारत में GST प्रक्रिया और विभिन्न फाइलिंग फॉर्म!.....	34
7.1	GST के तहत रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया .....	37
7.2	GST के तहत भुगतान प्रक्रिया.....	40
8	GST रिटर्न कैसे फाइल करें!.....	42
8.1	GST फाइल करने के लिए किन लोगों की जरूरत है? .....	45
9	GST गैर-अनुपालन दंड और अपील क्या है!.....	46
9.1	अपराध और दंड.....	46
10	GST लागू होने के क्या लाभ हैं? .....	50
10.1	व्यापार करना आसान बनाना .....	51



10.2	2. रसद लागत और राज्यों में लगने वाले समय में कमी .....	52
10.3	3. नए व्यवसायों के लिए उच्च छूट .....	52
10.4	वित्तीय समावेशन .....	52
11	देश में GST से पहले और बाद में जमीनी अंतर क्या हैं? .....	54
12	GST भारत में विभिन्न उद्योगों और ट्रेडों को कैसे प्रभावित करता है? .....	58
13	GST आपके व्यक्तिगत वित्त को कैसे प्रभावित करता है? .....	63
13.1	खाद्य पदार्थ .....	63
13.2	घरेलू सामान .....	64
13.3	अन्य घरेलू सामान और उपकरण .....	64
13.4	दवाओं .....	64
13.5	मोबाइल नेटवर्क, डीटीएच और अन्य सेवाएं .....	65
13.6	रेस्तरां .....	65
13.7	मूवीगोअर्स .....	65
13.8	बैंकिंग, वित्त और बीमा .....	66
13.9	सफ़र .....	67
13.10	पर्यटन .....	67
13.11	सोना .....	67
13.12	आवास .....	68
14	GST के तहत छूट क्या है? .....	69
15	GST भुगतान और रिफंड पर एक अंतर्दृष्टि! .....	76
15.1	GST के तहत क्या भुगतान किया जाना है? .....	76
15.2	GST भुगतान की गणना कैसे करें? .....	77
15.3	भुगतान कौन करेगा? .....	78
15.4	GST भुगतान के लिए टीडीएस तिथि .....	78
15.5	इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्या हैं? .....	78
15.6	GST भुगतान कैसे करें? .....	79
15.7	भुगतान न करने या विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना .....	79



15.8	रिफंड का दावा कब किया जा सकता है?.....	79
15.9	GST रिफंड की गणना कैसे करें? .....	80
15.10	रिफंड का दावा कैसे करें? .....	81
16	भारत में वस्तु एवं सेवा कर का भविष्य क्या है? .....	82
17	GST के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर .....	85
17.1	GST क्या है?.....	85
17.2	प्रस्तावित GST कैसे काम करता है?.....	85
17.3	किसी विशेष राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लेनदेन पर केंद्रीय GST (CGST) और राज्य GST (SGST) के तहत एक साथ कर कैसे लगाया जाएगा?.....	86
17.4	अंतर-राज्य लेनदेन पर कर लगाने का तंत्र क्या होगा?.....	86
17.5	GST के तहत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित कर क्या हैं?.....	86
17.6	वे कौन से सामान/क्षेत्र हैं जो GST के दायरे से बाहर होंगे? .....	87
17.7	GST के तहत दर संरचना क्या होगी?.....	87
17.8	GST के तहत थ्रेशोल्ड लिमिट और कंपाउंडेड लेवी क्या होगी?.....	87
17.9	GST के तहत आयात पर कैसे लगोगा टैक्स?.....	87
17.10	GST के तहत क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे काम करेगा?.....	88
17.11	GST को लागू करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों है? .....	88
17.12	माल की आपूर्ति पर GST लगाने का क्या मतलब होगा?.....	88
17.13	सेवाओं की आपूर्ति पर GST लगाने का क्या मतलब होगा? .....	88
17.14	नए व्यवसायों / आवेदकों के लिए प्रस्तावित GST व्यवस्था के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी?..	88
17.15	मौजूदा व्यवसायों / आवेदकों के लिए GST के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? .....	89
17.16	GST शासन के तहत जारी किए जाने वाले कर चालान की सामग्री क्या है?.....	89
17.17	रिटर्न कैसे और कब दाखिल किया जाना चाहिए?.....	89
17.18	कर के भुगतान का तरीका क्या है? .....	90
17.19	GST के तहत निर्यात पर कर कैसे लगोगा?.....	90
17.20	GST व्यवस्था में कोई करदाता कब रिफंड के लिए जा सकता है? प्रस्तावित GST कानून के तहत रिफंड प्रक्रिया कैसे काम करेगी? .....	90
17.21	प्रस्तावित GST व्यवस्था के तहत विवाद समाधान तंत्र कैसे काम करता है?.....	90



- 17.22 GST ढांचे के तहत वर्तमान व्यवस्था में दी गई क्षेत्र-आधारित छूटों सहित विभिन्न छूटों का क्या होता है? 90
- 17.23 उपभोग पर गंतव्य आधारित कर की अवधारणा वास्तव में क्या है?..... 91
- 17.24 GST व्यवस्था के तहत विवादों को कैसे हल किया जाएगा?..... 91
- 17.25 अनुपालन रेटिंग तंत्र का उद्देश्य क्या है?..... 91
- 17.26 क्या कार्रवाई योग्य दावे GST के लिए उत्तरदायी हैं?..... 91
- 17.27 क्या प्रतिभूतियों में लेनदेन GST में कर योग्य है?..... 91
- 17.28 सूचना वापसी की अवधारणा क्या है? ..... 91
- 17.29 विभिन्न कंपनियों के पास विभिन्न प्रकार के लेखा सॉफ्टवेयर पैकेज हैं और रिकॉर्ड रखने के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप अनिवार्य नहीं है। विभाग इन जटिल सॉफ्टवेयर को कैसे पढ़ सकता है? ..... 92
- 17.30 क्या प्राप्तकर्ता द्वारा लौटाए गए माल के कर उपचार के लिए GST में कोई प्रावधान है? ..... 92
- 17.31 क्या बिना विचार के की गई आपूर्ति भी GST के दायरे में आएगी?..... 92
- 17.32 क्या किसी धर्मार्थ संस्था द्वारा आवश्यक वस्तुओं को देना कर योग्य गतिविधि होगी? ..... 92
- 17.33 माल या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में लेनदेन को कौन सूचित कर सकता है?..... 92
- 17.34 समग्र आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति क्या हैं? ये दोनों एक-दूसरे से कैसे अलग हैं?..... 93
- 17.35 GST के तहत समग्र आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति का उपचार क्या है?..... 93
- 17.36 क्या सभी वस्तुएं और सेवाएं GST के तहत कर योग्य हैं?..... 93
- 17.37 रिवर्स चार्ज से क्या तात्पर्य है? ..... 93
- 17.38 क्या रिवर्स चार्ज तंत्र केवल सेवाओं पर लागू है?..... 93
- 17.39 अपंजीकृत व्यक्तियों से आपूर्ति प्राप्त होने के मामले में क्या निहितार्थ होंगे?..... 93
- 17.40 क्या आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति GST के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है? ..... 94
- 17.41 कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्स चुकाने का विकल्प चुनने की सीमा क्या है?..... 94
- 17.42 कंपोजिशन स्कीम के लिए टैक्स की दरें क्या हैं?..... 94
- 17.43 एक वित्तीय वर्ष के दौरान कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये के कारोबार को पार कर जाता है यानी वह दिसंबर में 50 लाख रुपये के कारोबार को पार कर जाता है? क्या उसे वर्ष की शेष अवधि यानी 31 मार्च तक कंपोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी?



- 17.44 क्या एक कर योग्य व्यक्ति, जिसके पास कई पंजीकरण हैं, केवल कुछ पंजीकरणों के लिए कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र होंगे?..... 94
- 17.45 क्या कम्पोजिशन योजना का लाभ निर्माता और सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाया जा सकता है?..... 95



# 1 GST क्या है और इसे भारत में कैसे पेश किया गया था?



GST के बारे में सब कुछ जानें

हाल ही में, GST के बारे में बहुत प्रचार किया गया था, जो प्रचलित कर प्रणाली में संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा पेश किया गया नवीनतम करा धान सुधार है।

इसने आम जनता के बीच हलचल और अनिश्चितता की भावना लाई, सिर्फ इसलिए कि अवधारणा और लाभो को समझा नहीं गया था। इस सेगमेंट में हम GST से जुड़े हर पहलू पर समझने में आसान और भरोसेमंद भाषा में चर्चा करने जा रहे हैं।

## 1.1 सबसे पहले, आइए हम GST शब्द को कम करने की कोशिश करें

नाम के अनुसार; GST – वस्तु और सेवा कर, कर का एक एकल एकीकृत रूप है, जो सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं को देने और लेने में शामिल सभी ट्रेड और लोग अब अलग-अलग व्यवसायों में लगाए गए करों के कई अलग-अलग रूपों में उलझने के बजाय GST का भुगतान करेंगे। GST ने कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया, जो पहले व्यवहार में थे, और इस प्रकार कराधान प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरल बना दिया। GST की शुरुआत के पीछे प्रमुख दृष्टिकोण न केवल राज्य स्तर पर, बल्कि केंद्रीय स्तर पर कर प्रक्रियाओं को एकीकृत करना और राष्ट्र की आर्थिक बेहतरी लाना था।



इस प्रकार, GST वास्तव में एक स्मार्ट कराधान प्रणाली है।



पिछली कर प्रणाली में, वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण, बिक्री और खपत पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में कर एकत्र किए गए थे (हम अध्याय 3 में इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे) GST लागू होने के साथ, ऐसे सभी करों को बदल दिया जाएगा और प्रचलित 2 प्रमुख कर होंगे, 1। GST और 2. आयकर।

यह कराधान प्रणाली में सुधार और केंद्र और राज्य स्तर पर करों को विलय करके भारत को एक आम बाजार में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा सकारात्मक कदम है। यह सुधार सभी के लिए जीवन को आसान और सरल बनाने जा रहा है, और व्यापार सौदों में बहुत पारदर्शिता लाएगा, जो निश्चित रूप से काफी हद तक भ्रष्टाचार को मारने वाला है।

अब, आइए यात्रा पर एक नज़र डालें कि भारत में GST कैसे लागू किया गया था।

GST की शुरुआत कुछ अनिवार्य कदमों में हुई:

1 अप्रैल, 2006 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में कराधान को सरल बनाने के लिए GST के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया गया था, जो पहले से ही कई विदेशी देशों में प्रचलित था।

इसके बाद, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने 2007 की पहली तिमाही में GST का रोडमैप बनाने का कार्य शुरू किया। नवंबर 2007 में, समिति को पहली रिपोर्ट इस पर काम करने वाली टीम द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

समिति ने 2008 में इस पहली रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और इसे इस नाम से प्रस्तुत किया: "भारत में माल और सेवा कर के लिए एक मॉडल और रोडमैप"

अधिकार प्राप्त समिति ने नवम्बर, 2009 में रिपोर्ट पर प्रथम पेपर चर्चा जारी की।

वर्ष 2010 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने अपने भाषण में अप्रैल, 2011 से GST लागू करने का उल्लेख किया था, जो अंततः नहीं हुआ।





इसके बाद , अगस्त 2013 में स्थायी समिति द्वारा GST पर एक पूरी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत की गई थी। अधिकार प्राप्त समिति ने उसी वर्ष नवंबर में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था।

दिसंबर 2014 में आयोजित सत्र में GST लगाने के लिए संविधान का 122वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था।

अंत में, 3 अगस्त 2016 को, विधेयक को राज्यसभा द्वारा स्वीकार और पारित किया गया था, और यह कहा गया था कि GST 1 जुलाई 2017 से लागू होगा।

और इस प्रकार, वस्तु और सेवा कर विधेयक (GST), जिसे 122 वें संशोधन विधेयक के रूप में जाना जाता है, ने 1 जुलाई 2017 को दिन की रोशनी देखी।

वर्तमान परिदृश्य में, जहां औद्योगिकीकरण समय की मांग है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, GST निस्संदेह देश के आर्थिक विकास का समर्थन करने में एक प्रयास कदम है। यह वित्तीय विकास और सभी के लिए लाभ की प्रतिबद्धता के साथ आता है।

## 1.2 GST के व्यापक लाभ क्या हैं?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पास GST के संबंध में एक दृष्टिकोण था। उन्होंने इसे राष्ट्र के लिए सबसे आवश्यक सुधार के रूप में देखा, जिससे विकास और लाभ हुआ।



# Benefits of Goods & Service Taxes (GST)

## ONE NATION, ONE MARKET



एक नियमित उपभोक्ता या आम आदमी के दृष्टिकोण से, GST का सबसे प्रमुख लाभ वस्तुओं और सेवाओं पर समग्र कर बोझ में लगभग 30% की कमी है, जो हम सभी उत्पादों को खरीदने या किसी भी सेवा का उपयोग करने पर पहले भुगतान कर रहे थे। इस प्रकार, कीमतों में गिरावट आएगी।

प्रवेश कर और राज्य कर को हटा दिया गया है, जो माल की उपलब्धता को आसान बनाते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करता है। यह निर्माताओं और व्यापारियों की आयात और निर्यात शक्ति को भी बढ़ाता है।

इसके अलावा, पहले प्रचलित कई करों के लिए विभिन्न कर खंडों में बहुत अधिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता थी। सभी कारोबारियों को अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कागज के ढेर में खुद को व्यस्त रखना पड़ता था। अब जब GST कर का एक एकीकृत रूप है, तो कागजी कार्रवाई काफी कम हो जाएगी।

जैसा कि भारत एक संघीय गणराज्य है, इसलिए GST केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है।





## 2 भारत में GST की आवश्यकता क्यों थी- GST परिषद का परिचय।

GST से पहले, भारतीय कर प्रणाली कई करों की एक विशाल गैंग थी जो व्यवसाय के विभिन्न चरणों में भुगतान की जाती थी और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग एकत्र की जाती थी। कर की दरें भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं। निर्यात पर छिपे हुए कर, और एक राज्य से दूसरे राज्य में माल आयात करने पर लागू कोई शुल्क भी धोखाधड़ी और जालसाजी के साधन थे। इससे एक उलझा हुआ कर ढांचा खड़ा हो गया, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां हुईं और कर भ्रष्टाचार बढ़ गया।

इसके बजाय, GST ने कर संरचना और परिणामस्वरूप पूरे देश को एकीकृत किया। अब, एकत्र किए गए समेकित कर को केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित किया जाएगा, जो उन पर लगाए गए किसी भी अतिरिक्त करों के बिना, देश भर में सेवाओं और वस्तुओं को प्रदान करने का एक आसान तरीका है।

विभिन्न चरणों में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए अतिरिक्त करों का मतलब लागत में पर्याप्त वृद्धि थी जो अंतिम उपभोक्ता भुगतान कर रहा था। निर्माताओं और व्यापारियों ने अपने कर बोझ को कम करने के लिए लागत में वृद्धि की। इसके अलावा, जटिल कर संरचना अक्षम थी, उलझे हुए जाल में बहुत सारी कमियां बनाई जा रही थीं। यही कारण है कि इन सभी को खत्म करने के लिए एक समेकित और एकीकृत कर ढांचे की आवश्यकता थी। GST कराधान व्यवसाय और व्यापार के प्रत्येक चरण में बहुत अधिक मूल्य जोड़ देगा। इस प्रकार, GST के आने वाले चरणों में आर्थिक विकास देखा जाना निश्चित है। भारत को अब एक एकीकृत और सरलीकृत कर संरचना के साथ एक राष्ट्रीय बाजार के रूप में पहचाना जा सकता है, वह भी उचित कर दर पर।

GST देश की संपूर्ण कराधान प्रणाली में बहुत पारदर्शिता लाने जा रहा है उपभोक्ताओं और व्यापारियों को इस प्रकार पता चल जाएगा कि वे वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खरीद के लिए सरकार को कितना कर दे रहे हैं।

### GST की जरूरत

- एक पूर्ण गंतव्य-आधारित कर प्रणाली
- कराधान का लाभ सिद्धांत - 2 विचार - लाभार्थी भुगतान करता है और आनुपातिक रूप से भुगतान करता है।
- एक एकल कर जो कई अप्रत्यक्ष स्तरों को प्रतिस्थापित करेगा। केंद्र और राज्य दोनों में लगाया जाता है
- पूर्व चरण के करों के सेट ऑफ के रूप में कर का व्यापक प्रभाव उपलब्ध नहीं था।
- आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर कर के बोझ को कम करना पड़ा।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमारे उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए।
- आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और अधिक रोजगार पैदा करना।

आइए अब GST के कुछ प्रमुख लाभों पर एक नज़र डालते हैं:

**सरलीकृत कर संरचना:** जैसा कि पहले बताया गया है। GST एक एकीकृत कर इकाई है जो वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि जैसे विभिन्न व्यवसायों में विभिन्न चरणों में पहले भुगतान किए गए बहुत सारे करों को समाप्त करती है, जो आपने अपनी खरीद के लिए प्राप्त बिलों पर देखा होगा। अब, GST एक एकल कर है जो किसी भी वस्तु या सेवाओं को बेचे या खरीदे जाने पर लगाया जाता है। यह इस कर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। व्यवसायों के लिए, लेखांकन जटिलताओं को कम



किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कम कागजी कार्रवाई होगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। GST से आर्थिक GDP में 2-2.5% की वृद्धि होगी

**कर राजस्व में पर्याप्त वृद्धि:** जब कर प्रणाली सरल हो जाती है, तो लोग करों का भुगतान करने से नहीं भागेंगे और स्वेच्छा से एक कर इकाई, GST के माध्यम से योगदान करने के लिए आगे आएंगे। यह सरकार के लिए एक अच्छा राजस्व जमा पैदा करेगा, जिसका उपयोग राष्ट्र के आगे के विकास और बेहतरी में किया जाएगा।

**वस्तुओं और सेवाओं की कम कीमतें:** जब विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को हटाकर करों को कम किया जाता है, तो निर्माता, व्यापारी और सेवा प्रदाता स्वचालित रूप से अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतों पर अपनी पेशकश उपलब्ध कराएंगे। व्यवसायों और कंपनियों को इससे लाभ होगा, क्योंकि वे में अधिक उत्पादन और अधिक बेचेंगे।

**निर्यात उद्योग को एक मजबूत बढ़ावा:** GST की शुरुआत के साथ, भारत उचित मूल्य निर्धारण के साथ एक प्रतिस्पर्धी बाजार के रूप में उभरेगा। यह अधिक से अधिक विदेशी खिलाड़ियों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इस प्रकार, निर्यात और व्यापार को अच्छी तरह से बढ़ावा देगा।

GST बिक्री/उत्पादन/खरीद पर लगाए जाने वाले विभिन्न करों के व्यापक प्रभाव को दूर करेगा, जिससे सभी करदाताओं और अंतिम उपभोक्ताओं पर से बोझ कम हो जाएगा।

**लेकिन, यह सभी सुधार, निर्णय लेना और कार्यान्वयन आसान नहीं था और भविष्य के पाठ्यक्रम में आसान नहीं होगा। एक संरचना रखने और प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने के लिए, एक निर्णय या निर्णय लेने वाले निकाय की आवश्यकता थी। इस प्रकार, GST परिषद का गठन किया गया।**

## 2.1 GST परिषद और इसके कार्य क्या हैं?

निर्णय लेने वाली प्रमुख संस्था, जो GST, इसकी संरचना के बारे में सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मानदंडों, विनियमों, प्रवर्तन और कार्यान्वयन को GST परिषद कहा जाता है। यह परिषद है जो कर दरों, कर छूट, GST फॉर्म प्राप्त करने की नियत तिथियां और GST दाखिल करने की समय सीमा तय कर रही है, यह परिषद विभिन्न राज्यों के लिए विशेष दरों और प्रावधानों के बारे में निर्णय लेने के लिए भी जिम्मेदार है। GST परिषद की प्रमुख जिम्मेदारी देश भर में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान कर प्रणाली और कर दरों को सुनिश्चित करना है।

## 2.2 GST परिषद की संरचना कैसे की जाती है?

जैसा कि हमने पहले अध्याय - 1 में चर्चा की थी, पूरे देश में GST को लागू करने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक 122 पेश किया गया था। यह विधेयक 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा और 08 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 15 राज्यों द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किए जाने के बाद माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने संविधान (111वां संशोधन) अधिनियम को अपनी सहमति दे दी। इस सहमति के बाद, 16 सितंबर 2016 को, भारत सरकार ने एक परिषद को अस्तित्व में लाने के बारे में अधिसूचना जारी की, जो GST से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

तब से, GST परिषद को GST से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए संवैधानिक निकाय को अस्तित्व में लाने के लिए अधिसूचित किया गया है। संशोधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 (1) में कहा गया है कि GST परिषद का गठन अनुच्छेद 279 ए के लागू



होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि GST परिषद केंद्र और राज्यों के लिए एक संयुक्त मंच होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितम्बर, 2016 को GST परिषद की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279ए के अनुसार GST परिषद का गठन।
- नई दिल्ली में अपने कार्यालय के साथ GST परिषद सचिवालय का निर्माण।
- सचिव (राजस्व) की GST परिषद के पदेन सचिव के रूप में नियुक्ति।
- GST परिषद की सभी कार्यवाहियों में आमंत्रित (गैर-मतदान) अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) एक स्थायी के रूप में
- GST परिषद सचिवालय में GST परिषद के अतिरिक्त सचिव का एक पद (भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर), और GST परिषद सचिवालय में आयुक्त के चार पद (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर पर) सृजित करना।
- GST परिषद सचिव के अतिरिक्त सचिव के लिए एक पद सृजित करने के लिए)
- GST परिषद सचिवालय में आयुक्त के चार पद सृजित करना। (यह संयुक्त स्तर पर है।)
- मंत्रिमंडल ने आवर्ती और गैर-केंद्र सरकार को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन प्रदान करने का भी निर्णय लिया। GST परिषद सचिवालय का आवर्ती व्यय, जिसकी पूरी लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।
- GST परिषद सचिवालय केंद्र और सरकार दोनों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों द्वारा संचालित होता है।
- GST परिषद सचिवालय में केंद्र और राज्य दोनों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारी होंगे
- कैबिनेट GST परिषद सचिवालय के खर्चों (आवर्ती और गैर-आवर्ती) की बैठकों के लिए धन भी प्रदान करता है। यह खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

### इस प्रकार, इसमें निम्नलिखित प्रमुख सदस्य शामिल थे।

- केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली: अध्यक्ष के रूप में
- केंद्रीय राज्य मंत्री। सदस्यों के रूप में और वित्त के राजस्व के प्रभारी के रूप में
- वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य द्वारा सदस्य के रूप में नामित मंत्री
- GST परिषद की अन्य सिफारिशें





इसके अलावा, अनुच्छेद 279 ए (4) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि GST परिषद GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सभी सिफारिशें करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगी; उदाहरण के लिए, क्या उस राज्य में वस्तुओं और सेवाओं को GST के अधीन या छूट दी जाएगी।

**GST परिषद निम्नलिखित से संबंधित कर कानूनों को भी बनाती और लागू करती है:**

- आपूर्ति का स्थान
- थ्रेशोल्ड लिमिट
- वस्तुओं और सेवाओं पर GST दर
- प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष दर
- कुछ राज्यों के लिए विशेष GST दर

चूंकि यह अस्तित्व में आया था, इसलिए GST परिषद की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं और बैठकों में निम्नलिखित से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय किए और कार्यान्वित किए जाते हैं। यह GST परिषद की बैठकों में क्या हुआ, इसकी एक खिड़की है:

- GST परिषद में आचरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए नियम बनाए गए थे।
- विभिन्न GST के कार्यान्वयन के लिए समय सारिणी बनाई गई थी।
- विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए GST से छूट की सीमा 20 लाख रुपये तय की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 279ए के अनुसार विशेष श्रेणी के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।
- कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए सीमा (हम बाद के अध्यायों में इस पर चर्चा करेंगे) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में 75 लाख रुपये तय की गई थी, जहां कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने की सीमा 50 लाख रुपये तय की गई है।
- GST परिषद ने यह भी सिफारिश की कि निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माता कंपोजिशन लेवी के लिए पात्र नहीं होंगे:
  - आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे में कोको हो या न हो
  - मसाला
  - तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प

रेस्तरां सेवाओं को छोड़कर इन सेवा प्रदाताओं को कंपोजिशन स्कीम से बाहर रखा गया है।

- GST के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 साल तक क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया, राज्य के राजस्व के लिए आधार वर्ष 2015-16 रखा गया है और इस पर 14% की निश्चित वृद्धि दर लागू होती है।
- पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न, रिफंड और चालान, मूल्यांकन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंपोजिशन और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित विभिन्न GST नियमों के मसौदे को मंजूरी दी गई।
- यह निर्णय लिया गया कि किसी भी मौजूदा कर प्रोत्साहन योजना के तहत अप्रत्यक्ष कर के भुगतान से छूट प्राप्त सभी इकाइयां GST शासन में कर का भुगतान करेंगी और किसी भी प्रोत्साहन योजना को जारी रखने का निर्णय केवल संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के पास होगा। यदि राज्य या केंद्र सरकार किसी मौजूदा छूट/प्रोत्साहन योजना को जारी रखने का निर्णय लेती है; यह एक प्रतिपूर्ति तंत्र के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।



- 5%, 12%, 18%, और 28% के चार स्लैब कर दर संरचना को अपनाने के लिए निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, छूट वाले सामानों की एक श्रेणी तय की गई थी और राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए 28% की दर के अलावा लकजरी कारों, वातित पेय, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों जैसे कुछ सामानों पर उपकर लगाने का निर्णय लिया गया था। (इन सभी दर स्लैब और छूटों पर आगे के अध्यायों में चर्चा की जाएगी)।
- 18 और 19 मई 2017 को श्रीनगर में आयोजित 14<sup>वीं</sup> GST परिषद की बैठक में 1211 वस्तुओं (खाद्यान्न और आम उपयोग के उत्पाद जैसे कि तेल, साबुन और टूथपेस्ट) पर GST दरों को मंजूरी दी गई थी।
- 3 जून 2017 को नई दिल्ली में आयोजित 15 वीं GST परिषद की बैठक में, शेष वस्तुओं पर कर दरों को मंजूरी दी गई थी।
- 28 राज्यों और विधानसभाओं वाले 2 केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी) ने पहले ही अपनी राज्य विधानसभाओं में अपने संबंधित राज्य GST विधेयक पारित कर दिए हैं।
- राज्यों और केंद्र के बीच करदाताओं के क्रॉस सशक्तिकरण और प्रशासनिक विभाजन के कुछ मुद्दे थे, जिन्हें परिषद द्वारा हल किया गया था और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रखा गया था।

### थोड़ा अतिरिक्त:

**GST बिल और GST काउंसिल के अलावा एक और बड़ा रिफॉर्म हुआ। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक, एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश (विधायिका के बिना) वस्तु और सेवा कर विधेयक और वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 29-03-2017 को लोकसभा द्वारा और 06-04-2017 को राज्यसभा द्वारा पारित किए गए थे।**



## 3 GST के तहत अब किन सभी प्रकार के करों और शुल्कों को शामिल किया गया है?

भारत एक गणतंत्र है और कराधान न केवल केंद्र का विषय है, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य का भी विषय है, भले ही केंद्र हर राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसा कि ऐसा करने की आवश्यकता होती है, आपात स्थिति के समय और शासन के पूर्व-परिभाषित मामलों के तहत, वास्तविकता यह है कि प्रत्येक राज्य विभिन्न भोजन और अप्रत्यक्ष करों को एकत्र करके अपने दम पर प्रशासन चलाने के लिए बाध्य है। सरकार चलाने, वेतन का भुगतान करने, प्रशासनिक लागतों को पूरा करने, बुनियादी ढांचे के विकास को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार और इसी तरह की सरकार से अपेक्षित बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार द्वारा ली जानी चाहिए। यही कारण है कि राज्य सरकारें कराधान नीतियों को इतना महंगा मानती हैं।

कुछ ऐसे उत्पाद और सेवाएं हैं जिनकी दूसरों की तुलना में अधिक खपत होती है और उनके बिक्री मूल्य में शामिल कोई भी कर घटक यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के खजाने को स्थिर आय का आश्वासन दिया जाए, उन करों में किसी भी कमी का मतलब है कि राजकोष को पर्याप्त वित्तीय नुकसान होता है जो सरकार के बही-खातों और उसके दिन-प्रतिदिन के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इससे न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि बैलेंस शीट में कोई भी लाल निशान राज्य सरकार की प्रमुख वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की क्षमता को भी खतरे में डाल सकता है, न कि सरकार की विश्वसनीयता का उल्लेख करने के लिए।

एक राज्य सरकार को प्रतिकूल परिस्थितियों में केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए, अतिरिक्त व्यय के साथ राजस्व में कोई भी नुकसान क्रेडिट लाइनों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संघों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय रियायतों पर चूक के लिए एक आसान नुस्खा है। यह देश की वित्तीय रेटिंग को भी प्रभावित करता है जो अंततः अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। **Adverse ratings** का मतलब है कि ऋण महंगा हो जाता है, व्यवसाय का संचालन करना मुश्किल हो जाता है और संचालन चलाने की लागत बढ़ जाती है जिससे वित्तीय उथल-पुथल होती है।

संक्षेप में, सरकार का वित्तीय स्वास्थ्य देश के वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है, और इससे जुड़े सभी लोग वित्तीय प्रतिकूलताओं के कारण होने वाली किसी भी मंदी या नकारात्मकता से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि GST को तैयार करने और आखिरकार लागू करने में इतना समय लगा। प्रत्येक हितधारक को लंबे समय में कर के लाभ के बारे में आश्वस्त होना था, व्यक्तिगत हितधारकों के वित्तीय हितों का ध्यान रखा जाना था ताकि प्रशासन के संचालन में कोई ठहराव न हो और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पद्धति पर काम किया जाना चाहिए कि किसी भी चीज की अनदेखी न की जाए, चाहे राजस्व के नुकसान के संदर्भ में या राजस्व के ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने के संदर्भ में।

यह देखते हुए कि भारत एक विशाल देश है, जिसमें कई राज्यों में केंद्रीय करों के साथ संयुक्त रूप से कई कर हैं, अंतिम दरों को तय करने से पहले एक गहन जमीनी काम किया गया था। इस प्रक्रिया में, करों की एकरूपता सुनिश्चित करने और दोहरेपन को दूर करने के लिए बहुत सारे केंद्रीय और राज्य करों को GST के साथ जोड़ा गया, हटा दिया गया या जोड़ा गया, जैसा कि पहले होता था।

हालांकि, ध्यान दें कि तदर्थ आधार पर कुछ भी नहीं किया गया था। एक रणनीति बनाई गई थी और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया था कि क्या हासिल किया जाना था।

आइए उन कारकों पर एक नज़र डालें जिन्हें लगाए जा रहे करों की बहुलता को दूर करने और एमको GST के तहत शामिल करने पर विचार किया गया था:



- A. पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार यह था कि GST के साथ जुड़े कर मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति में रहे हैं। इस तरह के कर या तो आपूर्ति वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाते थे और उसके बाद ही उन्हें GST के तहत विलय करने पर विचार किया जाता था।
- B. लेन-देन श्रृंखला नामक कुछ है जो वस्तुओं के आयात / निर्माण / उत्पादन या एक छोर पर सेवाओं के प्रावधान और दूसरे छोर पर ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की खपत से शुरू होता है। अब करों और शुल्कों को इस तरह की लेनदेन श्रृंखला का हिस्सा होना था ताकि उन्हें GST के साथ जोड़ा जा सके।
- C. GST लाने का उद्देश्य सुचारू और आसान कराधान सुनिश्चित करना है। हालांकि, GST के साथ कुछ करों और शुल्कों को जोड़ने से कर क्रेडिट के मुक्त प्रवाह को प्रभावित नहीं करना चाहिए और यह पूरी प्रक्रिया को शुरू करते समय महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक था।
- D. GST के साथ करों और शुल्कों को शामिल करते समय एक और कारक को ध्यान में रखा गया था कि जो विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित नहीं थे, उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाना था।
- E. चूंकि कराधान राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार को समान रूप से प्रभावित करता है, इसलिए एक कारक जो ईमानदारी से ध्यान में रखा गया था, वह यह था कि राजस्व सृजन और कमाई दोनों हितधारकों के लिए उचित थी, GST के साथ करों और करों को शामिल करने से एक को नुकसान नहीं होना चाहिए और दूसरे को लाभ और इसके विपरीत!

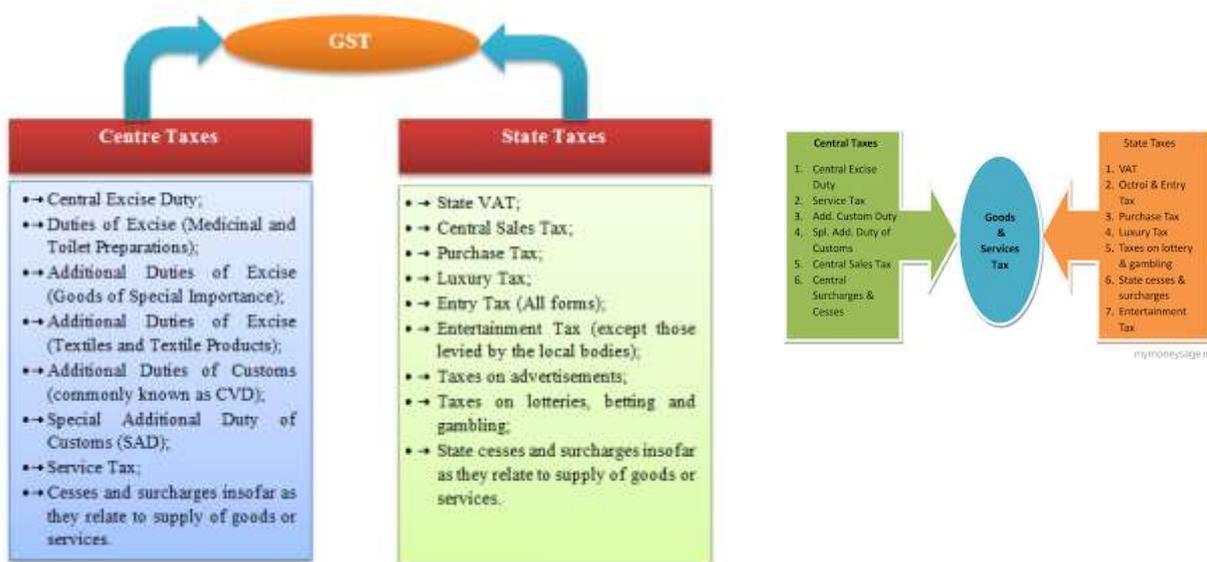
पिछली कराधान प्रणाली में, जो अधिक जटिल थी, करों और शुल्कों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रूपों में व्यवसाय के विभिन्न चरणों में एकत्र किया गया था। व्यवसायियों को अपने कर खातों को बनाए रखने और कानूनी प्रणालियों का पालन करने के लिए कई रिकॉर्ड बुक बनाए रखने की आवश्यकता थी। कागजी कार्रवाई दोनों छोरों पर भारी थी: व्यापार के अंत के साथ-साथ सरकार का अंत और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों के साथ पर्याप्त जनशक्ति को निपटान में रखने की आवश्यकता थी।

लेकिन अब, GST के तहत कई करों और शुल्कों को एक साथ जोड़ा गया है, जिससे रिकॉर्ड बनाए रखना, दक्षता में सुधार करना, जटिलताओं को कम करना आसान हो जाता है, जिससे सभी को व्यवसाय करने में आसानी होगी!

इस विषय की बेहतर समझ रखने के लिए, हम राज्य और केंद्रीय करों के तहत उन्हें अलग करने के बाद GST के साथ जुड़े करों को प्रस्तुत कर रहे हैं।



निम्नलिखित शुल्क और कर हैं जो पहले केंद्रीय स्तर पर भुगतान किए जाते थे लेकिन अब GST के तहत विलय कर दिए गए हैं:



गए हैं:

**केंद्रीय उत्पाद शुल्क - Central Excise Duty (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सहित):** देश में निर्मित प्रत्येक उत्पाद को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ लगाया गया था। इस तरह के शुल्क को एकत्र करने की जिम्मेदारी केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड पर थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ कर की दर सभी निर्मित वस्तुओं पर 12.5% थी, जिससे चांदी के गहने जैसे कुछ उत्पादों को छूट मिली।

**सेवा कर- Service Tax:** सेवा कर एक कर है जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लगाया जाता है और वास्तव में ग्राहकों द्वारा किया जाता था और चालान का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। यह एक अप्रत्यक्ष कर था, जिसमें सेवा प्रदाता ने सेवा प्राप्तकर्ता से कर एकत्र किया और सरकार को भुगतान किया और सरकार के लिए पर्याप्त कमाई की। हालांकि, इससे ग्राहकों के बीच भ्रम पैदा हो गया कि सेवा शुल्क आदि से अलग कैसे था और इसके आसपास बहस हुई थी, लेकिन अब यह सब ध्यान रखा गया है, रिकॉर्ड के लिए, सेवा कर की दर प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य का 15% थी, शिक्षा उपकर और माध्यमिक शिक्षा उपकर 2% की दर से और स्वच्छ भारत उपकर 0.50% की दर से जोड़ा गया था।

**अतिरिक्त सीमा शुल्क- Additional Customs Duty:** देश में आयात किए जाने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए सरकार ने उस पर शुल्क लगाया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर, इसे आमतौर पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता था। इसकी गणना लैंडिंग शुल्क और मूल सीमा शुल्क (डंपिंग रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क आदि को छोड़कर) सहित माल के आधार मूल्य पर की गई थी। और अब इसे GST के साथ जोड़ा गया है।

**विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क- Special Additional Customs Duty:** यह शुल्क आयातित वस्तुओं पर 4% पर देय था, जिसने वैट बिक्री कर को बदल दिया

**केंद्रीय अधिभार और उपकर- Central Surcharges and Cess:** कर पर एक शुल्क को अधिभार के रूप में जाना जाता है और यह मूल रूप से व्यक्तिगत आयकर (विशेष रूप से उच्च आय स्लैब पर) पर लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त शुल्क था और



कॉर्पोरेट आयकर उपकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था और विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया था। अधिभार और उपकर दोनों को GST के साथ जोड़ा जाता है, जहां भी वे वस्तुओं या सेवाओं पर करों की प्रकृति में थे। इसमें रबर, चाय, कॉफी, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क आदि पर उपकर शामिल था।

**केंद्रीय बिक्री कर- Central Sales Tax:** इसे पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है।

**निम्नलिखित शुल्क और कर हैं जो पहले राज्य स्तर पर भुगतान किए जाते थे लेकिन अब GST के तहत विलय कर दिए गए हैं:**

**मूल्य वर्धित कर- Value Added Tax (VAT):** वैट राज्य या घरेलू स्तर पर प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर एक अप्रत्यक्ष कर था। यह वितरण और उत्पादन की श्रृंखला में प्रत्येक चरण में लगाया गया था, कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर उत्पाद के अंतिम मूल्यांकन तक और यह वितरण चैनल में अंतिम उपयोगकर्ताओं (सीमा शुल्क) द्वारा वहन किया गया था।

**केंद्रीय बिक्री कर- Central Sales Tax:** सीएसटी, बिक्री पर लगाया जाता था, जो अंतर-राज्य व्यापार से प्रभावित होता है। सीएसटी फिर से उपभोक्ताओं पर एक अप्रत्यक्ष कर था। जैसा कि यह केंद्रीय रूप से लगाया गया था, इसलिए इसे संबंधित राज्य द्वारा प्रशासित किया गया था जहां बिक्री उत्पन्न हुई थी।

**ऑक्ट्रॉय और प्रवेश कर- Octroi & Entry Tax:** ऑक्ट्रॉय स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाया गया कर था; उदाहरण के लिए, नगर पालिका और प्रवेश कर राज्य द्वारा लिया गया था।

**खरीद कर- Purchase Tax:** खरीद कर एक कर था जो राज्य सरकार द्वारा माल की खरीद पर लगाया गया था और उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला पर लागू किया गया था।

**लक्जरी टैक्स- Luxury Tax:** लक्जरी टैक्स उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो या तो महंगे या वैकल्पिक थे।

**लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ पर कर:** कर जो लॉटरी जीतने, जुआ और सट्टेबाजी पर लगाया गया था और इसकी गणना स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में की गई थी। इसे अंतिम आय से काट लिया गया था।

**मनोरंजन कर:** मनोरंजन कर सरकार द्वारा मनोरंजन से संबंधित चीजों जैसे फिल्म टिकट, वाणिज्यिक शो आदि पर लगाया जाने वाला कर था।

उपर्युक्त कर और लेवी अब प्रभावी नहीं हैं और पूरी तरह से GST के साथ जुड़ गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार को उनका वित्तीय लाभ भी खत्म हो गया है। इसके बजाय, उचित जांच और विस्तृत गणना के बाद दरों को GST दरों के साथ मूल रूप से विलय कर दिया गया है।



## 4 GST वास्तव में कैसे काम करता है! GST के प्रकार!

भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 25 साल पहले बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार हुए थे जब बाजारों को उनकी क्षमता पर खरा उतरने के लिए खोल दिया गया था और केवल बाजार की ताकतों को देश के आर्थिक विकास को चलाने की अनुमति दी गई थी। तथापि, प्रभावी कराधान नीतियां वही थीं जो उदारीकरण से पूर्व मौजूद थीं। यह एक विसंगति थी क्योंकि असमान आर्थिक विकास, "कर पर कर" मुद्दों के कारण विभिन्न खामियां थीं, जिससे देश की आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों दोनों की अपनी बात थी कि किस तरह के उत्पादों पर किस तरह के कर लगाए जाएंगे और इसने भारत को संचालित करने के लिए एक बेहद कठिन बाजार बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप देश के आम आदमी को देश के विभिन्न हिस्सों में एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग कीमतें चुकानी पड़ीं। इसका न केवल औसत नागरिकों पर असर पड़ा, बल्कि उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी असर पड़ा, जो समान अवसर की तलाश में थे और अनुचित करों को देखे बिना अपने निवेश पर लगातार रिटर्न का आश्वासन दे रहे थे।

GST को पूरी कराधान नीति को एकीकृत करने और करों, शुल्कों और उपकरों के मामले में पूरे देशों को एक बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है जो देश के बाजार को एकजुट करेगा और कोई भी और हर कोई विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद कर बाधाओं को कम करके देश के भीतर बेचने, खरीदने, आयात करने और निर्यात करने के लिए स्वतंत्र होगा। और फिर भी, इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में जीडीपी में 1-1.5% की वृद्धि होगी!

सरल शब्दों में, GST आम आदमी के लिए दो तरह से फायदेमंद होगा: पहला, करों को केवल उपभोग के बिंदु पर एकत्र किया जाएगा, अर्थात्, जब खरीदार अच्छा खरीदता है या सेवा का उपभोग करता है। दूसरे, चूंकि राज्यों के बीच कर बाधाएं कम हो जाएंगी, इसलिए अंतिम उपयोगकर्ता उत्पादों / सेवाओं पर कर का भुगतान नहीं करेगा। यह, दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है कि कर केवल उत्पाद चक्र के अंतिम चरण में लगाया जाता है, इससे पहले कि यह खरीदार के साथ उतरता है!

भारत में, GST एक दोहरी प्रणाली में लागू किया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण, बिक्री और खपत पर लगाया जाता है। कर दो संस्थाओं द्वारा एकत्र और लगाया जाएगा: केंद्र और राज्य। केंद्र स्तर पर लगाया और एकत्र किया गया कर CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) है। राज्य स्तर पर लगाया और एकत्र किया गया कर SGST (राज्य वस्तु और सेवा कर) है।

GST एक मूल्य वर्धित कर है जो पहले की प्रणाली में बिक्री और खरीद के विभिन्न चरणों में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, प्रत्येक विक्रेता खरीदार से कर वसूलता था, जिसका अर्थ है, अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक वस्तु और सेवा पर कर का बोझ डाला गया था।

लेकिन अब व्यवस्था बदल जाएगी। अब वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बिंदु GST का भुगतान करेंगे शेष इसे वापस दावा करेंगे।



आगे बढ़ने से पहले, यहां कुछ व्यापक संकेत दिए गए हैं कि वास्तव में GST कैसे काम करेगा:

1. यह एक बहु-चरण संग्रह तंत्र का पालन करेगा जहां उत्पादन के हर चरण में कर एकत्र किया जाएगा और पिछले चरण में भुगतान किए गए कर (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का क्रेडिट लेनदेन के अगले चरण में सेट-ऑफ के रूप में उपलब्ध होगा।
2. इसके परिणामस्वरूप कर-पर-कर व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और अंतिम उपयोगकर्ता केवल उत्पादन / सेवा उत्पादन के अंतिम चरण में लागू कर का भुगतान करेगा, जिससे लंबी अवधि में कीमतों और कर घटक में कमी आएगी।
3. GST दरों को 4 बुनियादी दरों के तहत वर्गीकृत किया गया है: 5%, 12%, 18% और 28% जिससे अन्य सभी करों और शुल्कों को समाप्त कर दिया गया है जो अब तक प्रभावी थे। यह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को समझना आसान और आसानी से समझने और लागू करने के लिए आसान बनाता है।
4. 20 लाख रुपये और उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले सभी व्यावसायिक उद्यम GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे और कुछ राज्यों को छोड़कर मानदंडों का पालन करेंगे, जहां 10 लाख रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों के लिए सीमा सीमा निर्धारित की गई है।

एक व्यावहारिक उदाहरण की मदद से पूरे तंत्र को समझना हमेशा बेहतर होता है।

यहां समझने के लिए एक आसान उदाहरण दिया गया है, GST वास्तव में कैसे कार्य करेगा:

हम यहां मिठाई बनाने और बेचने के बारे में बात कर रहे हैं।

माना जाता है, मिठाई बनाने के वितरण चैनल में, 3 लोग हैं: निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता।

### स्टेज-1

मान लीजिए, मिठाई का निर्माता दूध, चीनी, सूखे मेवे और अन्य आवश्यक चीजों जैसे कच्चे माल खरीदता है जो 250 ग्राम मिठाई तैयार करने के लिए आवश्यक है, और इसकी लागत लगभग 200 रुपये है, जिसमें 20 रुपये का 10% कर भी शामिल है। अब, मिठाई तैयार है और निर्माता ने सामग्री में अपना मूल्य जोड़ा, 60 रुपये कहते हैं। फिर मिठाई के डिब्बे की कुल लागत 260 रुपये हो जाती है और इसके लिए कर 26 रुपये (10% कर दर) होगा। लेकिन, GST कराधान के तहत, इस स्तर पर निर्माता केवल 6 रुपये का भुगतान करेगा (जैसा कि उसने शुरू में 20 रुपये का भुगतान किया है, इसलिए 26-रुपये 20 = 6 रुपये)।



## चरण - 2

इसके बाद, हम दूसरे चरण में जाते हैं, जहां थोक व्यापारी निर्माता से 260 रुपये में मिठाई खरीदता है और लाभ कमाने के लिए, वह 40 रुपये जोड़ता है। अब मिठाई के उस डिब्बे की कुल लागत 300 रुपये है। कर की दर ऊपर उल्लिखित (10%) के समान होगी, कर राशि 30 रुपये होगी। यहां, पहले चरण में 26 रुपये की कर राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, इसलिए उसे फिर से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। GST के तहत, थोक व्यापारी के कर की गणना इस प्रकार की जाएगी:  $INR\ 30 - INR\ 26 = INR\ 4$

## स्टेज-3

अब माल अंतिम चरण में पहुंच जाता है, यानी खुदरा विक्रेता, जिसमें खुदरा विक्रेता को 300 रुपये की लागत पर थोक व्यापारी से मिठाई का डिब्बा मिलता है। चूंकि वह लाभ भी अर्जित करना चाहता है, इसलिए वह 20 रुपये का मार्जिन जोड़ता है। मिठाई के डिब्बे की कुल कीमत 320 रुपये है और 10% कर की दर से शुल्क लिया जाता है, इसलिए कर 32 रुपये होगा। दूसरे चरण में, 30 रुपये पहले से ही कर के रूप में भुगतान किया जाता है, इसलिए शेष कर प्रभाव  $INR\ 32 - INR\ 30 = INR\ 2$  होगा।

अब, अगर खुदरा विक्रेता को यह लाभ दिखाई देता है कि वह पहले की तुलना में काफी कम कर का भुगतान कर रहा है, तो वह स्वचालित रूप से अपनी मिठाई की कीमतों को कम कर देगा, और अंतिम उपयोगकर्ता को कम लागत पर माल के साथ लाभ होगा।

संक्षेप में, वितरण श्रृंखला के लिए GST के लिए कुल मिलाकर: निर्माता - थोक व्यापारी - खुदरा विक्रेता 20 रुपये + 6 रुपये + 4 रुपये + 2 = 32 रुपये है। हर चरण में 10% की कटौती के बजाय, जिसके परिणामस्वरूप माल की उच्च कीमत होती है।

अब GST को एक राष्ट्र एक कर के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और यह सही भी है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास अभी भी राजस्व अर्जित करने और साझा करने के लिए एक कार्य तंत्र है। GST को निष्पक्ष बनाने के लिए इसे समान रूप से अलग किया गया है।

आइए अब हम विस्तार से GST के प्रकारों का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

अब तक 4 प्रकार के GST लागू किए गए हैं:

- CGST - केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
- SGST- राज्य वस्तु एवं सेवा कर
- IGST - एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
- इसके अतिरिक्त, UTGST - भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर।



## CGST

- CGST stands for Central GST
- This is applicable on supplies within the State
- Tax collected will be shared to Centre

## SGST

- SGST stands for State GST
- This is applicable on supplies within the State
- Tax collected will be shared to State

## IGST

- IGST stands for Integrated GST
- This is applicable on interstate and import transactions
- Tax collected is shared between Centre and State

### 4.1 CGST - केंद्रीय वस्तु और सेवा कर

CGST केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 के तहत आता है।

आसान समझ के लिए, जब CGST पेश किया जा रहा है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर CST, सेवा कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, चिकित्सा और प्रसाधन सामग्री तैयारी अधिनियम के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क, CVD (अतिरिक्त सीमा शुल्क - काउंटरवेलिंग इयूटी), SAD (सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क) अधिभार और उपकर के वर्तमान केंद्रीय करों को समाहित किया जाता है। यह कर ढांचे में एकरूपता लाने और करों के दोहराव से बचने के लिए है, जैसा कि पिछली कर व्यवस्था के साथ पहले था।

CGST मानक वस्तुओं और सेवाओं की वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर लगाया जाता है जिसे समय-समय पर उभरती स्थिति और आर्थिक नीतियों और जरूरतों के आधार पर एक अलग निकाय द्वारा संशोधित किया जा सकता है। CGST के तहत एकत्रित राजस्व केंद्र सरकार के लिए अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए है। हालांकि, CGST पर इनपुट टैक्स क्रेडिट राज्यों को दिया जाता है और इस तरह के इनपुट टैक्स का उपयोग केवल केंद्रीय GST के भुगतान के खिलाफ किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें एक ही पृष्ठ पर हैं, और दोनों समान रूप से राजस्व को विभाजित करते हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार के नुकसान में नहीं है।

उपभोक्ताओं को वास्तविक कर के घटक के बारे में पता होने और समझने के लिए प्रत्येक चालान पर इस कर घटक का उल्लेख करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

उदाहरण के लिए यदि कोई उत्पाद एक ही राज्य के भीतर निर्मित और बेचा जाता है, तो उपभोक्ता उस पर 2 टेक का भुगतान करेगा। CGST जो केंद्र सरकार के पास जाएगा और SGST जो राज्य के पास जाएगा। हालांकि यदि उत्पाद एक राज्य में निर्मित किया गया था और दूसरे में बेचा गया था, तो विनिर्माण राज्य उस पर कोई कर नहीं लगाएगा। यदि ऐसा होता है, तो इसे केंद्र सरकार के माध्यम से उपभोक्ता राज्य को हस्तांतरित किया जाएगा।

### 4.2 SGST - राज्य माल और सेवा कर

SGST राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 के तहत आता है।



आसान समझ के लिए, जब SGST पेश किया जा रहा है, तो राज्य बिक्री कर वैट, लकजरी कर, मनोरंजन कर (जब तक कि यह स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लगाया जाता है), लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ पर कर, ऑक्ट्रॉय के बदले में प्रवेश कर, राज्य उपकर और अधिभार आदि के वर्तमान राज्य करों को शामिल किया जाता है, जहां तक वे माल और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं।

जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार के उन सभी कई करों, शुल्कों और उपकरों को एक एकल SGST द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो एक कुशल तरीके से लागू करना, फाइल करना, ट्रैक रखना और लागू करना बेहद आसान होगा, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक वित्तीय लेनदेन पारदर्शी तरीके से हो। निर्माता से अंत तक - उपभोक्ता को पता होगा कि पैसा कहां जा रहा है।

SGST के अंतर्गत एकत्रित राजस्व राज्य सरकार के लिए है।

प्रत्येक बिल उपभोक्ताओं की जागरूकता और समझ के लिए इस कर घटक का अलग से उल्लेख करता है।

### 4.3 IGST - एकीकृत माल और सेवा कर

IGST एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 के तहत आता है।

IGST तब वसूला जाता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही होती है। उदाहरण के लिए। यदि माल को तमिलनाडु से केरल ले जाया जाता है, तो ऐसे सामानों पर IGST लगाया जाता है। IGST से प्राप्त राजस्व को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार साझा किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्तिगत राज्यों को करों और राजस्व का निपटान करने के लिए विभिन्न राज्यों से निपटना न पड़े; इसके बजाय, वे केवल करों के अपने सही हिस्से के लिए केंद्र सरकार के साथ सौदा करते हैं।

IGST आयात पर भी लागू होता है और एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निर्यात शून्य-रेटेड होगा। GST कानून के अनुसार:

GST व्यवस्था के तहत, वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर केंद्र द्वारा एक एकीकृत GST (IGST) लगाया जाएगा और एकत्र किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 269A के तहत, अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर GST भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा और ऐसे कर को संघ और राज्यों के बीच उस तरीके से विभाजित किया जाएगा जो वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर संसद द्वारा कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, गुजरात में एक निर्माता महाराष्ट्र में अंतिम खरीदार को एक उत्पाद बेचता है। यह मानते हुए कि अंतिम उत्पाद की लागत 1 लाख रुपये है और विशेष वस्तु पर 18% की कर दर है, 18% का IGST लगाया जाएगा और कर घटक 18,000 रुपये होगा, अब यह IGST केंद्र के पास जाएगा, जो इस राजस्व को संबंधित राज्य के साथ साझा करेगा।

### 4.4 UTGST - भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर

हम CGST, IGST और SGST के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में, दोहरी GST लागू है। वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति (राज्य के भीतर) के खिलाफ CGST और SGST और अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिए IGST।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), लक्षद्वीप, पुडुचेरी आदि जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के तहत GST होता है।



UTGST अधिनियम के नाम पर भारत में GST लगाने और प्रशासित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के लिए एक अलग अधिनियम लागू किया जा रहा है। UTGST अधिनियम के तहत, केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के खिलाफ देय GST दरों का विवरण समझाया गया है।

UTGST विधेयक को UTGST अधिनियम के रूप में लागू करने के लिए संबंधित राज्यों की सरकारों में प्रस्तुत किया जाता है।

ये सभी विभिन्न प्रकार के GST यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि व्यक्तिगत राज्य सरकारों को कोई वित्तीय नुकसान पहुंचाए बिना कर संग्रह और राजस्व के बंटवारे में एकरूपता हो। इस तंत्र को किसी भी कदाचार या करों के दोहराव से बचने के लिए इस पर नजर रखने के अलावा पूरी प्रक्रिया को समझने और लागू करने के लिए बेहद सरल रखने के लिए परिभाषित किया गया है।

पहले की कर व्यवस्था में लगाए जा रहे बहुत सारे कर अदृश्य थे और अंत - उपभोक्ता आसानी से समझ नहीं पाते थे कि किसी उत्पाद / सेवा की अंतिम कीमत की गणना कैसे की गई थी। GST उस दिशा में एक कदम है जहां हर किसी को पता चल जाएगा कि किसी विशेष उत्पाद की लागत कैसे पहुंची और उस उत्पाद / सेवा को अपने दरवाजे पर लाने के लिए कितना अप्रत्यक्ष कर का भुगतान किया जा रहा है।

प्रारंभ में यह सब अवशोषित करने और समझने के लिए बहुत अधिक लग सकता है, लेकिन लंबे समय में GST वह है जो भारत जैसे बड़े और विविध राष्ट्र को अपनी आर्थिक क्षमता का एहसास करने की आवश्यकता है। यह न केवल भारतीय नागरिकों के लिए, बल्कि विदेशी कंपनियों के लिए भी सरल है जो अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए देश में दुकान स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। यह अंततः हम सभी को लाभान्वित करेगा।



## 5 GST संशोधन विधेयक क्या है?

विधेयक संसद में चर्चा के लिए पेश प्रस्तावित कानून का मसौदा होता है। एक बार जब यह संसद द्वारा पारित हो जाता है, तो यह एक अधिनियम बन जाता है। इसलिए, GST विधेयक अब GST अधिनियम बन गया है।

उक्त अधिनियम में कोई भी संशोधन एक संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है। इसी तरह GST अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को GST संशोधन विधेयक में दर्ज किया गया था।



### ● GST संशोधन विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या GST अधिनियम में कोई बदलाव किया गया था?

मॉडल GST कानून का मसौदा पहली बार जून 2016 में तैयार किया गया था और बाद में नवंबर 2016 में संशोधित किया गया था। लोकसभा ने कुछ संशोधनों के साथ 4 विधेयक पारित किए। GST विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों की एक सूची यहां दी गई है:

### ● जम्मू और कश्मीर राज्य में GST कानून की प्रयोज्यता

जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने पुष्टि की कि जम्मू-कश्मीर GST लागू करेगा। हालांकि, चूंकि जम्मू-कश्मीर का एक अलग संविधान है और विधायिका के बारे में विशेष प्रावधान हैं, इसलिए CGST और IGST अलग से पारित किए जाएंगे। SGST को अन्य राज्यों की तरह अलग से पारित किया जाएगा।

### ● कर्मचारी को नियोक्ता के उपहार अब GST के तहत कर नहीं लगाया जाएगा

इससे पहले संबंधित व्यक्तियों (व्यवसाय के दौरान की गई) के बीच वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को 'आपूर्ति' के रूप में माना जाता था, भले ही कोई विचार न हो। नियोक्ता और कर्मचारी को संबंधित व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया था। इसलिए, यह खड़ा था कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को माल या सेवाओं की कोई भी आपूर्ति (भले ही मुफ्त में) GST के दायरे में आती।

अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन में प्रावधान है कि 100 रुपये तक के उपहारों पर GST लागू नहीं होगा। एक नियोक्ता द्वारा किसी विशेष कर्मचारी को 50,000 रुपये। हालांकि, 50,000 रुपये से अधिक के उपहारों पर GST लगेगा।

### ● भूमि/भवन की बिक्री पर GST लागू नहीं



इससे पहले, 'माल' शब्द में कार्रवाई योग्य दावों सहित सभी चल संपत्ति शामिल थी। केवल धन और प्रतिभूतियों को बाहर रखा गया था। "सेवाओं" में "माल के अलावा कुछ भी" की अस्पष्ट परिभाषा थी।

इस प्रकार, एक आशंका थी कि सरकार स्टांप ड्यूटी लगाने के अलावा अचल संपत्ति (भूमि /भवन) की आपूर्ति पर GST लगा सकती है।

अब, सरकार ने अनुसूची III में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि भूमि और / या भवन की बिक्री को न तो वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति, यानी, माल और सेवा कर (GST), इस पर लागू नहीं होगा।

इसलिए वर्तमान में (आज तक इस पुस्तक को संकलित किया जा रहा है) यह वही है।

- जमीन और/या भवन को किराए पर लेने, पट्टे पर देने पर GST लागू होगा।
- भूमि/भवन की बिक्री पर लागू नहीं होगा GST (स्टाम्प ड्यूटी लागू रहेगी)
- GST कार्य अनुबंध, यानी भवन निर्माण पर लागू होगा।
- निर्माणाधीन इमारत की बिक्री पर GST लागू होगा।

हालांकि, GST लागू होने की तारीख से 1 साल के भीतर जमीन और/या भवन की बिक्री को GST के दायरे में लाने की चर्चा है।

### ● GST दरों की ऊपरी सीमा तय करना- CGST- 20% और IGST- 40%

इससे पहले, दोनों कानूनों में निर्धारित ऊपरी सीमा क्रमशः 14% और 25% थी। अब CGST और IGST कानून के तहत ऊपरी सीमा क्रमशः 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तय की गई है ताकि भविष्य में दरों में वृद्धि के लिए लचीलापन रखा जा सके। हालांकि, GST स्लैब वही हैं - 5%, 12%, 18% और 28%,

### ● पेट्रोलियम उत्पाद GST के दायरे में आएं

पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन/एटीएफ) को अब GST के दायरे में लाया गया है।

यह भारतीय व्यवसायों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा क्योंकि व्यवसाय अब खरीदे गए पेट्रोल उत्पादों पर इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। प्लास्टिक और रासायनिक उद्योगों जैसे कई उद्योगों में पेट्रोलियम उत्पादों को निर्माण के लिए इनपुट के रूप में रखा गया है। इसके अलावा मशीनरी, वाहन चलाने के लिए पेट्रोल/एटीएफ का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता से वस्तुओं की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी।

### ● अपंजीकृत विक्रेता और पंजीकृत खरीदार - GST रिवर्स चार्ज के आधार पर लागू है

एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता बिक्री पर GST नहीं ले सकता है। मॉडल कानून में इस बात का जिक्र नहीं था कि अगर कोई गैर-पंजीकृत डीलर किसी पंजीकृत खरीदार को बेचता है तो कर के साथ क्या व्यवहार किया जाता है।

अधिनियम में अब प्रावधान है कि जब कोई पंजीकृत खरीदार किसी अपंजीकृत डीलर से खरीदता है, तो रिवर्स चार्ज लागू होता है, में खरीदार (माल / सेवाओं का प्राप्तकर्ता) GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह कई राज्यों में लागू एक अपंजीकृत डीलर से माल की खरीद पर वर्तमान खरीद कर के समान है।

### ● संरचना दरों में कमी



विवरण व्यापारी ई पहले कंपोजिशन योजना अब GST अधिनियम में 1 % 0.5 % निर्माता 2.5 % 1 % रेस्तरां एन / ए 2.5 % सेवा प्रदाता एन / ए एन / ए

कंपोजिशन दरों में कमी एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। कंपोजिशन स्कीम में ITC की अनुपलब्धता जैसे कई प्रतिबंध हैं, जो अंतर-राज्यीय लेनदेन के लिए पात्र नहीं हैं। कंपोजिशन दरों में कमी से अधिक करदाता पंजीकरण के लिए आकर्षित होंगे।

तथापि, सेवा प्रदाता कम्पोजिशन स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं जिससे विभिन्न पेशेवरों और फ्रीलांसरों पर बोझ पड़ता है।

### ● कंपोजिशन स्कीम के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं

अब एक करदाता, जिसका टर्नओवर पिछले वित्त वर्ष में 50 लाख से कम था, वह कंपोजिशन स्कीम के तहत भुगतान करने के लिए ओपीटी कर सकता है। उसे उचित अधिकारी की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ता है। वह सीधे कंपोजिशन स्कीम के तहत खुद को पंजीकृत कर सकता है,

### ● सेवाओं की आपूर्ति के प्रावधान समय में परिवर्तन

मॉडल GST कानून में कहा गया था कि सेवाओं की आपूर्ति का समय (यानी, कराधान का बिंदु जब कर का भुगतान करने की देयता उत्पन्न होती है) निम्नलिखित में से पहले होगा:

- चालान जारी करने की तारीख, या
- अंतिम तिथि जिस पर चालान जारी किया जाना चाहिए था, या
- आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त होने की तारीख।

अब अधिनियम, जैसा कि संसद में पारित किया गया है, सेवाओं के लिए आपूर्ति का समय निर्धारित करने के प्रावधानों को बदल दिया गया है। इस प्रकार, सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों से पहले होगा:

**यदि चालान निर्धारित समय के भीतर जारी किया जाता है:**

- ★ चालान जारी करने की तारीख, या
- ★ भुगतान प्राप्त होने की तारीख

जो भी पहले हो

**यदि चालान समय के भीतर जारी नहीं किया जाता है:**

- सेवाएं प्रदान करने की तारीख, या
- भुगतान प्राप्त होने की तारीख

जो भी पहले हो

**यदि खंड (ए) और (बी) लागू नहीं होते हैं, तो:**

वह तिथि जिस पर प्राप्तकर्ता अपने खातों की पुस्तक में सेवाओं की प्राप्ति दिखाता है।

### ● इनपुट क्रेडिट टैक्स को अस्वीकार करने के लिए शर्तों में बदलाव



GST कानून के पहले के प्रावधानों के अनुसार, यदि प्राप्तकर्ता / खरीदार 3 महीने के भीतर सेवा प्रदाता को भुगतान करने में विफल रहता है, तो खरीदार द्वारा प्राप्त इनपुट क्रेडिट टैक्स (ITC) को अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसे ब्याज के साथ प्राप्त ITC की राशि का भुगतान करना होगा। यह केवल सेवाओं के लिए था। यदि खरीदार 3 महीने के बाद भुगतान करता है तो ITC को फिर से अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं था।

अब संशोधित अधिनियम में इस प्रावधान में वस्तुओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, भुगतान की समय अवधि ITC की अनुमति से पहले 3 महीने के बजाय 180 दिनों तक बढ़ा दी गई है। अब, यदि 180 दिनों के बाद भी भुगतान किया जाता है, तो ITC को फिर से अनुमति दी जाएगी।

## ● किराए का क्रेडिट - एक कैब, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की अनुमति है यदि समान श्रेणी की बिक्री के खिलाफ उपयोग किया जाता है

पहले किराया - एक - कैब। जीवन बीमा, और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए पात्र नहीं थे, केवल वे सेवाएं, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जो नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को प्रदान करने के लिए अनिवार्य हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आनंद लेंगे।

ऋण देने से इनकार करने के पहले के प्रावधान के कई परिणाम होते। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा के पुनर्बीमा के मामले में, एक जीवन बीमा कंपनी, बीमा राशि पर भुगतान किए गए GST का क्रेडिट लेने के लिए पात्र नहीं होगी।

करदाता के बोझ को कम करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपरोक्त सेवाओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी:

क्रेडिट को केवल सेवा की एक ही श्रेणी की बाहरी आपूर्ति (बिक्री) के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए। यह खनन या समग्र आपूर्ति का एक हिस्सा भी हो सकता है।

GST एक तारीख को और परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर पेट्रोल पर लागू होगा।

## ● कार्रवाई योग्य दावों पर GST की गैर प्रयोज्यता

मॉडल GST कानून में "माल" की परिभाषा में "कार्रवाई योग्य दावे" शामिल थे। अनुसूची 1 में GST अधिनियम में लोकसभा संशोधन स्पष्ट करते हैं कि लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के अलावा कार्रवाई योग्य सीएल उद्देश्यों को न तो वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

'कार्रवाई योग्य दावों' का अर्थ उन दावों से है जिन्हें केवल कानूनी कार्रवाई या मुकदमे द्वारा लागू किया जा सकता है, उदाहरण के लिए एक बुक डेट बिल ऑफ एक्सचेंज, वचन पत्र। एक पुस्तक ऋण (देनदार) माल नहीं है क्योंकि इसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन बेचा नहीं जा सकता है। विनिमय बिल, वचन पत्र को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत डिलीवरी या एंडोर्समेंट द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन बेचा नहीं जा सकता है।

## 5.1 समाप्ति

बदलावों से पता चलता है कि सरकार GST मुकदमेबाजी को मुक्त करने की पूरी कोशिश कर रही है।





## 6 GST के तहत व्यापार प्रथाओं को फिर से परिभाषित किया गया!



पिछले 70 सालों से देश में एक खास तरीके से कारोबार चलाए जा रहे हैं। भले ही औपचारिक क्षेत्र में देश के कानूनों का पालन करने वाली कंपनियां शामिल थीं, जो पुस्तक के अनुसार अपना संचालन करती थीं, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र इससे बाहर रहा। लिखित नियम का पालन करने के लिए न तो प्रोत्साहन था और न ही सजा। व्यवसायों के लिए निष्पक्ष होने के लिए, कर कानून भी भ्रामक और बोझिल थे ताकि ज्यादातर लोग उनका पालन कर सकें और उनके अनुसार कंपनियां चला सकें। इसलिए, यह व्यवसाय करने का एक जीवन शैली बन गया, जिस तरह से किया गया था, राज्य के खजाने को करों, राजस्व पर नुकसान हुआ, जबकि कंपनियों के लिए व्यापार करना, कई करों का भुगतान करना महंगा हो गया और अंत में उपभोक्ता को अंतिम उत्पाद / सेवा के लिए अधिक भुगतान करके जलाया हुआ सहन करना पड़ा। इसने अर्थव्यवस्था के विकास को भी प्रभावित किया और नीतियों के कार्यान्वयन की बात आने पर बहुत सारी बाधाएं पैदा कीं, भले ही वे कभी-कभी केवल व्यवसायों के लाभ के लिए हों।

GST की शुरुआत के साथ। देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एकरूपता हाथ में गोली मारने की तरह है। बस सही समय पर जब देश विकास के मामले में दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। कर आधार को व्यापक बनाना, अप्रत्यक्ष करों में एकरूपता लाना, जिससे देश के भीतर राज्यों में माल की आवाजाही आसान हो गई। परिचालन की लागत को कम करना GST के कुछ प्रमुख लाभ हैं।

हालांकि, ऐसे सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने और नई कर व्यवस्था के साथ गले लगाने और संरेखित करने के लिए, व्यवसायों के लिए कुछ बड़े बदलावों से गुजरना महत्वपूर्ण है कि वे कैसे चलाए जाते हैं, और इसमें संचालन और इसका मानवीय हिस्सा दोनों शामिल हैं। इससे पहले कि हम इसे विस्तार से समझें, आइए पहले समझते हैं कि GST लागू होने से पहले एक व्यवसाय कैसे चलाया गया था।



## 6.1 व्यापार करने का तरीका: GST से पहले

जब विनिर्माण की बात आती है, तो कंपनियों को न केवल कच्चे माल के मामले में सर्वश्रेष्ठ आपूर्तिकर्ताओं को देखना पड़ता था, बल्कि उन स्थानों को भी देखना पड़ता था जहां से वे उस कच्चे माल का स्रोत करते हैं। इसका कारण यह है कि हर राज्य के पास करों और शुल्कों का अपना सेट था। इसमें लॉजिस्टिक्स लागत को जोड़ें और कंपनियों ने उसी के आधार पर अपनी विनिर्माण योजनाओं को स्थापित करने के बारे में अपने निर्णय लिए।

यह विचार इसलिए किया गया था क्योंकि प्रत्येक कंपनी सबसे कम खरीद लागत, सबसे कम संभव करों का भुगतान करते हुए माल को स्थानांतरित करने में आसानी चाहती थी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपना व्यवसाय कर रहे थे और माल को ले जा रहे थे और अंततः अधिकतम इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना चाहते थे।

लाभ चिह्न के साथ संयुक्त संचालन की वास्तविक लागत के आधार पर उत्पाद का अंतिम खुदरा मूल्य तय करने के बजाय, अंतिम मूल्य बाजार में पहले से मौजूद समान उत्पाद के औसत मूल्य के आधार पर तय किया गया था। यह अंतिम उपभोक्ता के लिए अनुचित था, क्योंकि इसने उसे कम कीमत पर बेहतर उत्पाद प्राप्त करने से वंचित कर दिया, यह सब दोषपूर्ण कराधान प्रक्रिया के कारण था।

इसके अलावा, परिचालन का विस्तार या विविधता लाने का कोई भी निर्णय विशुद्ध रूप से राज्यों के करों और कच्चे माल की सोर्सिंग की लागत के आधार पर लिया गया था। कई बार, संगठनों को अपने मुख्य व्यवसायों के विनिर्माण या आउटसोर्सिंग के बीच चयन करने की दुविधा का सामना करना पड़ता था। इस तरह के फैसलों से एक व्यवसाय अपनी इष्टतम क्षमता, असमान खेल के मैदान को प्राप्त नहीं कर पाया और लंबे समय में अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।

भले ही GST प्रमुख वित्तीय सुधारों में से एक है और सार्वभौमिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक बदलाव स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक के लिए, उन चीजों को करने के तरीके को बदलना आसान नहीं है जो 70 लंबे वर्षों से अभ्यास में हैं। दूसरा, विविध पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता, विविध कौशल- सेट और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के साथ एक अरब से अधिक आबादी को शिक्षित करना और यह सब एक साथ करना कोई मामूली काम नहीं है!

यही कारण है कि GST के सामने कुछ अंतर्निहित चुनौतियां थीं। आइए इन प्रमुख बाधाओं को देखें जिन पर लाइन पार करने से पहले काम करने की आवश्यकता थी:

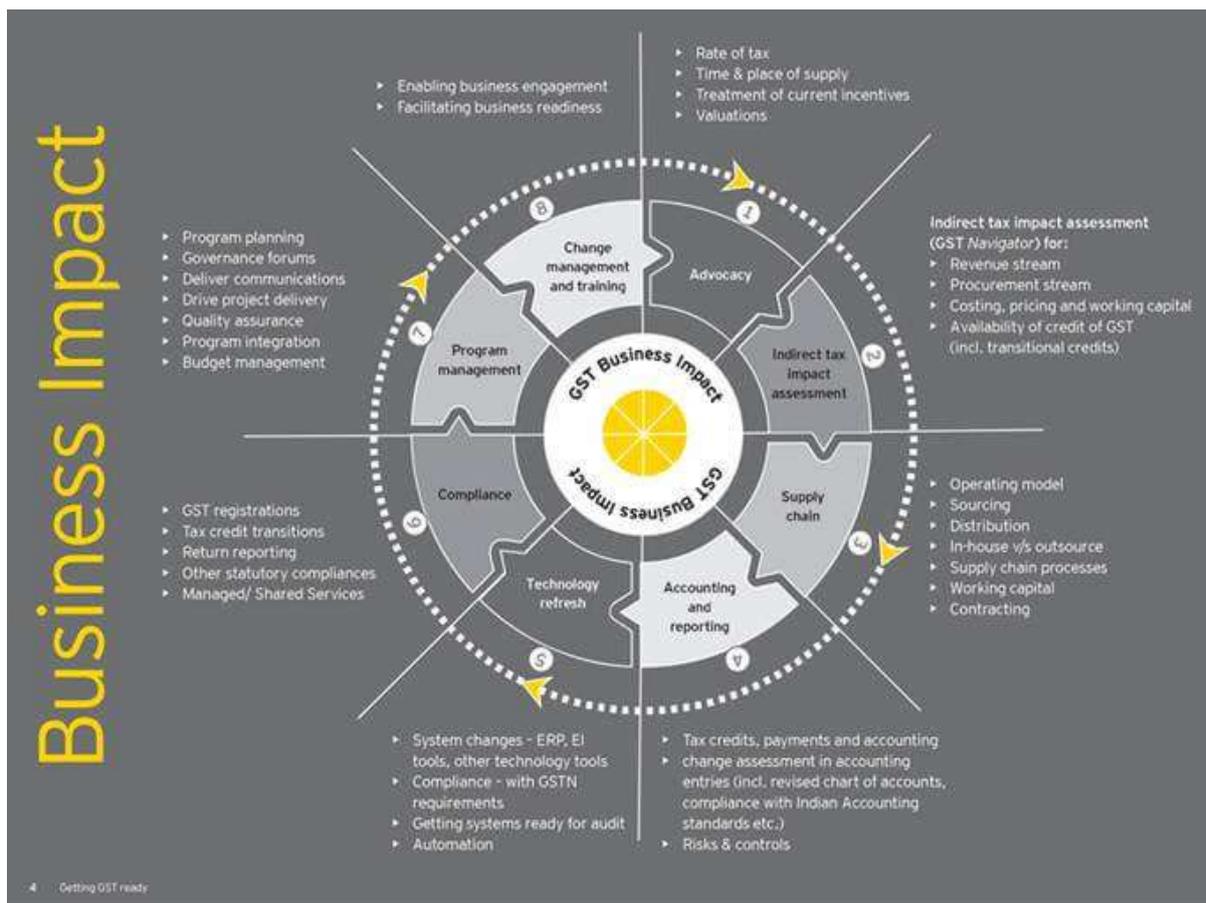
1. **परिवर्तनकारी परिवर्तन: कच्चे माल की खरीद**, इसका निर्माण, इसे बाजार में ले जाने, खरीदार को अंतिम बिक्री के लिए पट्टे पर देने से लेकर हर व्यावसायिक गतिविधि को बदलने की आवश्यकता थी। घटनाओं की पूरी श्रृंखला को फिर से देखने की आवश्यकता है क्योंकि कर सुधार व्यवसाय के प्रत्येक चरण को प्रभावित करता है। इसलिए, प्रत्येक संगठन को ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना पड़ा, न केवल अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को विस्तार से समझना पड़ा, बल्कि उनके विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं और यहां तक कि खरीदारों को भी नई योजनाएं बनाने के लिए समझना पड़ा। यह ध्यान में रखते हुए कि नया कर ढांचा उनकी व्यावसायिक गतिविधि को कैसे प्रभावित करेगा, प्रत्येक कंपनी को कराधान सुधारों के साथ संरेखित करने के लिए विनिर्माण गतिविधि / सेवा उत्पादन के हर कदम का विश्लेषण करना था। यह कहना आसान है क्योंकि भले ही बड़े निगमों के पास इस तरह के विशाल कार्य को संभालने के लिए संसाधन हैं, प्रमुख व्यवसायों के लिए जो छोटे पैमाने पर हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसमें जनशक्ति और धन दोनों के मामले में काफी समय और संसाधन शामिल थे। हर किसी को इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के लिए राजी करना, निश्चित रूप से एक चुनौती थी।



2. **कर अनुपालन रणनीति पर फिर से काम करना:** कर फाइलिंग प्रक्रिया को बदल दिया गया है और GST के दायरे में आने वाले प्रत्येक संगठन को मानदंडों का पालन करना होगा। चुनौती यह है कि अधिकांश छोटे क्षेत्र की कंपनियों ने कभी मानदंडों का पालन नहीं किया है और अभी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग एक बोज़िल प्रक्रिया के रूप में पाते हैं। चूंकि GST फाइलिंग और प्रोसेसिंग एक ऑनलाइन प्रक्रिया होने जा रही है, इसलिए इसका काम इसके बारे में सीखना और विशेषज्ञों को अनिवार्य समयसीमा के अनुसार रिटर्न दाखिल करने में मदद करना है। कई व्यवसायों ने कभी भी आधिकारिक पुस्तकों या चालानों को बनाए नहीं रखा है, लेकिन अब कर राहत का दावा करने के लिए सब कुछ होना चाहिए और पूरी श्रृंखला में एक गड़बड़ भी सभी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए यह कर प्रणालियों का अनुपालन करने के लिए एक व्यक्तिगत कंपनी के बारे में नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए एक ही पृष्ठ पर होना और कुशलतापूर्वक और समय पर अपना काम करना है।
3. **जनशक्ति प्रशिक्षण:** प्रत्येक कंपनी को यह सुनिश्चित करना था कि उनके कर्मचारी और संबंधित कर्मचारी पूरे कर सुधार में बदलावों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि रिटर्न अब एक अलग तरीके से दायर किए जाएंगे। न केवल कर्मचारियों, बल्कि विक्रेताओं और ग्राहकों को भी गलतियों और भ्रम से बचने के लिए पूरी कर प्रक्रिया के बारे में अपडेट करना पड़ा। यह अवधारणा, विनियमों, रिटर्न दाखिल करने, अपलोड करने आदि से जुड़ी वास्तविक प्रक्रिया से लेकर पूरे कर स्पेक्ट्रम के बारे में था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी स्तर पर गलती से उत्पादन की पूरी श्रृंखला में पर्याप्त वित्तीय नुकसान हो सकता है, जो दोगुना चुनौतीपूर्ण है, वह यह है कि भले ही बड़ी कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक संसाधन हैं, छोटी कंपनियों के लिए, यह वित्तीय शिक्षा और कौशल की सीमाओं को देखते हुए एक विशाल कार्य था - एक जटिल कर संरचना को समझने और अनुपालन करने के लिए सेट। हम इसे जटिल कर संरचना कहते हैं क्योंकि यह उन लोगों के लिए है, जो पहली बार कर-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र में आ रहे हैं, भले ही यह अब तक का सबसे सरल कर सुधार है!
4. **कीमतों का निर्धारण:** GST से लंबी अवधि में कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने कंपनियों पर अपने उत्पादों/सेवाओं पर नई कर दरें निर्धारित करने, उनकी लाभप्रदता पर प्रभाव की गणना करने और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लाभ देने की जिम्मेदारी छोड़ दी है। यह अच्छी धारणा है कि अधिकारियों ने यह मान लिया था कि व्यवसाय अपने दम पर लाभ देंगे, लेकिन फिर भी, निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों के जमीनी कार्यान्वयन के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करनी पड़ी। यह कम करों, व्यापक कर आधार और उपभोक्ता को कम कीमतों से अंतिम लाभार्थी होने के बारे में है। इसलिए अनैतिक कीमतों या जटिल कराधान द्वारा मुनाफाखोरी के बिना पुस्तक द्वारा खेले गए सभी लोगों को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती थी।



एक बार जब हम सामने आने वाली चुनौतियों को समझ लेते हैं, तो आइए अब देखें कि GST ने विशिष्ट व्यावसायिक पहलुओं को



कैसे प्रभावित किया:

- कानूनी:** यह किसी भी व्यवसाय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर फिर से काम किया जाना था। नए नियमों और नीतियों के साथ, कंपनी के पूरे कानूनी ढांचे पर पुनर्विचार करना पड़ा और अद्यतन सुधारों के साथ अद्यतित लाया जाना था। कर दरों, आपूर्ति मार्गों, मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों, मौजूदा प्रोत्साहन और वित्तीय लेनदेन के संबंध में निर्णय लिए गए और उन्हें आवश्यक नए दिशानिर्देशों के अनुसार बराबर लाया गया।
- GST को समझना:** नए कर कानून के माध्यम से पर्याप्त जनशक्ति को समर्पित किया गया था, व्यवसाय के हर पहलू पर इसके प्रभाव को नए सिरे से समझना और दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय में किसी भी व्यवधान के बिना इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदमों का आकलन करना GST न केवल करों और राजस्व पर प्रभाव डालेगा, बल्कि सामग्री की खरीद भी करेगा। पूंजी प्रवाह, उत्पादन प्रक्रियाएं, भंडारण निर्णय, अंतिम लागत और उत्पाद और पसंद का मूल्य निर्धारण। इसलिए प्रशिक्षित और समर्पित कर्मचारियों को काम पर रखा गया था और यह एक सतत प्रक्रिया होगी क्योंकि सुचारु संक्रमण के लिए अपेक्षित समय छह से नौ महीने होने जा रहा है, भले ही यह एक बार की प्रक्रिया हो।
- आपूर्ति प्रबंधन:** अंतर-राज्य यात्रा करते समय अधिकांश उत्पादों पर कोई शुल्क या कर नहीं दिया जाना चाहिए। GST से देश भर में उत्पादों का सुगम प्रवाह सुनिश्चित होगा और लॉजिस्टिक्स को संभालना एक आसान प्रक्रिया होगी। बहरहाल, व्यापार करने के बदले हुए तरीके के प्रकाश में, परिवर्तनों को अपडेट करने के लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला को सहारा देना पड़ा। इसमें सोर्सिंग से लेकर वितरण तक हर कदम शामिल था। चूंकि GST से अंतिम ग्राहक द्वारा करों का भुगतान किया जाता



है और हर चरण को इनपुट टैक्स का लाभ मिलता है, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे कि कुछ भी गलत न हो और निर्बाध आपूर्ति और वितरण का प्रबंधन करने के लिए हर कदम को ध्यान में रखा गया था।

4. **लेखा:** एक व्यवसाय के इस पहलू में भी अद्यतन प्रथाओं को रिकॉर्ड पर लाने और कर सुधार को अक्षरशः लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। टैक्स क्रेडिट, चालान, रिटर्न दाखिल करना, सभी प्रकार के भुगतान, रिकॉर्ड रखना, बही-खातों को बनाए रखना और कानून का पालन करना पूरी तरह से फिर से तैयार किया गया है और कर कानूनों का पालन करना नया आदर्श वाक्य है!
5. **प्रौद्योगिकी:** GST रिटर्न का पालन करने और दाखिल करने के लिए न केवल नवीनतम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, बल्कि कार्य को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक कंपनी ने अपनी बिक्री की सुचारू, समय पर और पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और आवश्यक मानदंडों के अनुसार रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए बदलाव किए हैं।
6. **नीतियां:** नए परिवर्तनों का सामना करने के लिए व्यय, नए निवेश, गुणवत्ता आश्वासन, विस्तार, दीर्घकालिक लाभ, वित्तीय व्यवहार्यता आदि पर नीतियों का पूर्ण मूल्यांकन किया जाना था। चूंकि बदलाव सभी क्षेत्रों में हुआ, इसलिए इसने हर संगठन को एक स्तर दिया। हालांकि, इसने आपूर्तिकर्ताओं से निपटने और प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए योजनाएं तैयार करने की कंपनियों की क्षमता को प्रभावित किया।
7. **वेयरहाउसिंग:** पहले, कंपनियों ने सीएसटी और संबंधित बोझिल कागजी कार्रवाई से बचने के लिए अधिक से अधिक राज्यों में एक गोदाम रखने की कोशिश की, विभिन्न नियमों और विनियमों का पालन करने का उल्लेख नहीं किया। GST के साथ, पूरा देश एक बाजार बन गया है और अलग गोदाम रखने की आवश्यकता अब लागू नहीं है। इसके अलावा, माल की आवाजाही निर्बाध होगी क्योंकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कर नहीं होंगे, इस प्रकार गोदाम के मालिक होने और बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
8. **कार्मिक:** अंत में यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो GST से प्रभावित हुआ, हालांकि नकारात्मक तरीके से नहीं। बस, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं और ग्राहकों के साथ कंपनी में सभी को नए कर दिशानिर्देशों के तहत काम करने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाना था। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि संक्रमण सुचारू रूप से हो और आगे बढ़ते हुए, हर कोई एक ही पृष्ठ पर है, सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए समय पर रिटर्न दाखिल और अपलोड कर रहा है।

GST ने भारत के अपने व्यापार के संचालन के तरीके को बदल दिया है और व्यापार प्रथाओं में भारी बदलाव आया है। प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन कुछ वर्षों में, पूरी प्रक्रिया का सकारात्मक प्रभाव सभी के लिए आनंद लेने के लिए होगा।



## 7 भारत में GST प्रक्रिया और विभिन्न फाइलिंग फॉर्म

GST को देश में कर-आधार का विस्तार करने, करों की बहुलता को दूर करने, अप्रत्यक्ष कराधान में एकरूपता लाने और देश को एक एकल बाजार में बदलकर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए लाया गया है, हालांकि, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि एक ट्रेकिंग तंत्र और नए नियमों और विनियमों को लागू करने का एक व्यवस्थित तरीका हो।

यह कहते हुए कि, यह एक नीतिगत निर्णय है जो हर वित्तीय लेनदेन पर लागू नहीं हो सकता है। इसलिए अनावश्यक कागजी कार्रवाई और पर्यवेक्षण पर कीमती संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय अधिकतम एम प्रभाव के लिए नई कर व्यवस्था के तहत कवर किए जाने वाले लेनदेन की पहचान करने की आवश्यकता थी।

इसलिए, GST परिषद ने प्रत्येक व्यवसाय को 10,000 रुपये के वार्षिक कारोबार के साथ लाने का निर्णय लिया। GST के दायरे में 20 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि है। यह इस कारण से भी है कि केवल ऐसे कारोबार वाले व्यक्ति या उद्यम पूरी अप्रत्यक्ष कराधान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और शेष लोग वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में विचार करने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हैं।

एक बार जब कोई संगठन खुद को GST शासन के तहत आने के लिए योग्य पाता है, तो उसे आवश्यक कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करने और निर्धारित फॉर्म और प्रारूप में आवश्यक वित्तीय लेनदेन जमा करने में सक्षम होने के लिए खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है।

आइए समझते हैं कि सेवा प्रदाता व्यापारी निर्माताओं को इसके लिए पात्र होने के बाद 30 दिनों के भीतर GST के तहत खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है:

- एक वित्तीय वर्ष में रु. 20 लाख या उससे अधिक का कारोबार (रु. विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रुपये)
- यदि कोई व्यवसाय पंजीकृत है और फिर किसी और को हस्तांतरित किया जाता है, तो हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरण की तारीख से पंजीकरण करना होगा।
- वह व्यक्ति जो वस्तुओं/सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति में शामिल हो।
- आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति: यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में एजेंट या मूलधन या किसी अन्य क्षमता के रूप में वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति करते हैं जहां GST लागू है और आपके पास ऐसी जगह पर व्यवसाय का एक निश्चित स्थान नहीं है, तो GST के अनुसार आपको एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति माना जाएगा और GST के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी।
- अनिवासी कर योग्य व्यक्ति: उपरोक्त के समान, सिवाय इसके कि यदि आपके पास भारत में व्यवसाय का स्थान नहीं है, तो आपको अनिवासी कर योग्य व्यक्ति माना जाएगा और GST के तहत पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी।
- आपूर्तिकर्ता के एजेंट
- रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स का भुगतान करने वाले।
- इनपुट सेवा एग्रीगेटर
- ई - वाणिज्य ऑपरेटर या एग्रीगेटर
- ई - कॉमर्स एग्रीगेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति।

GST पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्थाएं हैं:

- सेवा प्रदाता

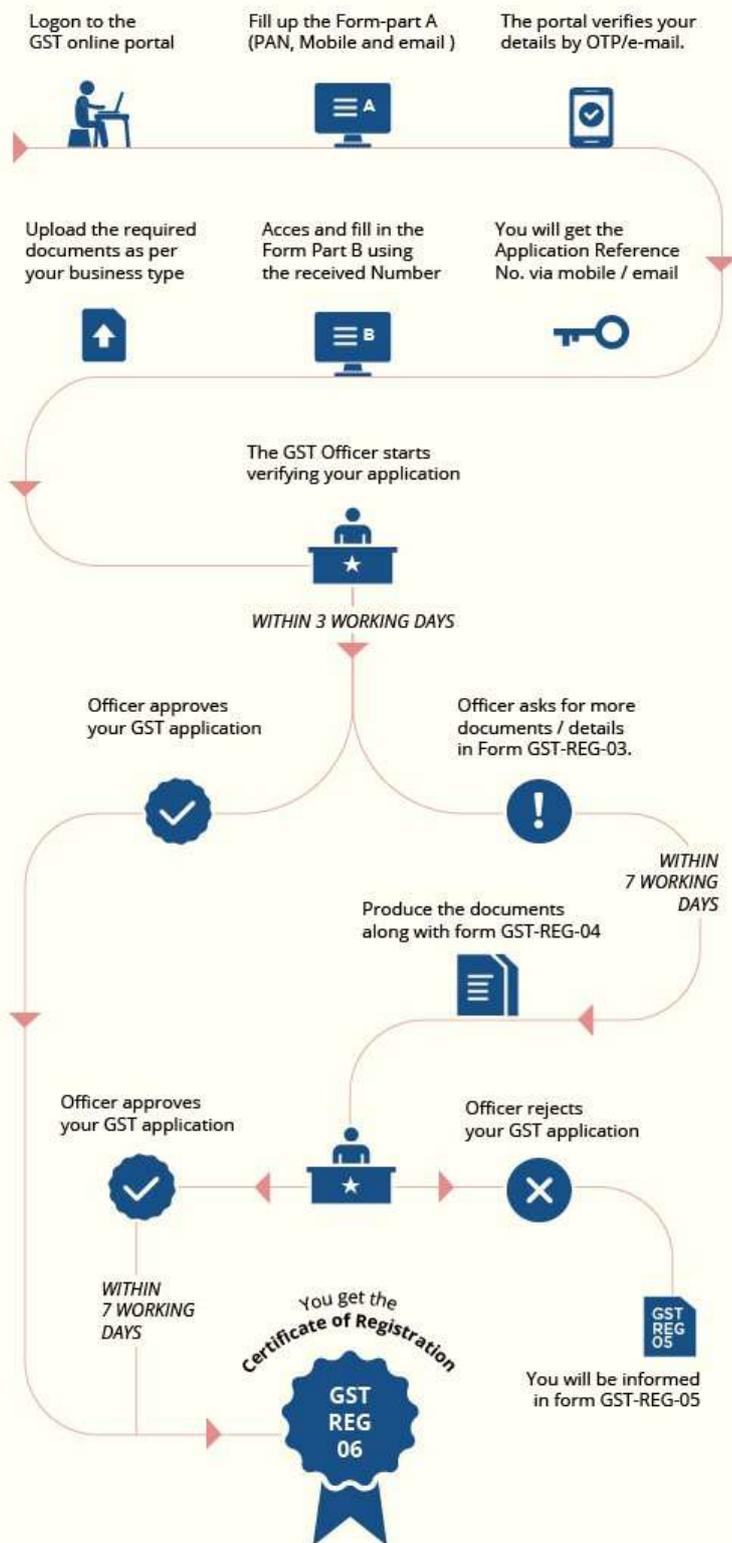


- व्यापारियों
- निर्माताओं
- डीलरों
- निजी, साझेदारी, स्वामित्व फर्म
- ट्रस्टों का प्रबंधन
- दुकान के मालिक

GST के लिए आवेदन करने के लिए नए व्यापारियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:



# HOW TO REGISTER FOR GST





## 7.1 GST के तहत रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया

GST रिटर्न दाखिल करने के लिए विभिन्न व्यवसायों के लिए कुल 11 फॉर्म प्रदान किए गए हैं। रिटर्न दाखिल करना ऑनलाइन है, और सभी करों का भुगतान एक सामान्य GST फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है। वापसी उद्देश्य के लिए मसौदा निम्नानुसार है:

### GSTR -1 – बिक्री रजिस्टर

यह सबसे प्रमुख GST है। सभी वस्तुओं और सेवा आपूर्तिकर्ताओं को रिपोर्टिंग महीने में अपनी बाहरी आपूर्ति की रिपोर्ट करनी होगी। सभी पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों को अगले महीने की 10 तारीख तक GSTR -1 दाखिल करना आवश्यक है। यह डीलरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने के लिए पहला या शुरुआती बिंदु है।

इस तरह फॉर्म दिखता है:

The screenshot shows the GST portal interface for filing GSTR-1. The header includes the GST logo and the text 'Goods and Services Tax'. The user is logged in as 'PALSIN SHIRA'. The main heading is 'GSTR-1 - Outward Supplies made by the Taxpayer'. Below this, there is a form with the following fields:

- GSTIN - 18AAAAS0312A1ZC
- Legal Name - PALSIN SHIRA
- Trade Name -
- FY - 2017-18
- Return Period - June
- Status - Not Filed
- Due Date - 10/07/2017
- Aggregate Turnover in the preceeding financial year\*
- Aggregate Turnover - April to June, 2017\*

There are two input fields for 'Enter Gross Turnover' and a 'SAVE' button. A red box highlights the mandatory fields section. Below the form, there are three buttons: '4A, 4B, 4C, 6B, 6C - B2B', '5A(1), 5A(2) - B2C', and '9B - Credit / Debit Notes'.

### GSTR -2 – खरीद रजिस्टर

इसमें एक महीने के लिए एक पंजीकृत डीलर के सभी खरीद लेनदेन का विवरण होता है। इसमें ऐसी खरीदारी भी शामिल होगी, जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है। एक पंजीकृत डीलर द्वारा दायर GSTR -2 का उपयोग सरकार द्वारा खरीदार-विक्रेता मिलान के लिए विक्रेताओं के GSTR -1 के साथ जांच करने के लिए किया जाता है।

### GSTR -3 – मासिक रिटर्न फॉर्म

यह GST देयता की राशि के साथ महीने के दौरान बिक्री, खरीद, बिक्री के सारांशित विवरण के साथ एक मासिक रिटर्न है। यह रिटर्न GSTR-1 और GSTR-2 से स्वतः सृजित जानकारी है।



## GSTR-4 - कंपाउंडिंग डीलर के लिए तिमाही रिटर्न

इसे हर 3 महीने में एक बार पंजीकृत टीएसी भुगतानकर्ताओं द्वारा दायर करने की आवश्यकता होती है जिन्होंने कंपोजिशन योजना के लिए साइन अप किया है (जो लोग इस योजना का विकल्प चुनते हैं उन्हें कंपाउंडिंग विक्रेताओं या डीलरों के रूप में जाना जाता है)। उन्हें बिना किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधाओं के निश्चित दर पर करों का भुगतान करना होगा।

## GSTR -5 – अनिवासी द्वारा रिटर्न फाइल।

अनिवासी विदेशी करदाता (GST पंजीकरण के तहत विशेष मामले) वे आपूर्तिकर्ता हैं जो यहां बिना किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के भारत में आपूर्ति करने के लिए छोटी अवधि के लिए आए हैं। उत्पादों को आम तौर पर स्थानीय आपूर्ति करने के लिए आयात किया जाता है। इसलिए, उन्हें केवल आयात पर भुगतान किए गए IGST पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, अन्य करदाता अपने द्वारा की गई आपूर्ति का श्रेय ले सकते हैं और फॉर्म GSTR -5 में दाखिल कर सकते हैं।

## GSTR -6 – इनपुट सेवा वितरक के लिए रिटर्न

GSTR-6 एक मासिक रिटर्न है जिसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी) द्वारा दाखिल किया जाना है। इसमें इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और ITC के वितरण का विवरण शामिल है। इनपुट क्रेडिट का मतलब है कि आउटपुट पर टैक्स का भुगतान करते समय, आप इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए कर को कम कर सकते हैं। GSTR-6 हर आईएसडी को दाखिल करना होता है, भले ही वह शून्य रिटर्न हो।

## GSTR-7 – टीडीएस रिटर्न

GSTR-7 वह रिटर्न है जिसे प्रत्येक टीएसी डिडक्टर द्वारा स्रोत पर काटे गए टीएसी के बारे में दाखिल करना होता है। डिडक्टर को रिटर्न फाइल करना होता है और उसे अपने रिटर्न में टीडीएस की राशि का विवरण देना होता है। कटौती होने पर, डिडक्टर द्वारा काटे गए कर के क्रेडिट का दावा अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में करेगा।

## GSTR -8 – वार्षिक रिटर्न

प्रत्येक ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जिसे GST के तहत स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने की आवश्यकता है, को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से GSTR -8 में एक विवरण प्रस्तुत करना होगा। इस रिटर्न में ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई आपूर्ति और आपूर्ति पर एकत्र किए गए कर की मात्रा का विवरण होगा।

## GSTR-9

यह रिटर्न हर पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना है और इसे GST के तहत दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न माना जाता है। कंपोजिशन डीलर के रूप में पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को फॉर्म GSTR -9A में इस तरह के वार्षिक रिटर्न जमा करने होंगे। इसके अलावा, 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता है। ऐसी व्यावसायिक इकाइयों को ऑडिट किए गए वार्षिक खातों और मिलान विवरण प्रस्तुत करना होगा, जो फॉर्म GSTR -9 B के तहत विधिवत प्रमाणित होगा।

## GSTR-10



कोई भी व्यावसायिक इकाई जो स्वेच्छा से व्यवसाय करना बंद कर देती है या सक्षम अधिकारियों के आदेशों के तहत इसे बंद कर देती है, उससे यह रिटर्न दाखिल करने की उम्मीद की जाती है।

### **GSTR-11**

कोई भी व्यक्ति, जिसे एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) जारी की गई है और वह अपनी आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों की वापसी का दावा करता है, उसे इस फॉर्म के तहत कर योग्य वस्तुओं / सेवाओं का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसे उस महीने के बाद के महीने की 18तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब आपूर्ति प्राप्त हुई थी।



# Types and Due Dates of GST Returns

## Registered Taxable Person

### GSTR-1

Outward supplies of taxable goods and/or services

10<sup>th</sup> of the next month

### GSTR-2

Inward supplies of taxable goods and/or services

15<sup>th</sup> of the next month

### GSTR-3

Monthly return

20<sup>th</sup> of the next month

### GSTR-9

Annual Return

31<sup>st</sup> December of next financial year

## Composition Supplier

### GSTR-4

Quarterly return for compounding taxable person.

18<sup>th</sup> of the next month

## Non-Resident Taxable Person

### GSTR-5

Return for Non-Resident foreign taxable person

20<sup>th</sup> of the next month

## Input Service Distributor

### GSTR-6

Return for Input Service Distributor

13<sup>th</sup> of the month succeeding quarter

## Tax Deductor

### GSTR-7

Return for authorities deducting tax at source.

10<sup>th</sup> of the next month

## E-commerce Operator

### GSTR-8

Details of supplies effected through e-commerce operator

10<sup>th</sup> of the next month

**clearTax**

Get GST Software Free Trial  
at <https://cleartax.in/gst>

## 7.2 GST के तहत भुगतान प्रक्रिया

यह एक बड़ी सफलता है कि GST कर भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है, जो कागजी कार्रवाई को काफी हद तक कम कर देता है। एकल बिंदु पर, GSTN चालान उत्पन्न होता है। भुगतान मोड करदाता की पसंद के अनुसार हो सकता है।



विकल्प हैं:

ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी/आरटीजीएस या बैंक में जमा नकदी या चेक के माध्यम से। यह ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक फॉर्म भरने और जमा करने का पालन करना GST कानून के तहत आवश्यक है और इसका पालन डर के कारण नहीं, बल्कि इस तथ्य के लिए किया जाना चाहिए कि यह न केवल व्यवसाय के लिए, बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है!



## 8 GST रिटर्न कैसे फाइल करें!

जबकि भारत अपने अब तक के सबसे बड़े कर सुधारों की ओर बढ़ रहा है, रिकॉर्ड के रखरखाव और रिटर्न दाखिल करने के लिए कई प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। यह गंतव्य-आधारित कर - रिपोर्टिंग संरचना को जन्म दे रहा है। वर्तमान प्रणाली में, प्रत्येक लेनदेन को अंतिम मील के माध्यम से एक सामान्य चालान के साथ सूचित किया जाना चाहिए, जो माल और सेवाओं के विक्रेता और प्राप्तकर्ता के लिए पहचान योग्य है।

GST परिषद और वित्त मंत्रालय ऐसे सभी चालानों को एक ही स्थान पर रिकॉर्ड करने और करदाता के लिए डेटा एकत्र करने के लिए एक शानदार समाधान लेकर आए हैं। प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, और कई करों को हटा दिया गया है। पूरा देश एक ही संरचना का उपयोग करके रिपोर्ट करेगा, भले ही आप अपना व्यवसाय कहां और कैसे ले जाएं।

GST के प्रभावी होने की तारीख से लगभग 1 करोड़ व्यावसायिक संस्थाओं ने GST के तहत पंजीकरण किया है, यानी 1 जुलाई 2017 इससे उनमें से प्रत्येक के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित GST रिटर्न देय तिथि अनुसूची के अनुसार GST रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य हो जाता है। GST के तहत पंजीकृत सभी व्यवसायों के लिए GST रिटर्न फाइलिंग अनिवार्य है, चाहे कोई भी व्यावसायिक गतिविधि, बिक्री या लाभ हो। इसलिए, भले ही कोई व्यावसायिक इकाई निष्क्रिय हो गई हो, लेकिन GST पंजीकरण है, उसे GST रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

मंत्रालय द्वारा डेटा की इतनी बड़ी आमद से निपटने के लिए एक व्यापक आईटी प्रणाली तैनात की गई है। इसे GSTN (गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क) कहा जाता है जो विक्रेताओं और खरीदारों की सभी जानकारी को एक साथ रखेगा, प्रस्तुत विवरणों को सहयोग करेगा और यहां तक कि भविष्य के संदर्भ और किसी भी समय सामंजस्य के लिए आपके लिए 3 रजिस्टर बनाए रखेगा। GSTN को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक लेनदेन एक-दूसरे के साथ समन्वय में है और खरीदार और विक्रेता के बीच लेनदेन की पूरी श्रृंखला को रिकॉर्ड करता है।

नवीनतम GST व्यवस्था के तहत GST दाखिल करना महत्वपूर्ण है और गैर-अनुपालन या देरी, यदि कारण बनती है, तो जुर्माना, जुर्माना और त्रुटि - पूर्ण पुस्तक रखरखाव का कारण बन सकता है। जबकि समय पर अनुपालन निर्दोष रिकॉर्ड बनाए रखने और समय पर रिफंड प्राप्त करने में मदद करेगा।

GST रिटर्न दाखिल करने के लिए विभिन्न व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। आमतौर पर, GST रिटर्न एक दस्तावेज होता है जिसमें आय का विवरण होता है जिसे करदाता को कर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दाखिल करना आवश्यक होता है। इसका उपयोग कर अधिकारियों द्वारा कर देयता की गणना करने के लिए किया जाता है।

GST के तहत, एक पंजीकृत डीलर को GST रिटर्न दाखिल करना होता है जिसमें शामिल हैं:

- खरीद
- बिक्री
- आउटपुट GST (बिक्री पर)
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (खरीद पर भुगतान किया गया GST)

GST रिटर्न दाखिल करने के लिए GST अनुरूप बिक्री और खरीद चालान की आवश्यकता होती है। कोई भी चालान छूट नहीं सकता। इसलिए, उचित प्रलेखन और रिकॉर्ड के हर एक टुकड़े को संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।



अब, GST रिटर्न दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विभिन्न फॉर्मों के तहत भरा जा सकता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि करदाता किस श्रेणी में आता है।

हम समझेंगे कि GST रिटर्न कैसे विभिन्न फॉर्मों के आधार पर निम्नानुसार दाखिल किया जाए:

1. **GSTR -1:** यह दाखिल किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिटर्न है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की सभी बाहरी आपूर्ति विस्तार से शामिल है। इसे GST के तहत सभी कर योग्य पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दायर किया जाना है, सिवाय उन लोगों के, जिन्हें उस श्रेणी के आधार पर अलग-अलग GST रिटर्न फॉर्म दाखिल करने के लिए अनिवार्य है, जिसमें वे आते हैं। इसे अगले महीने के 10 बजे तक भरना होगा और क्रेडिट सुलह के लिए भविष्य के सभी प्रवाह और मिलान का आधार बनेगा। आवश्यक जानकारी के माध्यम से जाने और आवश्यक जानकारी के बारे में चेकलिस्ट के साथ तैयार होने के बाद, किसी को अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ GSTN पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। उसके बाद रिटर्न दाखिल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
  - "सेवाओं" के लिए खोज करें और फिर रिटर्न पर क्लिक करें, उसके बाद डैशबोर्ड।
  - यहां, करदाता को वित्तीय वर्ष और उस महीने में प्रवेश करना होगा जिसके लिए रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद खोज पर क्लिक करें।
  - स्क्रीन संबंधित समय अवधि से संबंधित सभी रिटर्न प्रदर्शित करेगी।
  - दिए गए विकल्पों में से GSTR 1 का चयन करें।
  - अगला कदम ऑनलाइन तैयारी करने या रिटर्न अपलोड करने के बीच विकल्प चुनना है।
  - पूरा फॉर्म भरने के बाद, सबमिट पर क्लिक करें और भरे गए डेटा को मान्य करें।
  - डेटा को मान्य करने के बाद, फाइल GSTR - 1 पर क्लिक करें और या तो ई - साइन करें या डिजिटल रूप से फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।
  - एक बार फॉर्म जमा करने के लिए स्वीकार करने के बाद, एक पावती संदर्भ संख्या (ARN) उत्पन्न होगी।

करीब से देखें:

2. **GSTR -2:** जबकि GSTR - 1 आपूर्तिकर्ताओं के लिए है, GSTR - 2 प्राप्तकर्ताओं के लिए है। इसमें प्राप्तकर्ता की ओर वस्तुओं और सेवाओं की सभी आवक आपूर्ति शामिल है। इसे अगले महीने के 15 तक दाखिल करना होगा क्योंकि यह फॉर्म आपूर्तिकर्ताओं द्वारा GSTR - 1 भरने के बाद भरा जाता है, वे विवरण फॉर्म में ऑटो भरे जाते हैं। GST के तहत पंजीकृत सभी को इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता है, जिसमें GSTR - 1 दाखिल करने वाले भी शामिल हैं। हालांकि, कुछ अपवाद हैं, जिनमें इनपुट सेवा वितरक, GST के तहत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, कंपाउंडिंग योजना के तहत पंजीकृत, कर दाता और ई-कॉमर्स ऑपरेटर शामिल हैं। उन्हें अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे।

एक बार जब आपके पास सभी जानकारी हो जाती है, तो आप उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके GSTN पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। यह फॉर्म GSTR-1, GSTR-5, GSTR-6, GSTR-7 और ई-कॉमर्स नियामक द्वारा स्रोत पर एकत्र किए गए कर के विवरण से भरा होगा।



उसके बाद, 13 उपशीर्षकों के तहत आवश्यक विवरण दर्ज करें और अंत में एक घोषणा के साथ साइन ऑफ करें कि सभी जानकारी प्रदान की गई है और सही है। वस्तु एवं सेवा कर (GST)

3. **GSTR - 3:** यह फॉर्म ऑटो है - अगले महीनों के 20 तक तैयार किया गया है। इसमें GSTR -1 और GSTR - 2 में अपडेट की गई वस्तुओं और सेवाओं की सभी आवक और बाहरी आपूर्ति की पूरी जानकारी शामिल है, यह फॉर्म GSTR - 1 और GSTR - 2 के पूरे विवरण को देखने के बाद आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्धता या देय कर की राशि निर्धारित करने में मदद करता है। आप यूजरनेम और पासवर्ड के साथ GSTN पोर्टल में लॉग इन करने के बाद इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ऑटो-तैयार जानकारी के अलावा, आपको भाग बी भरने की आवश्यकता है जिसमें अवधि के दौरान भुगतान किए गए किसी भी कर, ब्याज, दंड या शुल्क और अवधि के दौरान दावा किए गए किसी भी रिफंड के बारे में किसी भी विवरण की आवश्यकता होती है। W.R.T. नकद बहीखाता।
4. **GSTR - 4 ए और 4:** GSTR - 4 ए कंपोजिशन योजना के करदाताओं के लिए तिमाही आधार पर स्वतः उत्पन्न होता है। इस जानकारी के आधार पर, करदाता को सभी बाहरी आपूर्ति को अपडेट करने की आवश्यकता है। इसे त्रैमासिक रूप से दायर किया जाना है और देय तिथि अगले महीने का 18% है। प्रक्रिया GSTN पोर्टल पर लॉग इन करने और वहां उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करने के समान होगी। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है।
5. **GSTR - 5:** इस फॉर्म को अगले महीनों के 20 से पहले या समर्पण या पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर भरना होगा। GSTN पोर्टल में आसानी से फॉर्म जमा करने में मदद करने के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी देता हूं।
6. **GSTR - 6 ए और 6:** GSTR - 6 ए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा GSTR - 1 दाखिल करने के एक दिन बाद अगले महीनों में 11 बजे तक उत्पन्न किया जाएगा। इसमें इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) को किए गए आंतरिक आपूर्तिकर्ता के सभी विवरण शामिल होंगे। एक बार जब आईएसडी इस तरह के विवरणों को सत्यापित या सही कर लेता है, तो GSTR - 6 उत्पन्न होगा जिसे अगले महीने की 13 तारीख तक दाखिल करने की आवश्यकता होगी। ऐसी सभी फाइलिंग जरूरतों के लिए GSTN पोर्टल आगे बढ़ने का तरीका है।
7. **GSTR - 7 और 7 ए:** महीने के दौरान सभी कर कटौती को अपडेट करने के लिए इस फॉर्म को दाखिल करना होगा। इस फॉर्म को दाखिल करने की नियत तिथि अगले महीने का 10% है। इसे अपडेट किए जाने के बाद, एक टीडीएस प्रमाण पत्र, GSTR - 7 ए स्वतः उत्पन्न होगा और करदाताओं के लिए डाउनलोड करने और ट्रैक रखने के लिए उपलब्ध होगा।
8. **GSTR - 8:** यह फॉर्म ई - कॉमर्स विक्रेता द्वारा भरा जाना है। इसमें की गई सभी आपूर्ति के साथ-साथ एकत्र किए गए कर की राशि भी शामिल है। इसे अगले महीने के 10% तक दायर करने की आवश्यकता है। GSTN पोर्टल में दिशानिर्देशों का पालन करने और फॉर्म को आसानी से जमा करने में आपकी सहायता करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग है
9. **GSTR -9:** यह एक वार्षिक रिटर्न है जिसे सभी करदाताओं द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक दाखिल किया जाना है। इसमें करदाताओं के पूरे 12 GSTR -3 शामिल हैं। एक बार जब आप दिए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ GSTN पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, तो आवश्यक विवरण जमा करने के अलावा, आपको वर्ष के दौरान भुगतान किए गए कर की राशि भी जमा करनी होगी और किसी भी निर्यात या आयात का विवरण शामिल करना होगा।



संपूर्ण GST व्यवस्था के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि पोर्टल स्वचालित रूप से वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न रूपों में सभी जानकारी को एक साथ रखता है। हालांकि, पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम GSTR - 1 दाखिल करना है, जो पूरी गतिविधि का आधार बनता है।

## 8.1 GST फाइल करने के लिए किन लोगों की जरूरत है?

GST व्यवस्था में 20 लाख या उससे अधिक का कारोबार करने वाले किसी भी नियमित कारोबारी या व्यक्ति को GST रिटर्न दाखिल करना होता है। ऐसे व्यवसायों को तीन मासिक रिटर्न और एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है। इस प्रणाली का लाभ यह है कि किसी को मैन्युअल रूप से एक मासिक रिटर्न - GSTR - 1 का विवरण दर्ज करना होगा। अन्य दो रिटर्न - GSTR 2 और 3 आपके और आपके विक्रेताओं द्वारा दायर GSTR - 1 से जानकारी प्राप्त करके स्वतः पॉप्युलेट हो जाएंगे।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब फॉर्म भरने और उन्हें जमा करने की समय सीमा को पूरा करने की बात आती है, तो अत्यधिक अनुशासन बनाए रखना पड़ता है, न केवल दंड से बचने के लिए, बल्कि समय पर कर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए भी। करदाताओं के लाभ के लिए, पूरे GSTN पोर्टल को सरल और समझने में आसान रखा गया है और साथ ही डेटा का एक सहज समावेश प्रदान करता है ताकि पूरी जानकारी बिना किसी जटिलता के एक्सेस की जा सके।



## 9 GST गैर-अनुपालन दंड और अपील क्या है!

GST कानून ने स्पष्ट रूप से अपराधों के विवरण और प्रत्येक परिदृश्य में लगाए गए दंड को परिभाषित किया है। यह सभी व्यापार मालिकों, CA और टैक्स पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि अनजाने में गलती गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है।

इस लेख में, हम निम्नलिखित विषयों को कवर करते हैं:

- सिंहावलोकन
- अपराध और दंड
- GST के तहत निरीक्षण
- GST के तहत तलाशी और जब्ती
- पारगमन में माल
- GST के तहत अपराधों का कंपाउंडिंग
- GST के तहत अभियोजन
- GST के तहत गिरफ्तारी
- अपील
- सिंहावलोकन

कर चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, GST ने दंड, अभियोजन और गिरफ्तारी के संबंध में अपराधियों के लिए सख्त प्रावधान लाए हैं।

### 9.1 अपराध और दंड

#### अपराध

GST के तहत 21 अपराध हैं, हमने यहां कुछ का उल्लेख किया है। 21 अपराधों की पूरी सूची के लिए कृपया अपराधों पर हमारे मुख्य लेख पर जाएं।

#### GST के तहत प्रमुख अपराध हैं:

- कानून द्वारा आवश्यक होने के बावजूद GST के तहत पंजीकरण नहीं करना। (GSTआई के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने वालों की सूची के लिए हमारा लेख पढ़ें)
- किसी भी चालान के बिना या गलत चालान जारी किए बिना किसी भी सामान / सेवाओं की आपूर्ति।
- किसी कराधीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य वास्तविक करदाता के GSTआईएन का उपयोग करके चालान जारी करना
- GST के तहत पंजीकरण करते समय गलत जानकारी प्रस्तुत करना
- कर चोरी के लिए नकली वित्तीय रिकॉर्ड / दस्तावेज या फाइलें, या झूठे रिटर्न जमा करना।
- धोखाधड़ी से धनवापसी प्राप्त करना।
- कर चोरी के लिए बिक्री को जानबूझकर दबाना।
- करदाता के अयोग्य होने के बावजूद कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनना।



## दण्ड

यदि कोई अपराध किया जाता है, तो GST के तहत जुर्माना देना होगा, जिन सिद्धांतों पर ये दंड आधारित हैं, कानून द्वारा भी उल्लेख किया गया है।

### 1. देर से फाइलिंग के लिए

देर से भरने पर विलंब शुल्क नामक जुर्माना लगता है। विलंब शुल्क प्रति अधिनियम प्रति दिन 100 रुपये है। इसलिए, CGST के तहत यह 100 और SGST के तहत 100 है। कुल 200 रुपये दिन होंगे। अधिकतम 5,000 रुपये है। देरी से भरने के मामले में IGST पर कोई विलंब शुल्क नहीं है।

विलंब शुल्क के साथ 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होता है। इसकी गणना करदाता को भुगतान किए जाने वाले कर पर करनी होती है। समय अवधि फाइलिंग के अगले दिन से भुगतान की तारीख तक होगी।

### 2. नहीं भरने के लिए

यदि आप कोई GST रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो बाद में रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अगस्त का GSTR - 2 रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो अगला रिटर्न GSTR - 3 और सितंबर का बाद का रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, GST रिटर्न देर से दाखिल करने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा जिससे भारी जुर्माना और जुर्माना लगेगा (नीचे देखें)

### 3. धोखाधड़ी या कर चोरी के इरादे के बिना 21 अपराधों के लिए

कर का भुगतान नहीं करने वाले या कम भुगतान करने वाले अपराधी को कर राशि का 10% जुर्माना देना होगा जो न्यूनतम 10,000 रुपये तक होगा। 10,000

**विचार:** यदि कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है, तो न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अधिकतम जुर्माना बकाया कर का 10% है।

### 4. धोखाधड़ी या कर चोरी के इरादे से 21 अपराधों के लिए

एक अपराधी को कर चोरी/कम कटौती आदि की जुर्माना राशि का भुगतान करना पड़ता है। 100% जुर्माना, जिसकी न्यूनतम सीमा 10000 रुपये है। 10,000.

### अतिरिक्त दंड निम्नानुसार हैं:

इसमें शामिल कर राशि	100-200 लाख	200-500 लाख	500 लाख से ऊपर
जेल की सजा	2 साल तक	3 साल तक	5 साल तक
समाप्ति		तीनों मामलों में	

धोखाधड़ी के मामलों में दंड, अभियोजन और गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ता है।

## GST के तहत निरीक्षण



SGST/CGST के संयुक्त आयुक्त (या उच्च अधिकारी) के पास यह मानने के कारण हो सकते हैं कि कर चोरी के लिए किसी व्यक्ति ने किसी लेनदेन को दबा दिया है या अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट आदि का दावा किया है। फिर संयुक्त आयुक्त CGST/SGST (लिखित में) के किसी अन्य अधिकारी को संदिग्ध चोर के कारोबार के स्थानों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

## GST के तहत तलाशी और जब्ती

SGST/CGST के संयुक्त आयुक्त तलाशी के लिए आदेश दे सकते हैं। वह निरीक्षण (या अन्य कारण) के परिणामों के परिणामों के आधार पर एक खोज का आदेश देगा यदि उसके पास विश्वास करने के कारण हैं:

ऐसे सामान हैं जिन्हें जब्त किया जा सकता है:

- कोई भी दस्तावेज या किताबें या अन्य चीजें जो कहीं छिपी हुई हैं। ऐसी वस्तुएं कार्यवाही के दौरान उपयोगी हो सकती हैं।

इस तरह के आपत्तिजनक सामान और दस्तावेज जब्त किए जा सकते हैं।

## पारगमन में माल

50,000 रुपये से अधिक का सामान ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता होती है:

- चालान या आपूर्ति या वितरण चालान का बिल
- ई-वे बिल की कॉपी (हार्ड कॉपी या आरएफआईडी के माध्यम से)

उचित अधिकारी के पास पारगमन में माल को रोकने और माल और दस्तावेजों का निरीक्षण करने की शक्ति है। अगर सामान GST एक्ट का उल्लंघन करता है तो सामान, संबंधित दस्तावेज और उसे ले जाने वाले वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। कर और जुर्माने के भुगतान पर ही माल जारी किया जाएगा।

माल जब्त करने से पहले, कर अधिकारी को जब्त करने के बजाय जुर्माना देने का विकल्प देना होगा।

## GST के तहत अपराधों का कंपाउंडिंग

मुकदमेबाजी से बचने के लिए अपराधों को कम करना एक शॉर्टकट तरीका है। आपराधिक अदालत में अपराध के लिए अभियोजन के मामले में, अभियुक्त को एक वकील के माध्यम से हर सुनवाई में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है।

कंपाउंडिंग में, आरोपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है और उसे शमन शुल्क के भुगतान पर आरोपमुक्त किया जा सकता है जो GST के तहत लागू अधिकतम जुर्माने से अधिक नहीं हो सकता है।

कंपाउंडिंग से समय और पैसे की बचत होगी। हालांकि, GST के तहत कंपाउंडिंग उन मामलों के लिए उपलब्ध नहीं है जहां इसमें शामिल मूल्य 1 करोड़ से अधिक है।

## GST के तहत अभियोजन

अभियोजन पक्ष आपराधिक आरोप के संबंध में किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रहा है।

धोखाधड़ी के जानबूझकर इरादे से अपराध करने वाला व्यक्ति GST के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो जाता है। वह आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। इन अपराधों के कुछ उदाहरण हैं:



- किसी भी वस्तु / सेवाओं की आपूर्ति के बिना चालान जारी करना इस प्रकार धोखाधड़ी से इनपुट क्रेडिट या रिफंड लेना
- धोखाधड़ी से किसी भी CGST /SGST की वापसी प्राप्त करना।
- कर चोरी के लिए नकली वित्तीय रिकॉर्ड / दस्तावेज या फाइलें जमा करना, और नकली रिटर्न जमा करना।
- GST के तहत धोखाधड़ी करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद करना।

## GST के तहत गिरफ्तारी

यदि CGST SGST के आयुक्त का मानना है कि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित अपराध किया है तो उसे किसी भी अधिकृत CGST SGST अधिकारी द्वारा GST के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है

गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। वह संज्ञेय अपराध के मामले में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा (संज्ञेय अपराध वे हैं जहां पुलिस गिरफ्तारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है)। वे हत्या, डकैती, जालसाजी जैसे गंभीर अपराध हैं)।

## अपील

GST के तहत अपने खिलाफ पारित किसी भी निर्णय या आदेश से नाखुश व्यक्ति ऐसे फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।

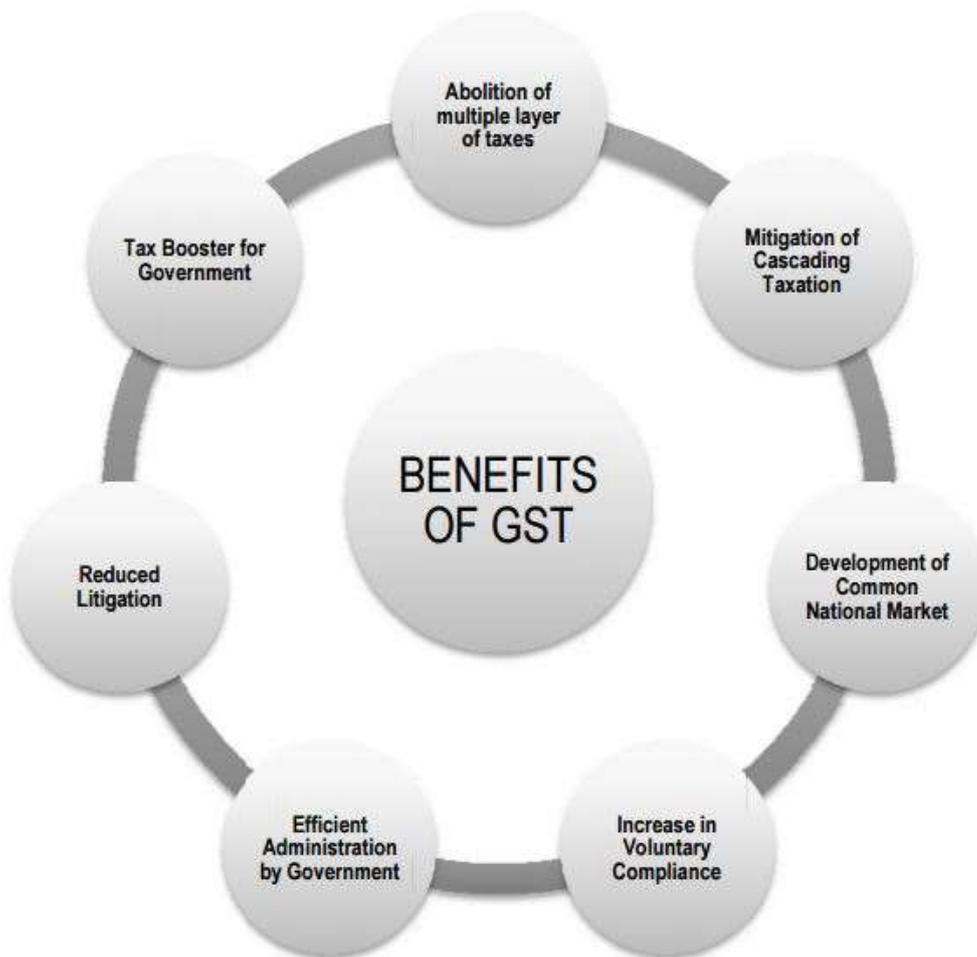
एक निर्णायक प्राधिकरण द्वारा आदेश के खिलाफ पहली अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास जाती है, करदाता प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के फैसले से खुश नहीं होता है, वे राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण, फिर उच्च न्यायालय और अंत में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।



## 10GST लागू होने के क्या लाभ हैं?

GST 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है और रिटर्न जल्द ही रोल आउट होने जा रहे हैं और एक समान और व्यवस्थित रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो शायद ही कहीं और पाया जाता है। यह लेनदेन वार, गंतव्य-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली एक बहुत प्रभावी क्रेडिट प्रवाह प्रदान करती है, भ्रष्टाचार और अवैध लेनदेन की संभावनाओं को दूर करती है, क्योंकि पूरी प्रणाली केंद्रीकृत और स्वचालित होगी।

एक त्वरित दृष्टिकोण में, ये GST के लाभ हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे।



1947 के बाद से (अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में) सबसे बड़े कर सुधारों में से एक के रूप में देखा जा रहा है, GST देश को एक राजनीतिक संघ से 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक संघ में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे विकसित देशों में मौजूद इस फैब्ड टैक्स सिस्टम के तहत, भारत में करदाता मूल्य वर्धित कर (VAT), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर या चुंगी, सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार और उपकर, लकजरी कर, मनोरंजन कर जैसे करों के ढेरों के बजाय एक समेकित कर का भुगतान करेंगे। और खरीद कर और कुछ अन्य अप्रत्यक्ष कर। जिससे अप्रत्यक्ष कराधान की प्रक्रिया को समेकित, सुव्यवस्थित और आसान और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलती है।

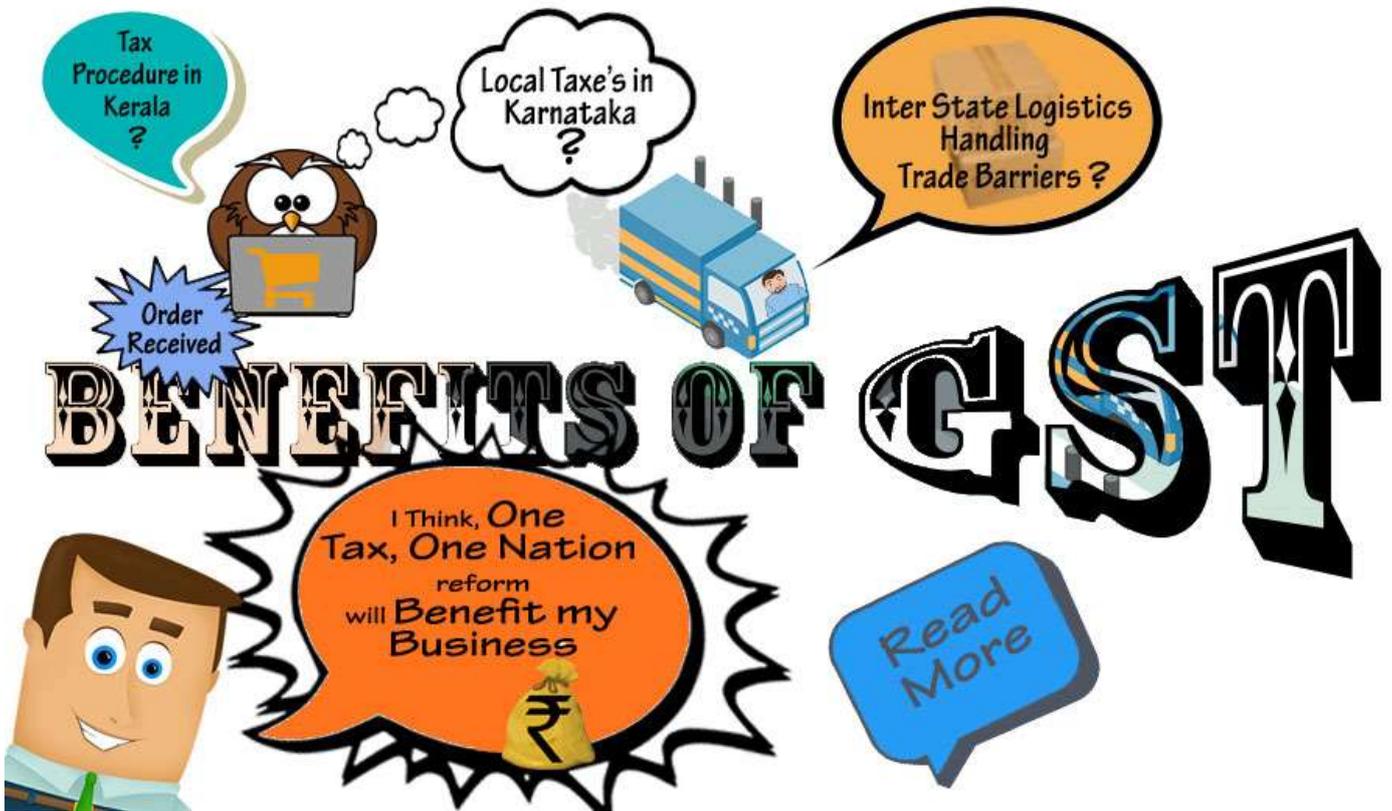
वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर खपत के अंतिम बिंदु पर GST देय होगा; इसे "लेनदेन मूल्य" कहा जाता है। इस लेनदेन मूल्य या वास्तविक भुगतान मूल्य, वस्तु या सेवा खरीदते समय, पैकिंग लागत, कमीशन और उनकी बिक्री के लिए किए गए अन्य सभी



खर्च शामिल होंगे। GST परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं के लिए 5%, 12%, 18%, और 28% के चार कर दर स्लैब को अंतिम रूप दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूध उत्पादों और शराब को आगामी GST व्यवस्था में कर से छूट जारी रहेगी। इसी तरह, सोना और कच्चे हीरे मौजूदा दर स्लैब के तहत नहीं आते हैं और उन पर क्रमशः 3% और 0.25% कर लगाया जाएगा।

GST के कार्यान्वयन से पहले, उदाहरण के लिए, सात राज्यों में व्यावसायिक हित रखने वाले उद्यमियों को उनके द्वारा भुगतान किए गए मूल्य वर्धित कर (VAT) में सात अलग-अलग कर दरों के साथ सात अलग-अलग कर अधिकारियों से निपटना होगा। हालांकि, GST के लिए फाइलिंग करते समय, उन्हें केवल दो प्रकार के पंजीकरण को निष्पादित करना होगा, एक राज्य के लिए - GST और दूसरा केंद्रीय GST के लिए। इसके अलावा, GST के साथ भारत के सभी राज्यों में समान कर दर होगी, जो कई व्यवसायों के लिए रसद लागत को कम करेगी। इस प्रकार, इस मोड़ पर भारतीय स्टार्टअप समुदाय को GST के कार्यान्वयन से काफी लाभ होगा।

युवा उद्यमियों के लिए GST एक अच्छी खबर है। यहां चार प्रमुख तरीके दिए गए हैं जिनमें भारतीय स्टार्टअप को नई प्रणाली से लाभ होगा।



## 10.1 व्यापार करना आसान बनाना

GST प्रक्रिया और केंद्रीकृत पंजीकरण में एकरूपता लाएगा जो व्यवसाय शुरू करने और विभिन्न राज्यों में विस्तार को बहुत आसान बना देगा। चूंकि स्टार्टअप के पास कर अनुपालन के विभिन्न रूपों को संभालने के लिए एक समर्पित टीम के कर विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए संसाधनों की कमी है, GST का उद्देश्य करों की बहुलता को कम करके कर व्यवस्था को सरल बनाना है। इससे न केवल अनुपालन लागत कम होगी, बल्कि डिजिटल टैक्स प्रोसेसिंग के साथ कराधान भी पारदर्शी होगा। इ इट योरसेल्फ (DIY) मॉडल स्टार्टअप संस्थापकों को करदाता पंजीकरण, कर रिटर्न जमा करने, कर भुगतान और ऑनलाइन रिफंड का दावा करने में सक्षम करेगा, जिससे सभी प्रकार के उद्यमों के लिए पैसे की बचत होगी, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों।



## 10.2 2. रसद लागत और राज्यों में लगने वाले समय में कमी

GST यह सुनिश्चित करेगा कि छोटे सीमा करों को समाप्त करके और चेक पोस्ट मुद्दों को हल करके अंतरराज्यीय आवागमन सस्ता हो जाए और कम समय लेने वाला हो। यह अनिवार्य रूप से उच्च स्टॉक को बनाए रखने से जुड़ी लागत को कम करेगा, क्योंकि माल की सुचारु आवाजाही होगी। क्रिसिल के विश्लेषण के अनुसार, GST गैर-थोक वस्तुओं (रेलवे द्वारा परिवहन की जाने वाली प्राथमिक थोक वस्तुओं के अलावा सभी वस्तुओं - कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, इस्पात, खाद्यान्न, उर्वरक) का उत्पादन करने वाली कंपनियों की रसद लागत को 20% तक कम कर सकता है।

## 10.3 3. नए व्यवसायों के लिए उच्च छूट

GST कंपोजिशन स्कीम नामक एक वैकल्पिक योजना भी पेश करता है, जो 30,000 डॉलर से 77,000 डॉलर (20 से 50 लाख रुपये) के बीच कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायों को कम करों का भुगतान करने का अधिकार देता है। इससे नवस्थापित व्यवसायों को कर के बोझ से राहत मिलेगी। इससे पहले, मूल्य वर्धित कर (VAT) संरचना के अनुसार, 7000 डॉलर (5 लाख रुपये) से अधिक के कारोबार वाले किसी भी व्यवसाय को वैट पंजीकरण प्राप्त करना था, GST के तहत पंजीकरण के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 30,000 डॉलर (20 लाख रुपये) कर दिया गया है, इस प्रकार कई स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के संस्थापकों को राहत प्रदान की गई है।

## 10.4 वित्तीय समावेशन

दीर्घकाल में GST से अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन संभव होगा। स्टार्टअप समुदाय के डिजिटल बुक की ओर पलायन करने के साथ-मौजूदा प्रक्रियाओं को बनाए रखने और अनुकूलित करने के साथ, वे भारत और विदेशों में बैंकों और निवेशकों द्वारा क्रेडिट सुविधाओं के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए बेहतर होंगे। इसके अलावा, फिनटेक संगठनों को डिजिटल रूप से युवा और तेजी से बढ़ते उद्यमों तक आसान पहुंच मिलेगी और उन्हें अपने व्यवसायों को स्थापित करने और विकसित करने के लिए आवश्यक क्रेडिट लाइन का विस्तार करना होगा।

इन लाभों के अलावा, क्रिसिल की एक विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि GST देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने में एक जटिल भूमिका निभाने जा रहा है। यह सरकार और करदाताओं दोनों के लिए जीत की स्थिति बनाता है। अटकलों और शुरुआती शुरुआती समस्याओं के बावजूद, GST एक आशाजनक क्रांतिकारी सुधार प्रतीत होता है जो कम लागत और सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करता है, ऐसे तत्व जो सफलता की गारंटी देने, उत्साह बढ़ाने और भारतीय उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हैं।

यहां कुछ प्रमुख समग्र लाभ दिए गए हैं जो GST ने इसके कार्यान्वयन के साथ लाए हैं:

- पारदर्शी कराधान प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जो अब तक के सभी अप्रत्यक्ष करों का प्रतिस्थापन है, GST सरकार द्वारा सतह पर लाया गया सबसे प्रभावी सुधार है। GST के साथ, प्रत्येक ग्राहक को माल और सेवाओं को खरीदने पर भुगतान की जाने वाली सटीक कर राशि का पता चल जाएगा, और जनता के बीच राहत की भावना होगी।
- GST लागू होने के साथ, कोई छिपा हुआ कर नहीं होगा, क्योंकि पंजीकृत खुदरा विक्रेताओं पर कोई अतिरिक्त कराधान गाड़ी नहीं लगाई जाएगी और व्यवसायों के संचालन की लागत भी काफी हद तक कम हो जाएगी।
- पूर्ण भारतीय बाजार एकीकृत होगा और इसे एक संयुक्त व्यापार मंच के रूप में देखा जा सकता है, जो विदेशी निवेशकों को आने के लिए प्रोत्साहित करेगा।



- GST आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा जिसके परिणामस्वरूप देश की कुल संपत्ति में वृद्धि होगी।
- गैस, तेल, पानी, बिजली आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर कम हो जाएगी।
- भारत में, GST दोहरी प्रणाली का पालन करेगा, जिसमें केंद्रीय GST और राज्य GST समान विनिर्माण लागत लेंगे और केवल बिक्री के बिंदु पर एकत्र किए जाएंगे। बदले में यह उपभोक्ताओं को समाप्त करने में मदद करेगा, क्योंकि कीमतें कम हो जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप माल की खपत को बढ़ावा मिलेगा जो उद्योगों के लिए एक प्रमुख उत्थान है।



## 11 देश में GST से पहले और बाद में जमीनी अंतर क्या हैं?

प्रत्येक राष्ट्र के पास कुछ ऐतिहासिक क्षण होते हैं जो उसके इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वहां कुछ भी वैसा न रहे। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए और आम आदमी को एक ऐसा जीवन जीने के लिए पंख दिए जो सक्षम है। इसके परिणामस्वरूप देश के अब प्रसिद्ध विशाल मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जो राष्ट्र के आर्थिक विकास में स्वस्थ रूप से योगदान दे रहा है।

1 जुलाई, 2017 से GST का कार्यान्वयन ऐसे मील के पत्थरों में से एक है जो बदल रहा है कि हम भारतीय कैसे व्यापार करते हैं और कैसे कराधान नीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। भले ही 1990 के दशक के सुधारों ने वित्तीय स्वतंत्रता लाई, लेकिन व्यवसाय करने के तरीके में बहुत बदलाव नहीं आया और वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। बहुत सारी अनैतिक प्रथाएं व्यापार करने का हिस्सा थीं और करों से बचने और काला धन पैदा करने के लिए नए और नए तरीके तैयार किए गए थे GST का परिचय करों का भुगतान करने में एकरूपता लाने, संदिग्ध व्यापार लेनदेन को मिटाने और देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने में पहला कदम है।

बारीकियों में जाने से पहले, आइए GST लॉन्च होने के बाद से हुए कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों को देखें:

- समावेशिता:** चूंकि GST इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार पर काम करता है और दिशानिर्देश प्रत्येक व्यवसाय को 20 LAKH रुपये के वार्षिक कारोबार के साथ इंगित करते हैं। GST का हिस्सा बनने के लिए, इसने यह सुनिश्चित किया है कि लगभग हर व्यावसायिक इकाई ने खुद को पंजीकृत किया है। कुल 72.33 लाख करदाताओं में से 58.53 लाख करदाता GSTN में स्थानांतरित हो गए हैं और शेष ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।
- संगठित व्यवसाय:** कानूनी चालान बनाने के बजाय व्यापार करने की कुख्यात 'पारची' प्रणाली एक स्वाभाविक मौत मर रही है। केईराना स्टोर से लेकर अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक, हर कोई एक-दूसरे की कर जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी है और हमेशा कर-भुगतानकर्ता श्रृंखला का हिस्सा बन रहा है। अपराधों की कंपाउंडिंग करने वाले माल को जब्त करने से पहले
- दक्षता:** भले ही शुरुआत में नए कर सुधार के बारे में बहुत सारी आशंकाएं थीं, लेकिन प्रौद्योगिकी ने इसे एक आसान और कुशल प्रक्रिया बना दिया है। मैनुअल काम कम कर दिया गया है और सब कुछ ऑनलाइन किया जा सकता है। शुरुआती परेशानियों और समय पर सरकार के हस्तक्षेप के बाद, GST के लिए रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है ताकि रिटर्न दाखिल करना आसान हो सके।
- संगठित डेटा और पारदर्शिता:** किसी उत्पाद / सेवा के उत्पादन में प्रत्येक भागीदार अब ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा डेटा ऑनलाइन संग्रहीत किया जाता है और चीजों को ट्रैक करना आसान बनाता है, बल्कि यह पारदर्शिता भी लाता है। अब, सूचना के चालान या दोहराव में कोई "बैक-डेटेड" परिवर्तन नहीं हो सकता है।
- राजस्व:** GST अधिक राजस्व पैदा करने की दिशा में एक कदम है और मजबूत कर फाइलिंग और ट्रैकिंग तंत्र केवल यह सुनिश्चित करता है। यह पूरी श्रृंखला में किसी भी लीक को रोकता है जिसके परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित करके उच्च राजस्व प्राप्त होता है कि हर कोई करों का खामियाजा भुगतान करने वाले कुछ चुनिंदा उद्योगों के बजाय अपने हिस्से के करों का भुगतान करता है। इसका प्रमाण वित्त वर्ष 2016-17 की इसी अवधि की तुलना में 5 अगस्त तक अग्रिम व्यक्तिगत



आयकर संग्रह में 41.79 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अलावा, स्व-मूल्यांकन कर (एसएटी) के तहत व्यक्तिगत आयकर वित्त वर्ष 2016-17 में इसी अवधि की तुलना में 34.25% की दर से बढ़ा

6. अल्पावधि परिवर्तन प्रारंभ में, कीमतें बढ़ती प्रतीत होती हैं और यहां तक कि अनुपालन की लागत उन लोगों के लिए अधिक होती है जिन्होंने कभी रिटर्न या कर दाखिल नहीं किया है। हालांकि, लंबे समय में, कीमतों में कमी आना तय है और पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा

ये व्यापक स्तर के परिवर्तन हैं जो देश में GST लॉन्च के बाद हुए हैं, हालांकि, जमीनी स्तर के परिवर्तनों को समझने के लिए, हमें विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को देखने की आवश्यकता है

1. 500 रुपये से अधिक कीमत वाले किसी भी फुटर पर अब 14.41% से 18% की GST दर लगेगी, जबकि 500 रुपये से कम कीमत वाले जूते पर 5% की दर से GST दर लगेगी, जबकि तैयार कपड़ों की बात आती है, तो दर 18.16% से घटकर 12% हो गई है, जिससे वे सस्ते हो गए हैं।
2. **टैक्सी की सवारी:** ऑनलाइन कैब बुक करने पर अब 6% के बजाय 5% की दर से टैक्स लगेगा। यह थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन लंबी और नियमित यात्राओं के लिए, बचत पर्याप्त हो सकती है।
3. **ट्रेन टिकट:** लोकल ट्रेन टिकट या स्लीपर क्लास की चर्बी समान रहेगी। GST में प्रभावी कर की दर 4.5% से बढ़कर 5% हो गई है, लेकिन व्यावसायिक यात्री इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं और खर्चों को कम कर सकते हैं। हालांकि, फर्स्ट क्लास में सफर करने वालों को ज्यादा किराया देना होगा।
4. **सिनेमा टिकट:** 100 रुपये से कम कीमत वाले मूवी टिकट पर अब 18% की दर से GST लगेगा, लेकिन 100 रुपये से अधिक की कीमत वाले टिकटों पर 28% की दर से GST लगेगा।
5. **जीवन बीमा पॉलिसियां:** जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा पॉलिसियों पर GST घटक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि टर्म एंड एंडोमेंट के लिए पॉलिसी पर प्रीमियम में अच्छी वृद्धि हुई है।
6. **आभूषण:** सोने पर आभूषणों पर GST बढ़ा दिया गया है, 3% का GST है और मेकिंग चार्ज पर 5% का GST लगेगा पहले सोने पर 2% लगाया जाता था।
7. **रियल एस्टेट:** अभी भी निर्माण के दौर से गुजर रही संपत्तियां संपत्तियों में तैयार - स्थानांतरित करने की तुलना में सस्ती हो गई हैं। भले ही निर्माणाधीन संपत्ति पर GST 18% है, प्रभावी दर 12% हो जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल्डर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और समग्र लागत को कम करने और खरीदारों को लाभ देने में सक्षम है।
8. **होटल स्टे:** हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को GST से फायदा होगा क्योंकि 1000 रुपये से कम के कमरे के किराए को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि, 5000 रुपये से अधिक के कमरे के टैरिफ के लिए, GST 28% पर लगाया जाएगा।
9. कारें: हाइब्रिड कारों को छोड़कर, अधिकांश कारें थोड़ी सस्ती हो गई हैं और उनकी बढ़ती बिक्री के बारे में सभी कारों पर समान रूप से 28% GST लागू होता है, चाहे उनका मेक, इंजन या मॉडल कुछ भी हो। हालांकि, कार सेगमेंट के आधार पर 1%, 3% या 15% की दर से इस 28% के अलावा अतिरिक्त उपकर लगाया जाता है।
10. सरकार ने अलग-अलग रेस्तरां के लिए अलग-अलग GST दरों को चिह्नित किया है एसी रेस्तरां और 5-सितारा होटलों के लिए, GST 18% की दर से लिया जाएगा। नॉन एसी रेस्तरां के लिए GST 12 प्रतिशत तय किया गया है। हालांकि, 50 लाख रुपये से कम के वार्षिक कारोबार वाले छोटे ढाबों, होटलों और रेस्तरां के लिए GST 5% तय किया गया है।
11. **केबल सेवाओं और डीटीएच:** केबल सेवाओं और डायरेक्ट-टू-होम कनेक्शन के लिए भुगतान में कमी आई है क्योंकि GST अब 18% है। मनोरंजन कर सहित पहले कर 15% के सेवा कर के अलावा 10-30% की सीमा में थे।

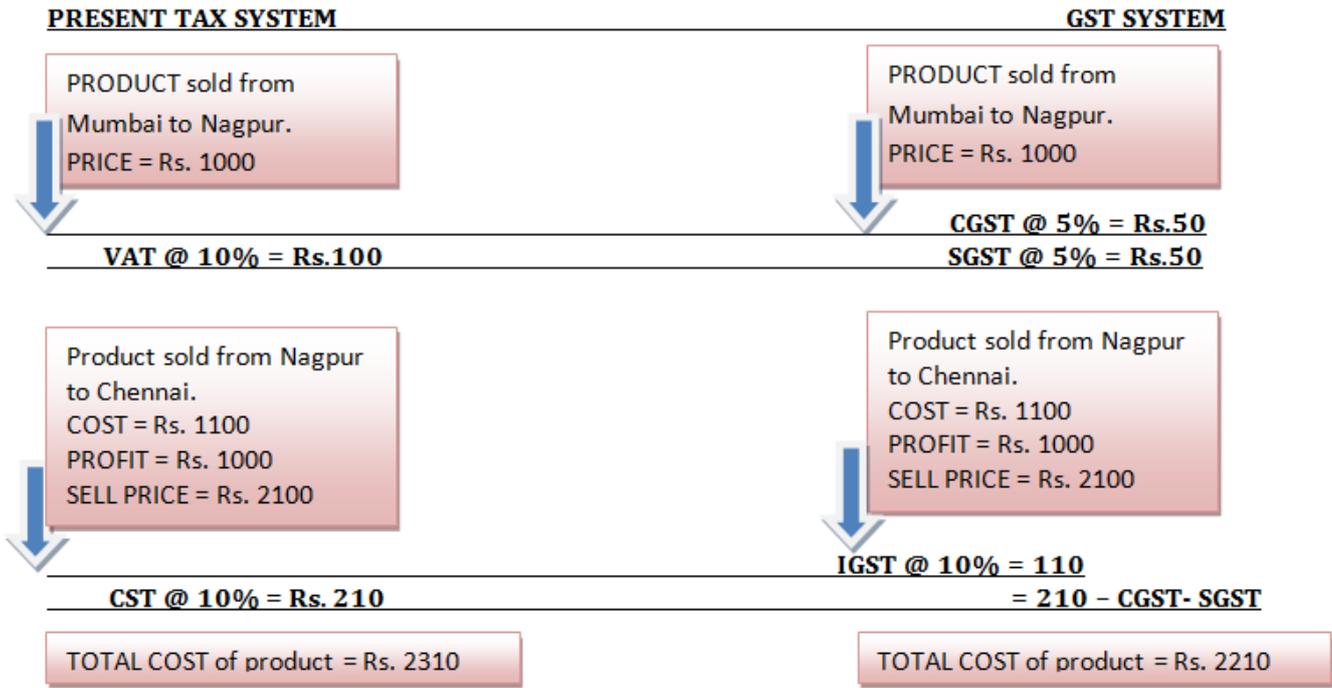


12. **मनोरंजन पार्क:** मनोरंजन पार्कों में आनंद लेना महंगा हो गया क्योंकि GST को 15% की पहले की कर दर से 28% तय किया गया है।

भारतीय कराधान प्रणाली में अपेक्षित सभी सकारात्मक परिवर्तनों के अलावा, GST लागत को कम करने जा रहा है और सभी के लिए जीवन को आसान बना देगा।

GST से पहले और बाद में जमीनी मतभेदों का एक स्पष्ट उदाहरण यहां दिया गया है:

तुलना GST से पहले और बाद में मुंबई से नागपुर तक बेचे जा रहे उत्पाद के लिए है:



लागत और करों का उपरोक्त प्रवाह स्पष्ट रूप से अंतिम उपभोक्ता को लागत में कटौती की व्याख्या करता है। यह सभी उत्पादों पर लागू होता है।

इसके अलावा, यदि आप किसी रेस्तरां या कैफे में जाते हैं तो वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो गया है। आपके बिल का ब्रेक-अप GST से पहले की तुलना में अलग दिखेगा।

एक जुलाई, 2017 से लागू हुए GST में 17 अप्रत्यक्ष कर और 22 उपकर समाहित हो गए हैं जो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दरों पर थे।

इससे पहले एक सामान्य रेस्तरां बिल में रेस्तरां मालिकों द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क के अलावा राज्य (वैट / बिक्री कर) और केंद्र सरकार (सेवा कर) द्वारा वसूले जाने वाले करों की अधिकता दिखाई देती थी।

GST से पहले का रेस्तरां बिल इस तरह दिखता था:



<b>XYZ Restaurant</b>	
<i>Particulars</i>	<i>Price</i>
Shahi Paneer	300
Butter Naan	50
Cold Drinks	50
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>
Service Charge @ 10%	40
Service Tax @ 14%	24.64
KKC @ 0.5%	0.88
SBC @ 0.5%	0.88
VAT @ 14.5%	58
<b>TOTAL AMOUNT PAYABLE</b>	<b>524.4</b>

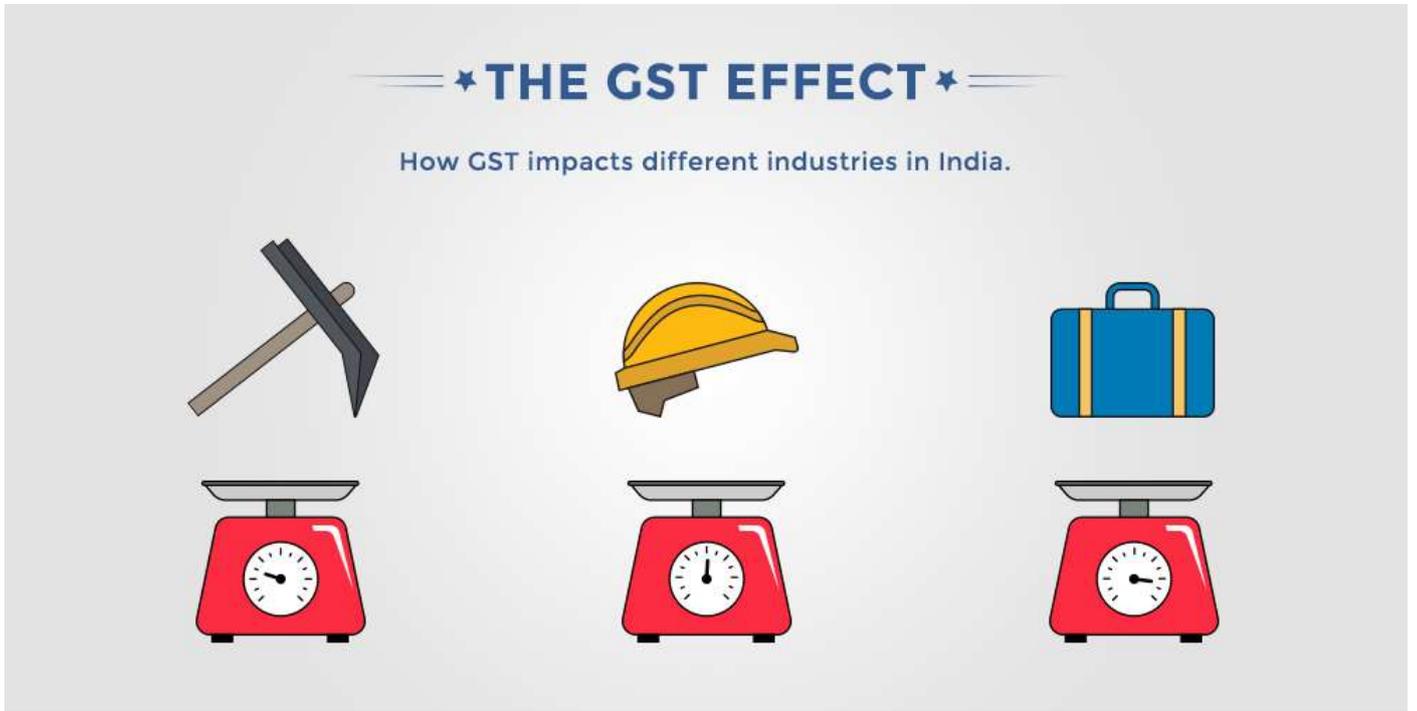
<b>XYZ Restaurant</b>	
<i>Particulars</i>	<i>Price</i>
Shahi Paneer	300
Butter Naan	50
Cold Drinks	50
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>
Service Charge @ 10%	40
CGST @ 9%	39.6
SGST @ 9%	39.6
<b>TOTAL AMOUNT PAYABLE</b>	<b>519</b>

बिलों में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जाता है।

इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि GST से पहले और बाद में अर्थव्यवस्था की स्थिति के बीच बहुत अंतर है और इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता है। आम आदमी ने कमोबेश बदले हुए कराधान परिदृश्य के साथ समायोजन किया है और अधिक सकारात्मक परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ते हुए, देश में हर किसी के पास इस अनुकूल कर व्यवस्था के फल का आनंद लेने का समान अवसर होगा।



# 12 GST भारत में विभिन्न उद्योगों और ट्रेडों को कैसे प्रभावित करता है?



देश में GST के कार्यान्वयन ने व्यापार और उद्योगों के सभी पहलुओं को कवर किया है। कुछ भी इससे अछूता या अप्रभावित नहीं रहता है और बदले में आम आदमी को कई तरह से प्रभावित कर रहा है।

इस विषय पर बेहतर पकड़ पाने के लिए, आइए विभिन्न क्षेत्रों और उनमें से प्रत्येक पर GST के प्रभाव पर एक नज़र डालें:

1. **एनजीओ और चैरिटेबल ट्रस्ट:** मोटे तौर पर, जब तक एक एनजीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट मुफ्त सेवाएं प्रदान कर रहा है और ऐसी सेवाओं के लिए पूर्व-निर्धारित मानदंडों को पूरा कर रहा है, तब तक वे GST से बाहर रहेंगे। हालांकि, यदि वे योग गतिविधियों या प्रशिक्षण शिविरों जैसी किसी भी सेवा के लिए पैसे लेते हैं या कोई सामान बेचते हैं, तो वे GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
2. **किराया:** यदि आपने आवासीय उद्देश्यों के लिए अपने परिसर को किराए पर दिया है, तो आपको GST से छूट दी जाएगी, इसके अलावा, यदि संपत्ति वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए पट्टे पर दी गई है, तो GST लागू होगा, लेकिन केवल तभी जब किराए से वार्षिक आय 1,000 रुपये की सीमा को पार कर जाती है। 20 लाख रुपये और उससे अधिक।
3. **शिपिंग शुल्क:** GST को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, शिपिंग शुल्क व्यक्तिगत उत्पादों पर लागू GST के अनुसार लागू होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पाद पर 5% का GST लगता है, तो शिपिंग चार्ज पर भी 5% का GST लगेगा। इसी तरह, यदि माल पर GST 18% है, तो शिपिंग शुल्क भी समान होगा। साथ ही दूध जैसे परिवहन के दौरान कुछ उत्पादों को GST से बाहर रखा जाता है। चावल, कृषि उपज, जैविक खाद, डीईएफ और एनसी उपकरण और इसी तरह।
4. GST लागू होने से पहले सोने पर 1% सेवा कर और 1% वैट के रूप में कर, कुल 2% था। हालांकि, GST के बाद, सोने पर लागू कर अब 3% है! जब सोने के निर्माण शुल्क की बात आती है, तो GST लागू 5% है
5. **GST के तहत गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (जीटीए):** जीटीए कोई भी व्यक्ति है जो सड़क के माध्यम से माल परिवहन के लिए सेवाएं प्रदान करता है और एक खेप नोट जारी करता है। खेप नोट जारी करना यहां जीटीए माने जाने के लिए सबसे



महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि माल पर ग्रहणाधिकार ट्रांसपोर्टर को हस्तांतरित किया गया है, जो माल प्राप्तकर्ता को इसकी सुरक्षित डिलीवरी तक माल के लिए जिम्मेदार होगा। GST जीटीए पर लागू होता है लेकिन अलग-अलग उत्पादों में अलग-अलग होता है। यह आवश्यक वस्तुओं और अधिकारियों द्वारा चिह्नित अन्य उत्पादों के लिए शून्य से लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बिना 5% और ITC के साथ 12% तक है।

6. **कैब सर्विसेज:** बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 फीसदी GST लागू होने के बाद किराए में कमी आई है। यह रेडियो टैक्सी और एसी बसों पर लागू होगा जबकि मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो रिक्शा को GST से छूट दी गई है।
7. **आईटी सेक्टर: प्रिंटर, फोटो कॉपी, फैंक्स मशीन और स्याही कारतूस** जैसे आईटी क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर 18% के बजाय 28% GST लगेगा। सॉफ्टवेयर सेवाओं पर भी 18 प्रतिशत GST लगेगा जबकि पहले 15 प्रतिशत सेवा कर लगता था। इस सब ने आईटी उद्योग के लिए लागत में वृद्धि की है, लेकिन GST के बारे में अच्छी चीजों में से एक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) है जो माल और सेवाएं बेचने वाले आईटी व्यापारियों के लिए उपलब्ध है।
8. **वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात:** वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात को शून्य-रेटेड आपूर्ति माना जाता है और इसलिए GST किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लागू नहीं होगा। इससे निर्यात उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी मूल्य रखने में मदद मिलती है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का एक आसान तंत्र है और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है।
9. **हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री:** GST लागू होने का इस इंडस्ट्री पर मिला-जुला असर पड़ा है। चूंकि यह एक कर है, इसलिए बिल तैयार करते समय, करों की गणना और उपभोक्ताओं के लिए स्पष्टता के दौरान एक प्रशासनिक आसानी होती है। साथ ही उद्योग को उनके इनपुट पर पूरा टीटीसी मिलेगा। हालांकि, कुल लागत थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि वैश्विक पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए भारतीय आतिथ्य के लिए 5% की मांग के खिलाफ GST 18% लगाया गया है।
10. **बीमा और बैंकिंग:** बदली हुई कर संरचना के कारण GST व्यवस्था लागू होने के बाद बीमा प्रीमियम में वृद्धि हुई है। बैंकिंग लेनदेन भी महंगा हो गया है क्योंकि पहले 15% के बजाय 18% GST शुल्क है।
11. **कोयला:** पहले कोयले पर कर विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के करों को शामिल करते हुए 12% था। अब, GST ने कर को 5% तक कम कर दिया है। हालांकि, कुछ स्थानीय कर, पर्यावरण शुल्क और कुछ अन्य छिपे हुए शुल्क अभी भी लागू हैं जिन्हें GST में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, शुद्ध कटौती करों में फ्लैट 7% के बजाय 2-3% की सीमा में है। लेकिन यह 2-3% कर कटौती देश में कोयले की भारी खपत को देखते हुए भी बड़े पैमाने पर है और उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर रही है।
12. **घरेलू उपकरण और विद्युत मशीनरी: फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशनर और जैसे घरेलू उपकरण** GST के बाद थोड़े महंगे हो गए हैं क्योंकि दर 28% तय की गई है। जो पहले की तुलना में 2-3% अधिक है। हालांकि, वाणिज्यिक विद्युत मशीनरी की लागत तटस्थ रहने की उम्मीद है।
13. **लोहा और इस्पात:** GST के तहत विभिन्न उत्पादों पर अलग-अलग कर लगाए जाते हैं। घरेलू बर्तन सस्ते हो गए हैं जबकि बारबेक्यू सेट महंगे हो गए हैं। नल, नल आदि जैसे स्वच्छता आइटम। यह भी महंगा हो गया है, जबकि रेल पटरियां बिछाना तटस्थ रहा है। अल्पावधि में, इस क्षेत्र के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी एक है। संक्रमण के दौर के कारण उद्योग में अधिक लागत शामिल है, लेकिन लंबे समय में, GST फायदेमंद होगा।



14. **तंबाकू उद्योग:** तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के उपयोग से संबंधित स्वास्थ्य चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, GST लागू 28% है और इस दर के ऊपर अतिरिक्त उपकर लगाया जाता है। कीमतें बढ़ गई हैं और उम्मीद है कि यह तंबाकू के उपयोग के लिए एक निवारक के रूप में साबित हो सकता है। F3 FA F5 FE
15. **एयर फेयर:** इकोनॉमी टिकट पर GST को 5: 6% से घटाकर 5% कर दिया गया है जिसने अर्थव्यवस्था की कीमतों को प्रभावी ढंग से कम कर दिया है। हालांकि बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए टैक्स 8.4 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो गया है।
16. **सीमेंट उद्योग:** पहले, कर 24-25% था, लेकिन GST 28% की फ्लैट दर पर लागू होगा, यह महंगा है, लेकिन GST शासन के तहत दिए जाने वाले विभिन्न अन्य लाभों के कारण लंबे समय में सीमेंट उद्योग के लिए संचालन की लागत कम हो जाएगी।
17. **मनोरंजन उद्योग:** यह मनोरंजन उद्योग के लिए एक मिश्रित बैग है क्योंकि यह राज्य और उसमें लागू स्थानीय करों पर निर्भर करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण मूवी हॉल, पार्क आदि के मालिकों को लाभ होगा। इसके अलावा, उच्च मनोरंजन कर वाले राज्यों के लिए GST अच्छा होगा क्योंकि टिकट की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन जिन राज्यों में मनोरंजन कर पहले से ही कम है, उनकी कीमतों में वृद्धि देखी जा सकती है।
18. **रेल परिवहन:** GST लागू 4.5% की पहले की दर की तुलना में अब 5% है। इससे किराये में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन व्यावसायिक यात्री इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह, ट्रेन से ले जाया जा रहा सामान भी अपनी GST देनदारी को कम करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए दावा कर सकता है।
19. **जीवन रक्षक दवाएं और अन्य फार्मा:** GST 5%, 12% और शून्य के तीन ब्रैकेट के तहत लगाया गया है। 12 प्रतिशत से कम ब्रैकेट में आने वाली दवाओं की कीमतों में पहले की कीमतों की तुलना में लगभग 2.30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जबकि 5 प्रतिशत ब्रैकेट से कम उम्र की दवाओं में अंतिम मूल्य में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।
20. **फर्नीचर निर्माण:** चाहे वह लकड़ी का फर्नीचर हो या लोहा और स्टील। हालांकि, दोनों के बीच, लकड़ी के फर्नीचर निर्माताओं के लिए GST अधिक फायदेमंद है, जिन्होंने अपनी पीआर कीमतों में वृद्धि की है। उन पर लागू कर के कम प्रभाव के कारण।
21. **फल और सब्जियां:** ताजे फलों और सब्जियों पर कोई GST नहीं लगता है, लेकिन सूखे मेवे और फलों और सब्जियों से तैयारी पर अब 12% और 18% शुल्क लगाया जाता है, जो पहले 5% था, जिससे वे महंगे हो जाते हैं।
22. **वस्त्र निर्माता:** जबकि कपड़ा उद्योग पर कर की दर बढ़ा दी गई है और कपास मूल्य श्रृंखला के तहत लाभ हटा दिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय में इस क्षेत्र के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हैं GST फायदेमंद साबित होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योग अधिक संगठित और विनियमित होगा।
23. **जॉब वर्क:** GST ने जॉब वर्क की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रक्रिया के तहत दावा किए गए किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलट दिया जा सकता है यदि निर्धारित पैरामीटर पूरे नहीं होते हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषित समयसीमा के साथ आपूर्तिकर्ता और अनुबंध कार्यकर्ता से क्या आवश्यक है, इस पर अधिक स्पष्टता है।
24. **आयात और आयातक:** GST ने काउंटरवेलिंग इयूटी (सीवीडी) और स्पेशल एडिशनल इयूटी (एसएडी) को समाहित कर दिया है। हालांकि, बेसिक कस्टम इयूटी (बीसीडी) GST का हिस्सा नहीं है और मौजूदा कानूनों के अनुसार वसूला जाएगा।
25. **हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर:** कुल 8 अलग-अलग टैक्स को एक ही टैक्स में समाहित किया गया है।



26. GST ने आपूर्ति श्रृंखला को तर्कसंगत बनाकर इस क्षेत्र की परिचालन दक्षता में भी सुधार किया है। GST के परिणामस्वरूप विनिर्माण लागत कम होने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की लागत भी कम हो रही है।
27. **थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता:** ये व्यापारी ज्यादातर कराधान व्यवस्था के बाहर काम करते थे और जिसे काला धन कहा जाता है। हालांकि, GST कार्यान्वयन ने उन्हें कर संरचना का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया है और करों से बचने या कम कटौती करने की उनकी क्षमता बड़े पैमाने पर कम हो जाएगी।
28. **फ्रीलांसर:** यह फ्रीलांसरों के लिए एक मिश्रित बैग है। जबकि GST उन्हें संगठित होने में मदद करेगा, 18% की GST दर 15% की पिछली कर दर से अधिक है और अनुपालन मुद्दों को भी लागू करेगी।
29. **एफएमसीजी सेक्टर:** पहले इस सेक्टर पर लागू टैक्स रेट 22-24% के दायरे में था, लेकिन GST लागू होने के बाद यह घटकर औसतन 18-20% रह गया है। कुछ उत्पाद महंगे हो गए हैं, और कुछ सस्ते हो गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर, एक क्षेत्र के रूप में इसे GST से लाभ हुआ है।
30. **कार्य अनुबंध:** पहले के परिदृश्य में, सेवाओं और वस्तुओं के विभिन्न घटकों के साथ कार्य अनुबंध काफी जटिल था और कराधान काफी जटिल हो गया था। हालांकि, GST ने इस तरह की सभी अस्पष्टताओं को दूर कर दिया है और अब कार्य अनुबंधों को विशुद्ध रूप से सेवा के रूप में माना जाएगा और कर तदनुसार लागू होंगे।
31. **ऑटोमोबाइल क्षेत्र:** GST के परिणामस्वरूप करों में कमी आई है और साथ ही जटिलताओं के कारण लगाए जा रहे कई करों में कमी आई है। इसका असर अब बिक्री और मांग में वृद्धि के साथ आसानी से दिखाई दे रहा है।
32. **लघु और मध्यम उद्यम:** इस क्षेत्र को सबसे लंबे समय तक काफी हद तक नजरअंदाज किया गया था, लेकिन GST के साथ, इस क्षेत्र के पास अब डेटा तक पहुंच होगी जिसका उपयोग बेहतर क्रेडिट प्राप्त करने, परिचालन क्षमता में सुधार, नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने, ग्राहक संबंधों में सुधार करने और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने के लिए किया जा सकता है।
33. **ईकॉमर्स प्लेयर्स:** चाहे वह अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केटप्लेस हों या इन मार्केटप्लेस पर हजारों विक्रेता हों, GST अनुपालन उनकी लागत और जटिलता को बढ़ाएगा। हालांकि, लंबे समय में, न केवल GST उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार है, बल्कि सभी खिलाड़ियों के लिए पारदर्शी स्तर का अवसर भी प्रदान करता है और इसके परिणामस्वरूप लागत को कम करके व्यवसाय में वृद्धि और लाभ होता है।
34. **लॉजिस्टिक्स उद्योग:** GST की शुरुआत के साथ इस क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है क्योंकि माल की आवाजाही में वृद्धि हुई है, कंपनियों की भंडारण आवश्यकताओं में कमी आई है और विभिन्न राज्यों में प्रवेश के विभिन्न बिंदुओं पर कई कर समाप्त हो गए हैं। GST निश्चित रूप से इस उद्योग के लिए एक वरदान के रूप में आया है।
35. **खाद्य सेवा और रेस्तरां उद्योग:** शुरू में एसी रेस्तरां के लिए GST 18% लगाया गया था, लेकिन अब इसे 12% तक लाया गया है। कुल मिलाकर GST का असर उपभोक्ताओं के साथ-साथ रेस्तरां मालिकों दोनों पर पूरी तरह से करों में कमी के कारण सकारात्मक रहा है, लेकिन अंतिम बिल की गणना की सादगी के कारण भी।
36. **रियल एस्टेट सेक्टर:** रेडी-टू-मूव-इन संपत्तियां GST से बाहर हैं, लेकिन निर्माणाधीन संपत्तियों को करों की एकरूपता के कारण लाभ होगा। इसके अलावा, अपारदर्शी संचालन से ग्रस्त क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का बड़ा प्रभाव पड़ता है।
37. **विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड):** जबकि कई करों को GST के तहत समाहित कर दिया गया है, एसईजेड से की गई आपूर्ति पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) वसूला जा रहा है।
38. **बैंक और एनबीएफसी:** यह क्षेत्र अभी भी पेश किए जा रहे मानदंडों पर और स्पष्टता और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अब तक अनुपालन मुद्दों के कारण पूरा संचालन जटिल हो गया है।



39. **स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक ट्रांसफर:** कर योग्य घटना को बिक्री से आपूर्ति में स्थानांतरित करने के साथ GST के तहत परिणामस्वरूप स्टॉक ट्रांसफर पर कर लगाया जाएगा और यह एक मिश्रित बैग होगा जिसमें कुछ उद्योगों को खरीद में लागत बचत से लाभ होगा और कुछ उद्योगों को उच्च लागत का भुगतान करना होगा।
40. **स्टार्ट-अप:** GST स्टार्ट-अप को विभिन्न तरीकों से लाभान्वित कर रहा है। उनमें से एक पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए 20 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा है, जबकि पिछली व्यवस्था में इस क्षेत्र के लिए न्यूनतम सीमा 5 लाख रुपये थी। साथ ही 20 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच टर्नओवर होने पर कम टैक्स का प्रावधान है। कुल मिलाकर GST स्टार्ट-अप के लिए वरदान है।
41. **कृषि क्षेत्र:** हालांकि इस क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले कुछ उत्पादों पर करों में वृद्धि की गई है, लेकिन लंबे समय में आर्थिक संचालन और एकल राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के कारण इस तरह की बढ़ी हुई लागत कम हो जाएगी।

जैसा कि काफी स्पष्ट है, GST एक क्रांतिकारी कर व्यवस्था रही है जो अर्थव्यवस्था पर बेहद सकारात्मक प्रभाव दिखा रही है और अगले 1-2 वर्षों में, हर कोई इस व्यापार के अनुकूल कानून का लाभ उठाएगा।

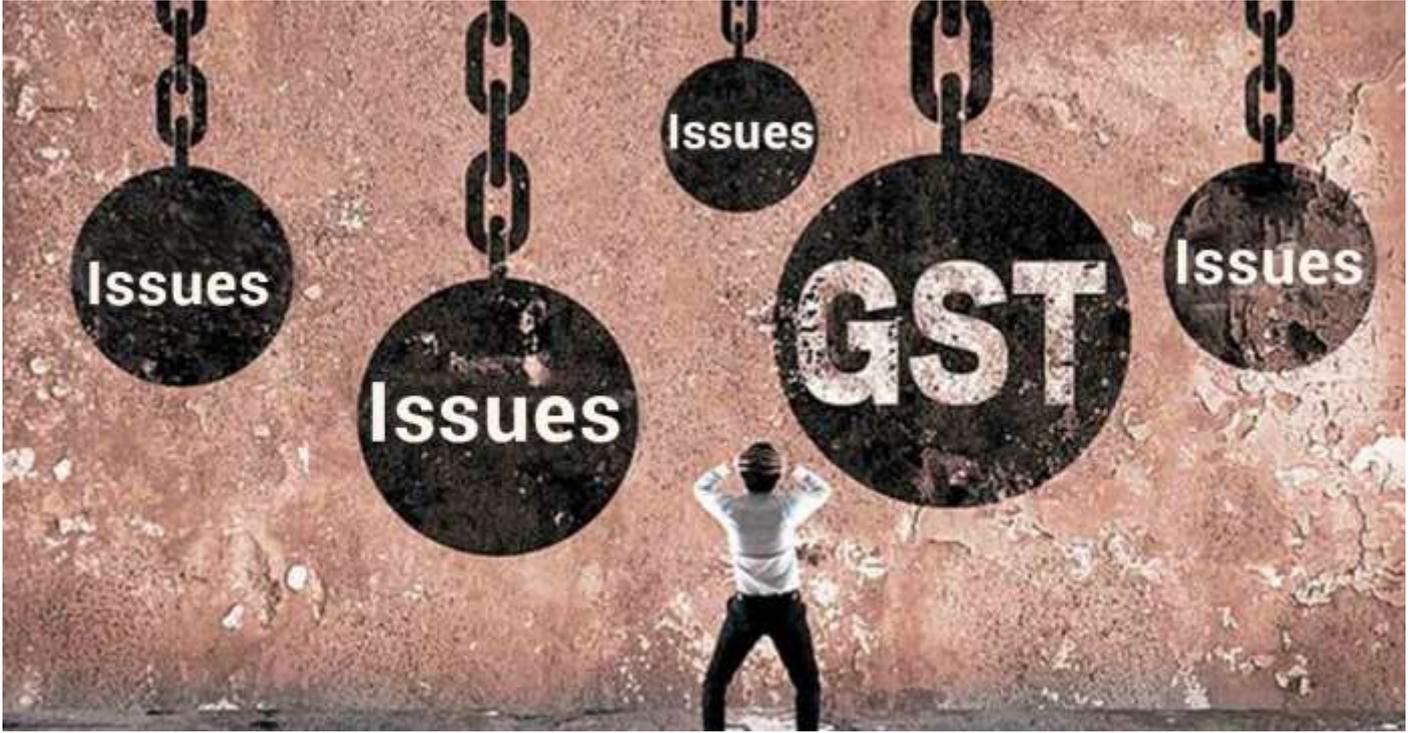
#### Impact On Different Sectors

	Impact of Tax Rate	Inventory Management	Logistics	For Organised Players	Overall Impact
Cement	😊	😊	😊	😊	😊
Consumer Durables	😊	😊	😊	😊	😊
FMCG	😊	😊	😊	😊	😊
Pharmaceuticals	😊	😊	😊	😐	😊
Automobile	😊	😊	😊	😊	😊
Cap Goods	😊	😐	😊	😐	😊
IT/ITES	😊	😐	😊	😐	😊
Media	😐	😐	😐	😐	😐
BFSI	😊	😐	😐	😐	😊
Textile	😐	😊	😊	😊	😐
Building /Home Material	😊	😊	😊	😊	😐
Telecommunications	😐	😐	😐	😐	😐
Metals	😐	😐	😊	😐	😊
Multiplex	😊	😐	😐	😐	😊

😊 Positive    😐 Neutral    😐 Negative



## 13 GST आपके व्यक्तिगत वित्त को कैसे प्रभावित करता है?



आपके व्यक्तिगत वित्त पर GST का प्रभाव मिश्रित होगा।

कई वस्तुओं के लिए, करों में कमी है। यह मुख्य रूप से है क्योंकि सरकार ने सख्त मुनाफाखोरी विरोधी उपाय किए हैं और व्यवसायों को कर छापे की चेतावनी दी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को लाभ दें।

### 13.1 खाद्य पदार्थ

ज्यादातर खाद्य पदार्थों को GST से छूट दी गई है। वे पुरानी व्यवस्था के तहत कर योग्य भी नहीं थे, इसलिए कीमतें काफी हद तक तटस्थ होने की उम्मीद करती हैं।

- अनाज
- ताजे फल और सब्जियां (जमे हुए या संसाधित के अलावा)
- मांस (जमे हुए राज्य के अलावा और यूनिट कंटेनरों में रखा गया)
- मछली (जमी हुई या संसाधित नहीं)
- सामान्य नमक

इस बात को लेकर भ्रम था कि पैकेट में बिकने वाला गेहूं, आटा, चावल उच्च कर के दायरे में होगा या नहीं। राजस्व सचिव ने स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकृत ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने वाले लोगों पर 5% का उच्च कर लगता है। तो, आपके स्थानीय किराने से आपके सामान्य अनब्रांडेड पैकेट अभी भी 0 रेटेड होंगे।

प्रसंस्कृत भोजन का प्रभाव अलग-अलग होगा। GST के तहत कॉर्न फ्लेक्स जैसी वस्तुओं में कमी आएगी जबकि पेस्ट्री और केक में बढ़ोतरी होगी।



## 13.2 घरेलू सामान

हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू सस्ता मिलने की उम्मीद है।

डिजिट की दर में वृद्धि और कपड़े धोने के स्थानों की सेवाओं पर कर में वृद्धि के कारण कपड़े धोने की लागत में वृद्धि होगी।

अन्य बुनियादी वस्तुओं जैसे कुमकुम, अल्टा, पूजा सामग्री, चूड़ियों (कीमती धातुओं से बनी वस्तुओं को छोड़कर) को GST से छूट दी गई है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। हालांकि, 28% के नीचे आने वाले GST के तहत मेकअप अधिक महंगा होगा।

## 13.3 अन्य घरेलू सामान और उपकरण

रसोई के बर्तन जैसे स्टेनलेस स्टील कुकर, पैन आदि। वे थोड़े सस्ते हैं क्योंकि उन पर GST के तहत 19.5% की पुरानी कर दर की तुलना में 12% की दर से शुल्क लिया जाता है।

नल, नल आदि जैसे स्वच्छता आइटम। GST के तहत महंगे हैं क्योंकि उन्हें 28% GST के तहत भी रखा गया है।

इसलिए, GST के तहत अपने घर की छोटी मरम्मत (नल को बदलना) और घरेलू उपकरणों को महंगा पड़ेगा।

## 13.4 दवाओं

मानव रक्त और इसके विभिन्न घटकों को GST के साथ-साथ मौजूदा कानूनों के तहत छूट दी गई है, इसलिए कीमतें तटस्थ रहेंगी।

केवल रासायनिक गर्भ निरोधकों (हार्मोन आधारित) को पहले छूट दी गई थी। अब कंडोम और अन्य गर्भ निरोधकों को भी GST के तहत छूट दी गई है।

मधुमेह रोगियों के लिए दवाओं सहित जीवन रक्षक दवाओं पर प्रभाव काफी हद तक तटस्थ है, जिस पर वैट /उत्पाद शुल्क व्यवस्था के तहत लगभग 5% कर लगाया गया था।

आयुर्वेदिक और अन्य वैकल्पिक दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि उन पर 12% GST के तहत कर लगाया जाता है।



### 13.5 मोबाइल नेटवर्क, डीटीएच और अन्य सेवाएं



सेवा उद्योग अब पहले के 15% की तुलना में 18% GST के तहत है। इसलिए, मोबाइल कनेक्शन, एजेंटों, ऐप के माध्यम से टिकटों की डीटीएच बुकिंग बढ़ेगी।

कंप्यूटर सस्ता होने की उम्मीद है।

### 13.6 रेस्तरां

करों में कमी के कारण ज्यादातर मामलों में बाहर भोजन करना सस्ता होगा। इससे पहले रेस्तरां पर कर 20.5% की प्रभावी दर पर आता था। इसे 5 स्टार रेस्तरां सहित सभी रेस्तरां के लिए घटाकर 18% GST कर दिया गया है। इससे भी बेहतर, शराब के बिना गैर-एसी रेस्तरां 12% कर के तहत और भी सस्ता होगा। कई रेस्तरां ने पहले से ही छूट और हैप्पी ऑवर कम कीमत देना शुरू कर दिया है।

इसलिए, GST में आपके वित्त पर बाहर खाना निश्चित रूप से आसान है।

### 13.7 मूवीगोअर्स

मूवी टिकट पर 28% और सिनेमाघरों में भोजन, पेय पर 18% GST लगेगा। GST का प्रभाव राज्यों के आधार पर मिला-जुला होगा। महाराष्ट्र, यूपी जैसे उच्च मनोरंजन कर वाले राज्यों को फायदा होगा क्योंकि यह अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को कम करेगा। हालांकि, GST का उन राज्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जहां पहले से ही कम मनोरंजन कर है जैसे कि पंजाब, राजस्थान।





### 13.8 बैंकिंग, वित्त और बीमा

विडंबना यह है कि सेवाओं पर कर की वृद्धि के कारण आपके वास्तविक वित्तीय लेनदेन आपके वित्त को 18% (पहले 15% से) तक कम कर देंगे

इसलिए, आपके जीवन, स्वास्थ्य, कार बीमा प्रीमियम में वृद्धि होगी। लोन प्रोसेसिंग आदि में सर्विस कंपोनेंट होने की वजह से लोन निकालने की लागत भी बढ़ेगी।

बैंकिंग सेवाओं पर वर्तमान में 15% सेवा कर लगता है जो GST के तहत बढ़कर 18% हो जाएगा। अधिकांश बैंकों ने विभिन्न बैंक एटीएम से नकद निकासी, शाखा से नकद निकासी पर लेनदेन शुल्क लागू किया है (दोनों के लिए पहले 5 मुफ्त हैं)। इन सभी पर 15% सेवा कर लगता था जो GST शासन के तहत बढ़कर 18% हो गया है।





### 13.9 सफ़र

मध्यम-बड़ी कारों की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि उन पर उपकर के साथ 28% GST लगेगा। हालांकि, छोटी कारों की कीमतों पर 1% -3% उपकर लगेगा, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में कमी आएगी। मध्यम आकार की कारों, एसयूवी और लक्जरी कारों पर 15 प्रतिशत उपकर लगेगा। मोटरसाइकिलों पर 3 प्रतिशत उपकर लगेगा।

ओला, उबर जैसी ऐप-आधारित कैब से यात्रा करना सस्ता हो गया है क्योंकि कर घटकर केवल 5% हो गया है। पहले से ही, हम यात्रा पर कम राशि का भुगतान करते हैं। इसके अलावा, सभी रेडियो टैक्सी कंपनियों ने मुनाफाखोरी विरोधी उपायों के अनुरूप विभिन्न छूट और ऑफ़र शुरू किए हैं।

### 13.10 पर्यटन

दरों के कारण रेलवे टिकटों में थोड़ी वृद्धि होगी, इकोनॉमी हवाई की कीमतें गिरेंगी। हालांकि, लक्जरी और बिजनेस क्लास टिकट की कीमतें बढ़ेंगी।

1000 रुपये प्रतिदिन से कम के बजट होटल के कमरों को GST से छूट दी गई है। 1000-2500 के बीच के कमरों पर 12% GST लगेगा। 2500-7500 के बीच के कमरों पर 18% के तहत कर लगाया जाएगा, 7500 से ऊपर के कमरों पर 28% की लक्जरी दर से कर लगाया जाता है। हाई-एंड लक्जरी कमरों को छोड़कर सभी कमरों के लिए होटल का किराया कम हो जाएगा।

### 13.11 सोना

सोना, हीरे, कीमती पत्थरों पर 3% GST लगेगा जो अधिकांश राज्यों में कीमतें बढ़ाएगा जहां पहले की दर 2% (1% उत्पाद शुल्क +



1% वैट) थी।



### 13.12 आवास

28% GST रेट की वजह से सीमेंट की कीमतें बढ़ेंगी। बदले में, बुनियादी ढांचे और आवास के लिए लागत जो सीमेंट पर अत्यधिक निर्भर हैं, भी बढ़ेगी।

इसके अलावा कार्यालय भवनों का किराया 18% GST के अधीन होगा। हालांकि आवासीय भवनों के किराए को GST से छूट दी गई है।



छूट सूची में केवल 100 वस्तुओं के शामिल होने की उम्मीद है क्योंकि छूट कर श्रृंखला को तोड़ती है और कर चोरी की गुंजाइश पैदा करती है। छोटी सूची रखने से कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं (आम आदमी की वस्तुएं) 12% और 18% से कम हैं

एक समान कर दर के कारण लॉजिस्टिक्स की कम लागत और सहज अंतर-राज्य परिवहन से ऑनलाइन शॉपिंग संतुलित होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दर तय करने के पीछे मुख्य सिद्धांत यह रहा है कि GST के तहत कर की दर किसी भी वस्तु के लिए नहीं बढ़ेगी। कोई वृद्धि नहीं हुई है। कई वस्तुओं पर, विशेष रूप से कमी आई है क्योंकि कर का व्यापक प्रभाव समाप्त हो गया है।



# 14 GST के तहत छूट क्या है?

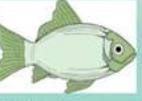
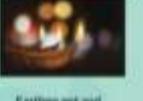
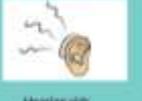
GST सभी वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया गया है।

कुछ वस्तुओं को जनता को लाभ पहुंचाने के लिए शून्य या 0% GST दर के तहत रखा जाता है।

निम्नलिखित वस्तुओं को GST के तहत स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।

## Exemptions under GST- Goods

### Goods @ 0%

 Edible vegetables, roots and tubers	 Cereals	 Fish (not frozen or processed)	 Fresh fruits & vegetables (Other than frozen or processed)	 Fresh ginger, Fresh Turmeric (other than in processed form)	 Human Blood and its components	 All types of sarbaapthiva	 Organic manure, other than those bearing a brand name
 Meat (Other than in frozen state and put up in unit containers)	 Cane jaggery (gur)	 Tender coconut water	 Silkworm laying cocoon	 Kumkum, Bindi, Sindur, Aha	 Firewood or fuel wood	 Wood charcoal	 Betel leaves
 Raw silk	 Silk waste	 Wool, not carded or combed	 Cotton used in Gandhi Topi	 Judicial, Nonjudicial Stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government, Treasuries or authorized Vendors	 Postal items like envelopes, Post card etc., sold by Government, rupee notes when sold to the RBI & Cheques	 Printed books, including Braille books, newspaper, maps	 Earthen pot and clay lamps
 Cotton used in Khadi Yarn	 Coconut, coir fibre	 Jute fibre raw or processed but not spun	 Puja samagri	 Bangles (except those made from precious metal)	 Agricultural implements manually operated or animal driven	 Hand tools, such as spades, shovels	 Haridra
 Live animals (except horses)	 All goods of seed quality	 Coffee beans, not roasted	 Unprocessed green tea leaves	 Spacecraft	 Hearing aids		

छूट के अन्य विशेष मामले हैं:



## LIST OF SERVICES EXEMPTED UNDER GST

# EXEMPT

- कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी) को आपूर्ति जो रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में है, लागू GST पर 50% रियायत का आनंद लेगा। मुआवजा उपकर पर कोई रियायत नहीं है, जिसका भुगतान अधिसूचित वस्तुओं या सेवाओं, या उनके द्वारा प्राप्त दोनों पर किया जाता है।
- सीएसडी द्वारा यूनिट रन कैंटीन/अंतिम उपभोक्ता को बिक्री और यूनिट रन कैंटीन द्वारा अंतिम उपभोक्ता को बिक्री को भी GST से छूट दी गई है।

18 मई 2017 और 3 जून 2017 को घोषित वस्तुओं पर GST दरों की पूरी सूची सीबीईसी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

### 0% GST पर सेवाओं को इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है:

#### 1. निम्नलिखित सेवाओं को छोड़कर सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवाएं:

- a) पोस्ट ऑफिस-स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली एजेंसी सेवाएं।
- b) एक विमान या एक पोत के संबंध में सेवाएं, एक बंदरगाह या हवाई अड्डे के परिसर के अंदर या बाहर
- c) माल या यात्रियों का परिवहन
- d) उपर्युक्त खंड (क) से (ग) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के अलावा कोई भी सेवा, व्यावसायिक संस्थाओं को प्रदान की जाती है।

#### 2. आरबीआई

- भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशन।
- पौधों की खेती और घोड़ों के पालन को छोड़कर सभी जानवरों का पालन
- टोल शुल्क के भुगतान पर सड़क या पुल तक पहुंच एक बिजली ट्रांसमिशन या वितरण उपयोगिता द्वारा बिजली का ट्रांसमिशन या वितरण
- निवास के रूप में उपयोग के लिए निवास भवन को किराए पर देना



### 3. माल का परिवहन:

- सेवाओं को छोड़कर सड़क मार्ग से
  - एक माल परिवहन एजेंसी, या
  - एक कूरियर एजेंसी,
- अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा

### 4. पशु चिकित्सक क्लिनिक

### 5. एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सेवाएं:

- कोई भी व्यक्ति (व्यवसाय नहीं)
- GST सीमा से कम कारोबार वाली व्यावसायिक इकाई (20 लाख रुपये) पिछले वित्तीय वर्ष में विशेष राज्यों के लिए 10 लाख रुपये)

### 6. एक साझेदारी फर्म या एक व्यक्तिगत वकील (वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं) , जो कानूनी सेवाएं दे रहा है

- कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाली एक अन्य साझेदारी फर्म या एक व्यक्तिगत वकील।
- कोई भी व्यक्ति (व्यवसाय नहीं)

### 7. GST सीमा से कम कारोबार वाली व्यावसायिक इकाई (20 लाख रुपये) विशेष राज्यों के लिए 10 लाख रुपये) पिछले वित्तीय वर्ष में GST एक वरिष्ठ अधिवक्ता पर लागू नहीं होता है जो कानूनी सेवाएं प्रदान करता है:

- कोई भी व्यक्ति
- एक व्यावसायिक इकाई

### 8. शिक्षा (प्री-स्कूल से हाई सेकेंडरी) सहित:

- छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का परिवहन
- मिड-डे मील और अन्य खानपान
- सुरक्षा और घर - स्कूलों में कीपिंग सेवाएं।
- उच्चतर माध्यमिक तक ऐसी संस्था में प्रवेश, या परीक्षा आयोजित करना।

### 9. लोक या शास्त्रीय (i) संगीत, या (ii) नृत्य, या (ii) रंगमंच में प्रदर्शन, यदि शुल्क 1000/- रुपये से कम है। 1,50,000।

- यदि कलाकार ब्रांड एंबेसडर के रूप में सेवाएं दे रहा है तो कोई छूट नहीं।

### 10. स्वतंत्र पत्रकार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समाचार एकत्र करना या प्रदान करना।

### 11. भर्ती से बाहर

- राज्य परिवहन- 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाला वाहन (बस)
- माल परिवहन एजेंसी, माल के परिवहन (ट्रक) के लिए।



## 12. यात्रियों का परिवहन:

- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य में स्थित हवाई अड्डे या पश्चिम बंगाल में स्थित बाग डोगरा में स्थित हवाई अड्डे से प्रस्थान करना या समाप्त करना।
- यात्रियों के परिवहन के लिए रेडियो टैक्सी के अलावा गैर-एसी अनुबंध कैरिज, पर्यटन को छोड़कर, टूर, चार्टर या किराए पर (कोलकाता से जोका जीप) आयोजित किया गया
- गैर-एसी घोड़ा गाड़ी

## 13. एक नैदानिक प्रतिष्ठान, एक डॉक्टर या पैरा - मेडिक्स द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

- एंबुलेंस

## 14. नई छूट:

- (GSTN) द्वारा सरकार (केंद्र या राज्य) को प्रदान की जाने वाली सेवाएं

## 15. एक व्यक्ति को निम्न के माध्यम से सेवा प्रदान करता है:

- किसी भी धार्मिक समारोह का संचालन।
- किसी धार्मिक स्थल के परिसर को किराए पर देना।
- 1,000 रुपये प्रति दिन से कम शुल्क वाले कमरों को किराए पर देना।

## 16. माल ढुलाई में निम्नलिखित वस्तुओं का परिवहन:

- कृषि उत्पाद
- ऐसा माल, जहां सकल प्रभारित राशि 10,000/- रुपये से कम हो। 1,500
- ऐसा माल जिसमें एक ही प्राप्तकर्ता के लिए सभी वस्तुओं के लिए प्रभारित सकल राशि 10,000/- रुपये से कम हो। 750 दूध, नमक और खाद्यान्न, समाचार पत्र
- चावल की लोडिंग, पैकिंग, भंडारण या भंडारण

## 17. प्रवेश:

- सर्कस, नृत्य, या नाटक या बैले सहित नाटकीय प्रदर्शन।
- पुरस्कार समारोह, संगीत कार्यक्रम, पेजेंट, संगीत प्रदर्शन या किसी मान्यता प्राप्त खेल आयोजन के अलावा कोई अन्य खेल आयोजन।
- मान्यता प्राप्त खेल आयोजन जहां प्रवेश मूल्य 250 रुपये प्रति व्यक्ति से कम है।

भविष्य में अन्य छूट भी मिल सकती हैं, जिनका खुलासा बाद में GST परिषद द्वारा किया जा सकता है।

## GST के बारे में विभिन्न विश्लेषण और राय!



चीजों की दिनचर्या में कोई भी विघटनकारी परिवर्तन अपने साथ बहुत सारी आशंकाएं और अनिश्चितता लाता है। यथास्थिति की चुनौती के परिणामस्वरूप न केवल इसे बहुत विरोध मिलता है, बल्कि यह गलत धारणा और अफवाह फैलाने की ओर भी जाता है।

GST भारत की अर्थव्यवस्था के कामकाज के तरीके में एक पथ-प्रदर्शक बदलाव रहा है और इस अप्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था के दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे जो कभी-कभी अकल्पनीय भी लगते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी को परिवर्तनों को समझना मुश्किल लगता है, लेकिन हवा को साफ करने, जागरूकता पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं कि हर किसी को काम करने के नए तरीके पर शिफ्ट होने और अंततः लाभ उठाने के लिए पर्याप्त समय मिले।

भले ही इस समय कई टैक्स स्लैब हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य "एक राष्ट्र एक कर" है और उस दिशा में एक सराहनीय शुरुआत की गई है। नई प्रणाली को व्यवस्थित होने और सकारात्मक ठोस परिणाम दिखाने में समय लगेगा, लेकिन इससे पहले, बहुत चर्चा और बहस करनी होगी ताकि प्रारंभिक झुर्रियों को दूर किया जा सके और आवश्यक बदलाव लाया जा सके।

ऐसा करने के लिए, किसी को यह समझना होगा कि GST विभिन्न क्षेत्रों पर कैसे प्रभाव डाल रहा है और इसे सुनी-सुनाई बातों या लोकप्रिय जनमत के बजाय डेटा के साथ समर्थन करने की आवश्यकता है।

इस प्रक्रिया की दिशा में पहला कदम अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना है: विनिर्माण, वितरण और खुदरा बिक्री, और सेवा उद्योग। इन दोनों पर GST की अलग-अलग दरें लगती हैं और दोनों मामलों में नई कर व्यवस्था का पूरा कामकाज अलग-अलग होगा।

आइए विकास के इन दोनों स्तंभों पर GST के प्रभाव का एक विहंगम दृश्य देखें:

## विनिर्माण, वितरण और खुदरा बिक्री पर GST का प्रभाव

भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद को उच्च अंकों में बढ़ाने के लिए एक मजबूत विनिर्माण आधार की आवश्यकता है। हालांकि, यह क्षेत्र कई करों से पीड़ित रहा है जो संचालन की उच्च लागत, जटिल प्रक्रियाओं का कारण बना और इसके परिणामस्वरूप कम क्षमता हुई। इसके अलावा, जटिलता के परिणामस्वरूप कई छोटे व्यवसाय पूरी कर भुगतान प्रक्रिया से बचते हैं और वास्तविक करों का भुगतान नहीं करने के लिए कमियां पाते हैं। GST लागू होने के साथ, कई करों के अनुपालन बोझ में कटौती की गई है, प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और उन सभी व्यवसायों को कर ब्रैकेट से बाहर लाया गया है। इससे कर प्रतिफल में वृद्धि होगी, परिचालन में पारदर्शिता आएगी और अंततः प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इस क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन होगा।

## सेवा प्रदाताओं पर GST का प्रभाव

पिछली कर व्यवस्था की कड़वी और काली वास्तविकताओं में से एक यह थी कि 14 मार्च तक देश में 12,76,861 सेवा कर दाताओं में से केवल शीर्ष 50 ने एकत्र किए गए कुल कर का 50% से अधिक का भुगतान किया। इस गंभीर वास्तविकता से पता चलता है कि इसका बोझ आईटी सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं, बीमा और बैंकिंग उद्योग और इसी तरह के लोगों द्वारा वहन किया गया था। भले ही वे संगठित तरीके से काम करते हैं और GST के साथ सभी आवश्यकताओं का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्हें कम कार्यभार का सामना करना पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप बेहतर अनुपालन होगा। इसलिए, GST के परिणामस्वरूप उनके प्रदर्शन में सुधार के साथ-साथ उनके वित्तीय क्षेत्र में बेहतर वृद्धि के कारण बेहतर कर संग्रह होना चाहिए।



अर्थव्यवस्था पर GST के निहितार्थ को और समझने के लिए, आइए एक नज़र डालें कि यह विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन के तरीके को कैसे बदल रहा है:

1. **लॉजिस्टिक्स:** यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अब तक यह काफी खंडित और असंगठित क्षेत्र है। GST के साथ, यह एकीकृत हो जाएगा और देश के आर्थिक विकास पर पर्याप्त प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त संगठित हो जाएगा। माल की आवाजाही निर्बाध होगी जिससे परिचालन लागत में कमी आएगी, मुनाफे में सुधार होगा और अंतिम उपभोक्ता को समग्र लाभ होगा।
2. **ई-कॉमर्स:** भारत उन कुछ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो युद्ध स्तर पर ई-कॉमर्स संचालन को अनुकूलित करती है- GST अपने लाभ के लिए काम करता है। हालांकि, ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ विवाद का एकमात्र बिंदु GST कानून के तहत प्रस्तावित एक नया तंत्र है, जो स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) तंत्र है। टीसीएस के लिए मौजूदा दर 1% है और कंपनियों की असुविधा को देखते हुए लंबे समय में इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।
3. **फार्मा:** फार्मा सेक्टर ने भारत को चिकित्सा पर्यटन में सबसे आगे लाया है, साथ ही सबसे गरीब लोगों को किफायती दर पर दवाएं प्रदान की हैं। GST जेनेरिक दवा निर्माताओं के लिए समान अवसर प्रदान करके और कर संरचना को सरल बनाकर इस क्षेत्र के कामकाज को और बढ़ाएगा।
4. **दूरसंचार:** यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने पिछले दो दशकों में काफी वृद्धि की है और समग्र आर्थिक विकास में शानदार योगदान दिया है। GST इस क्षेत्र के लिए एक वरदान की तरह आया है क्योंकि यह उनकी इन्वेंट्री के कुशल प्रबंधन और उनके गोदामों को मजबूत करके उनकी लागत को कम करने में मदद करेगा। दूरसंचार कंपनियों के मुनाफे को प्रभावित किए बिना दूरसंचार क्षेत्र में कीमतें कम होना तय है। इसके अलावा, हैंडसेट निर्माता GST के तहत अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकेंगे क्योंकि राज्य-विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना और स्टॉक के हस्तांतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। एक अन्य कारक जो इस क्षेत्र के पक्ष में काम करेगा, वह यह है कि रसद की लागत कम हो जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में बहुत जरूरी खुशी आएगी।
5. **वस्त्र:** देश में सबसे बड़े रोजगार जनरेटर में से एक माना जाता है, कपड़ा क्षेत्र बड़ी मात्रा में कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों को रोजगार देता है, भले ही कुल वार्षिक निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का हिस्सा वर्तमान में 10% है, लेकिन GST शासन के तहत इसके प्रभावशाली रूप से बढ़ने की उम्मीद है। GST कपड़ा उद्योग की कपास मूल्य श्रृंखला को प्रभावित करेगा, जिसका उपयोग अधिकांश छोटे उद्योगों द्वारा किया जाता है।

मध्यम उद्यमों को पहले शून्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क (वैकल्पिक मार्ग के तहत) लगता था।

6. **रियल एस्टेट:** अभी तक सिर्फ निर्माणाधीन परियोजनाओं को ही GST के दायरे में लाया जाता है, लेकिन पूरे सेक्टर पर GST लागू करने को लेकर बातचीत चल रही है। यह ध्यान देने योग्य है कि रियल एस्टेट क्षेत्र एक विशाल कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है, लेकिन साथ ही भ्रष्ट प्रथाओं और काले धन के सृजन के लिए भी बदनाम है। यह सुनिश्चित करना कि पूरा क्षेत्र GST के तहत आता है, न केवल अधिक पारदर्शिता लाएगा, यह संदिग्ध सौदों को खत्म करने और छाया अर्थव्यवस्था के दमन के साथ अर्थव्यवस्था में स्वस्थ, वास्तविक विकास में भी योगदान देगा।
7. **कृषि:** भारत सबसे लंबे समय से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहा है और आज भी, आंकड़ों के अनुसार, यह कुल जीडीपी में 16% योगदान देता है। इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक पूरे भारत में राज्यों में उपज का परिवहन रहा है। GST के साथ, इसका ध्यान रखा जाएगा क्योंकि खाद्य उत्पादों को GST से छूट दी गई है और यहां तक कि ऐसी उपज के राज्यों के बीच आवाजाही भी चुंगी और टोल नाकों को हटाने के साथ सहज होगी।



8. **एफएमसीजी:** एफएमसीजी सेक्टर को लागत बचाने के लिए हमेशा विभिन्न राज्यों में कई गोदाम और बिक्री डिपो स्थापित करने की आवश्यकता थी। GST के साथ, इस तरह के निश्चित अनावश्यक ओवरहेड्स की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और बचत को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत सी कंपनियां पहले ही विभिन्न उत्पादों की कीमतों को कम कर चुकी हैं और जल्द ही पूरा क्षेत्र GST कार्यान्वयन का लाभ देगा।
9. **फ्रीलांसर:** यह देश में एक काफी नया क्षेत्र है और जैसा कि कुछ नया होता है, इस क्षेत्र के लिए नियम और विनियम और कार्य स्थितियां स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं और प्रगति पर हैं। यह वह जगह है जहां GST फ्रीलांसरों के लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि वे अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। उन पर सेवा प्रदाताओं के रूप में कर लगाया जाएगा और नए कर ढांचे ने इस क्षेत्र में सामंजस्य और जवाबदेही लाई है।
10. **ऑटोमोबाइल:** एक राष्ट्र की प्रगति का अनुमान कभी-कभी नागरिकों द्वारा निजी ऑटोमोबाइल की मांग में वृद्धि से लगाया जा सकता है, भारत कोई अपवाद नहीं है और पिछले कुछ वर्षों में कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री को देखते हुए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र स्वस्थ है और बढ़ती अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुसार बढ़ रहा है। हालांकि, उत्पाद शुल्क, वैट, बिक्री कर, सड़क कर, मोटर वाहन कर, पंजीकरण शुल्क और इसी तरह के कई करों से यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। अच्छी खबर यह है कि GST ने ऐसे सभी करों को समाहित कर दिया है, जिससे ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए अपने करों का भुगतान करना और स्वच्छ लेखांकन सुनिश्चित करना आसान और कुशल हो गया है।
11. **स्टार्टअप:** मेक इन इंडिया और स्टार्टअप के उदय का समर्थन करने वाले पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, ऐसे आगामी उद्यमों के लिए करों के संदर्भ में भ्रम की स्थिति थी। इससे पहले, कई राज्यों में अलग-अलग वैट कानून थे जो उन कंपनियों के लिए जटिल साबित हुए जिनकी अखिल भारतीय उपस्थिति थी, विशेष रूप से ई - कॉमर्स क्षेत्र। लेकिन GST ने कारोबार के तरीके को बदल दिया है। यह पंजीकरण के लिए सीमा में वृद्धि, एक DIY अनुपालन मॉडल, खरीद पर कर क्रेडिट और वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह जैसे पर्याप्त और सार्थक लाभों के साथ आया है।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, GST का समग्र प्रभाव अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक है और परिणाम मध्यम से दीर्घकालिक विंडो में दिखाई देने लगेंगे। GST गरीबी को कम करने में मदद करेगा क्योंकि कर संग्रह बढ़ेगा और सरकार, राज्य के साथ-साथ केंद्र दोनों के पास विकास परियोजनाओं में योगदान करने के लिए अधिक संसाधन होंगे। इसके अलावा, करदाताओं के आधार में वृद्धि के साथ, पूर्ववर्ती शासन की तरह केवल कुछ करदाताओं पर बोझ गिर जाएगा और अधिक लोग राष्ट्र के विकास की जिम्मेदारी उठाएंगे। यह शुभ संकेत है क्योंकि हर कोई समृद्ध होता है, किसी और के समान कर का भुगतान करता है और विकास के फल का आनंद लेता है!



## 15 GST भुगतान और रिफंड पर एक अंतर्दृष्टि!

किसी भी विचार या विचार की सफलता उसे फलीभूत करने की क्रिया में निहित होती है। इसी तरह, किसी भी कानून की सफलता उसके सही कार्यान्वयन में निहित है। GST के लाभों के बारे में बहुत बहस हुई है और यह अर्थव्यवस्था में पर्याप्त बदलाव कैसे लाएगा। हालांकि, वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि जमीनी स्तर पर लाखों नागरिकों द्वारा बिना किसी जटिलता के और न्यूनतम त्रुटियों के साथ इसका वास्तविक कार्यान्वयन किया जाता है।

GST एक अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली है और पूरी प्रक्रिया में कोई भी त्रुटि करदाता या सरकार के लिए पर्याप्त वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए करदाता के लिए सही टैक्स फाइलिंग सिस्टम के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी संभावित त्रुटियों को खत्म या कम किया जा सके। दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रणाली को उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि प्रत्येक करदाता सरकारी कार्यालय में जाने या कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर सके। यह न केवल समय और संसाधनों को बचाता है, बल्कि यह डेटा का त्वरित अद्यतन भी सुनिश्चित करता है और वास्तविक समय में पूरी प्रक्रिया को सहज बनाता है।

हम पहले ही भरे जाने वाले GST के विभिन्न प्रकारों और फॉर्मों पर चर्चा कर चुके हैं। अब, हम इस बारे में बात करेंगे कि भुगतान कैसे किया जाना चाहिए और रिफंड कैसे लागू होगा और इसके लिए पूरी प्रक्रिया।

भुगतान करने की दिशा में पहला कदम पूर्ण और विस्तृत GSTR 1 और GSTR 2 दाखिल करना है। उसके बाद, एक डीलर को GSTR 3 दाखिल करने और फिर GST भुगतान करने की आवश्यकता होती है। रिफंड का दावा करने के लिए, प्रक्रिया शुरू करने के लिए समय पर भरे और जमा किए जाने वाले प्रासंगिक फॉर्म हैं।

आसान समझ के लिए विस्तृत भुगतान प्रक्रिया निम्नलिखित है:



### 15.1 GST के तहत क्या भुगतान किया जाना है?

GST कानून ने पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल रखा है और भुगतान किए जाने वाले कर को 3 में विभाजित किया गया है:

- IGST - यह तब होता है जब माल की अंतरराज्यीय आपूर्ति होने पर कर का भुगतान करना पड़ता है। इसका भुगतान केंद्र को किया जाता है।
- CGST - इसका भुगतान तब किया जाना है जब किसी राज्य के भीतर माल की आपूर्ति की जाती है। फिर, इस कर का भुगतान केंद्र को किया जाता है।
- SGST - यह कर तब भी दिया जाता है जब राज्य के भीतर माल की आपूर्ति की जाती है लेकिन राज्य को भुगतान किया जाता है।

बेहतर समझ के लिए यहां एक उदाहरण दिया गया है:



स्थिति	CGST	SGST	IGST
असम से कोलकाता तक बेचा जाने वाला सामान	नहीं	नहीं	हाँ
असम के भीतर बेचे जाने वाले सामान	हाँ	हाँ	नहीं
असम से सिलीगुड़ी में बेचा गया सामान	हाँ	हाँ	नहीं

उपर्युक्त भुगतानों के अलावा, एक डीलर को निम्नलिखित भुगतान भी करने की आवश्यकता होती है:

- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस): टीडीएस GST के तहत तैयार किया गया एक तंत्र है जहां आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने से पहले डीलर द्वारा कर काटा जाता है।
- स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस): यह ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स को लक्षित है। जब भी कोई डीलर ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से बिक्री करता है, तो उसे 2% की दर से टीसीएस की कटौती के बाद अपना भुगतान मिलेगा।
- रिवर्स चार्ज: इस मामले में, कर का भुगतान करने की देयता माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बजाय रिसीवर पर है।

## 15.2 GST भुगतान की गणना कैसे करें?

कुल GST भुगतान की गणना करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को बाहरी कर देयता से कम करना होगा। उसके बाद, टीडीएस / टीसीएस को कुल GST से कम कर दिया जाएगा और शुद्ध देय राशि की गणना की जाएगी। इस आंकड़े में, अंतिम राशि तक पहुंचने के लिए कोई विलंब शुल्क या ब्याज जोड़ा जाएगा। कृपया ध्यान दें कि ब्याज और विलंब शुल्क पर ITC का दावा नहीं किया जा सकता है।

अब, अंतिम राशि तक पहुंचने के लिए गणना विभिन्न डीलरों के लिए अलग-अलग है, जो निम्नानुसार है:

- रेगुलर डीलर: एक नियमित डीलर बाहरी आपूर्ति पर GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और की गई खरीद पर ITC का दावा भी कर सकता है। देय GST बाहरी कर देयता और ITC के बीच का अंतर है।
- कंपोजिशन डीलर: GST कानून ने कंपोजिशन डीलरों के लिए गणना को तुलनात्मक रूप से आसान बना दिया है। उन्हें कुल बाहरी आपूर्ति पर GST का एक निश्चित प्रतिशत देना होगा। कंपोजिशन डीलर के प्रकार के आधार पर GST का भुगतान किया जाएगा।

यहाँ बताया गया है कि कैसे:

व्यवसाय के प्रकार	CGST	SGST	कुल GST
निर्माण	1%	1%	2%
व्यापारी (माल)	0.5%	0.5%	1%
खाद्य / पेय के लिए आपूर्तिकर्ता	2.5%	2.5%	5%

मानव उपभोग के लिए

सेवा प्रदाता कंपोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकते



### 15.3 भुगतान कौन करेगा?

निम्नलिखित डीलर GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं:

- पंजीकृत डीलर GST देयता मौजूद है।
- पंजीकृत डीलर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है
- ई- कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस एकत्र करने और भुगतान करने के लिए
- डीलरों को कटौती करने की आवश्यकता है।

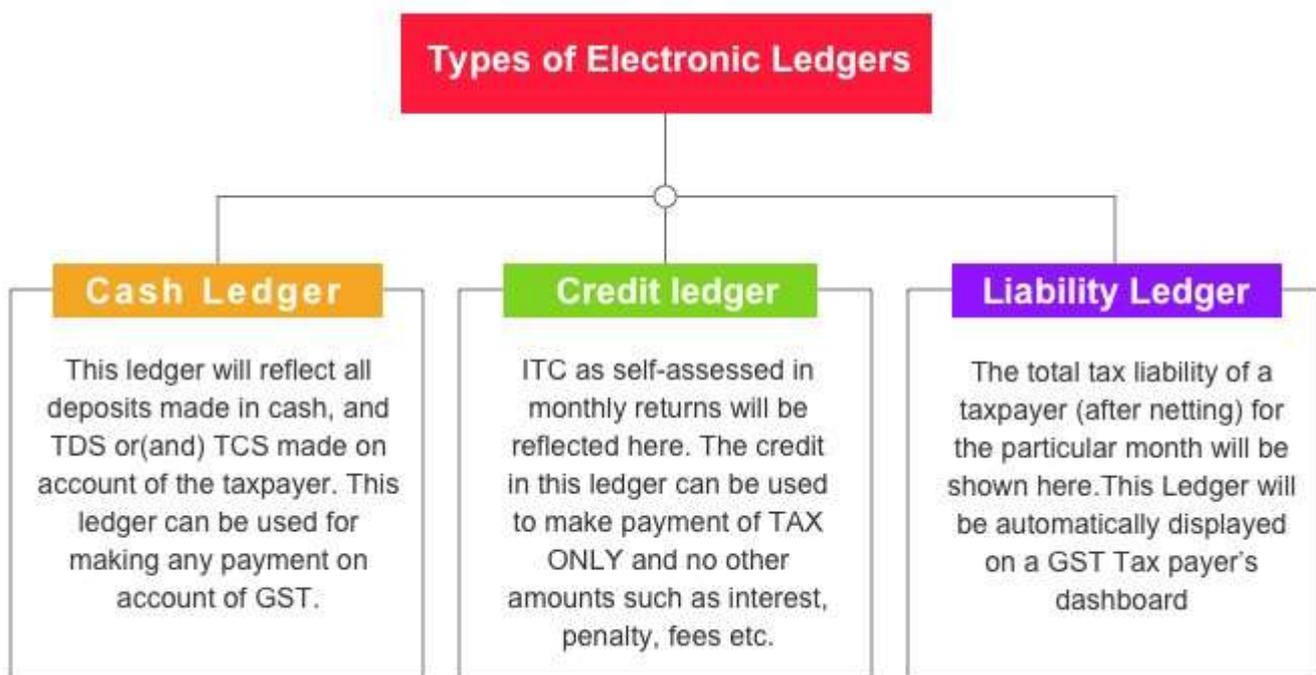
### 15.4 GST भुगतान के लिए टीडीएस तिथि

GST भुगतान अगले महीने की 20 तारीख तक GSTR 3 दाखिल करने के साथ किया जाना है।

### 15.5 इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्या हैं?

ये वे बही-खाते हैं जो GST पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए जाते हैं। वे निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं:

1. कैश लेजर: यह करदाता की ओर से किए गए टीडीएस / टीसीएस के साथ नकद में किए गए सभी जमा को दर्शाता है। इसका उपयोग GST के कारण किसी भी भुगतान के लिए किया जा सकता है।
2. क्रेडिट लेजर: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मासिक रिटर्न में स्व-मूल्यांकन के रूप में यहां परिलक्षित होगा। यहां क्रेडिट का उपयोग केवल कर का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है और ब्याज, जुर्माना, शुल्क आदि जैसी किसी और चीज के लिए नहीं।
3. देयता लेजर: किसी विशेष महीने के लिए करदाता की कुल कर देयता इस बहीखाते में दिखाई देगी और यह स्वचालित रूप से GST करदाता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होगी।





## 15.6 GST भुगतान कैसे करें?

इस तरह के भुगतान निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक द्वारा किए जा सकते हैं:

1. क्रेडिट लेजर के माध्यम से
2. कैश लेजर के माध्यम से: GST पोर्टल पर चालान जनरेट करने के बाद भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। 10,000 रुपये से अधिक के किसी भी कर भुगतान को अनिवार्य रूप से केवल ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

## 15.7 भुगतान न करने या विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना

यदि GST का भुगतान कम किया जाता है, अवैतनिक किया जाता है या देर से भुगतान किया जाता है, तो डीलर द्वारा 18% की दर से ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है।

इसके साथ ही जुर्माना भी देना होगा और यह 10,000 रुपये या कम भुगतान किए गए या अवैतनिक कर का 10% होगा।

आइए एक नजर डालते हैं रिफंड प्रक्रिया पर GST के तहत भ्रम से बचने के लिए क्लेम रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और यहां तक कि इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है।

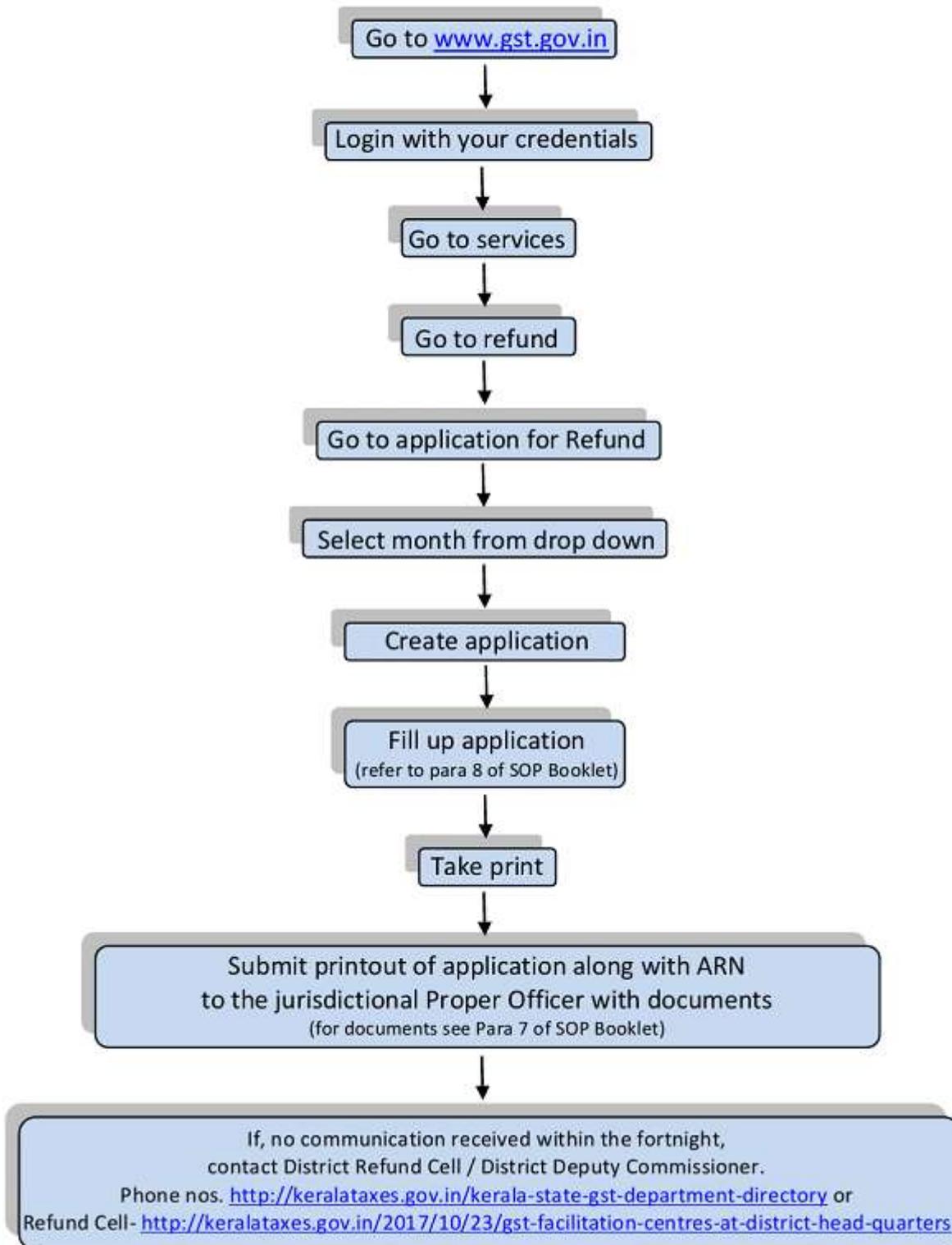
## 15.8 रिफंड का दावा कब किया जा सकता है?

यदि अतिरिक्त कर का भुगतान किया गया है, तो रिफंड का दावा किया जा सकता है। धनवापसी का दावा करने वाले कुछ परिदृश्य हैं:

- छूट या धनवापसी के दावे के तहत डीलर निर्यात (डीमड निर्यात सहित) वस्तुएं / सेवाएं।
- आउटपुट छूट या शून्य रेटेड होने के कारण ITC संचय।
- दूतावासों या संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा की गई खरीद पर भुगतान किए गए कर की वापसी।
- अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कर वापसी
- अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना



## STEPS TO BE FOLLOWED BY DEALER IN THE ROLLS OF STATE GST DEPARTMENT SEEKING REFUND



### 15.9 GST रिफंड की गणना कैसे करें?

गणना को समझने के लिए यहां एक उदाहरण दिया गया है।



आइए दिसंबर महीने के लिए एक डीलर की देयता 25,000 रुपये पर विचार करें, लेकिन वह 2.5 लाख रुपये का भुगतान करता है। अब GST भुगतान के रूप में 2.25 लाख रुपये की इस अधिक राशि को रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है। GST कानून डीलर को रिफंड का दावा करने के लिए भुगतान की तारीख से 2 साल की समय सीमा की अनुमति देता है।

### 15.10 रिफंड का दावा कैसे करें?

आप भुगतान की तारीख से दो साल के भीतर या व्यक्तिगत मामले के अनुसार फॉर्म आरएफडी 01 में रिफंड आवेदन जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग अपने दम पर GST शासन में शामिल हों और मजबूर और धमकी के बिना सक्रिय रूप से इसका हिस्सा बनें, पूरी भुगतान और रिफंड प्रक्रिया को सरल और समझने और पालन करने में आसान रखा गया है।



## 16 भारत में वस्तु एवं सेवा कर का भविष्य क्या है?

भविष्य हमेशा अतीत की सफलताओं और विफलताओं और वर्तमान में किए गए कार्यों से सीखे गए सबक से निर्धारित होता है। यह भारत में वस्तु और सेवा कर (GST) के लिए बिल्कुल सच है, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे परिवर्तनकारी कर सुधार है! हम पूंजीवाद से दूर रहे और 1947 में आजादी के बाद से सबसे लंबे समय तक एक बंद अर्थव्यवस्था बने रहे, जब तक कि अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण यथास्थिति को चुनौती नहीं दी गई, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग-थलग रहना अब संभव नहीं था, सत्ता में सरकारों ने अतीत से सबक सीखा और देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया। कदम दर कदम हमने बढ़ना शुरू किया और फिर देश की पूरी कराधान प्रणाली को बदलने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि इसे अपनी क्षमता प्राप्त करने और देश में एक शक्तिशाली शक्ति बनने में मदद मिल सके।

हालांकि, भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में व्यापक सुधार लाना हमेशा एक चुनौती होती है क्योंकि आम सहमति बनाने और विस्तृत रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता हमेशा अराजक होती है। कई ताकतें हैं जो चीजों को एक साथ अलग-अलग दिशाओं में खींच रही हैं और इसलिए परिवर्तन लाने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर कठिन है।



यही वजह है कि 2006 में GST लागू होने के बावजूद इसे वास्तव में लागू होने में लगभग 11 साल लग गए। वर्ष 2006 में संसद में GST पेश किए जाने के बाद से, यह एक अत्यधिक बहस का विषय रहा है, क्योंकि इसे अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इसके अलावा, GST को कई करों को बदलने और भारत में एकीकृत कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। GST का मूल सूत्रीकरण वर्तमान कराधान प्रणाली के साथ उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करना था, जिनका सामना भारत सरकार और नागरिक करों के भ्रष्टाचार, असमान और अधिक बोझ जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। GST को संसद में पारित होने और लागू होने के लिए कई वर्षों तक इंतजार किया गया, यहां तक कि एक फुलप्रूफ रोडमैप तैयार किए जाने के बाद भी।

3 अगस्त 2016 वह दिन था जब आखिरकार बिल पारित हो गया और GST को 1 जुलाई, 2017 से लागू करने का निर्णय लिया गया। अब, जब GST पूरी तरह से लागू है, और भारतीय नागरिक सुधार के विचार और लाभों से अच्छी तरह से वाकिफ हो रहे हैं, तो आइए हम राष्ट्र में GST के संभावित भविष्य पर एक नज़र डालें:

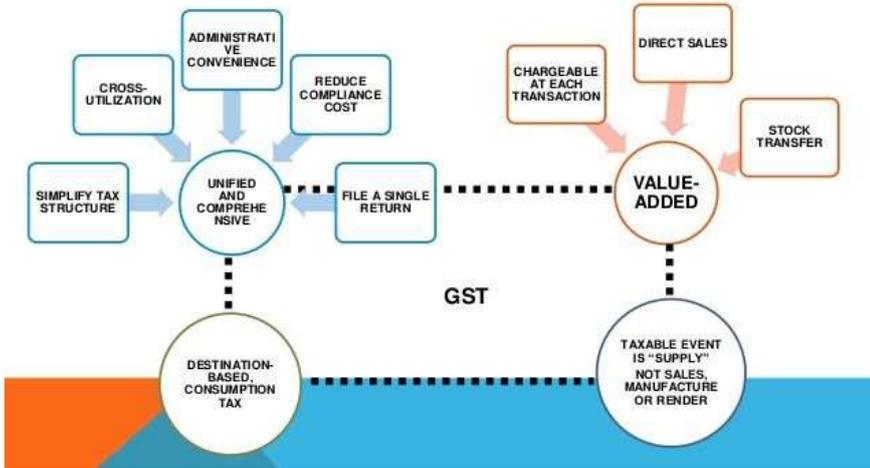


1. GST से पहले, बहुत सारे छोटे, मध्यम और यहां तक कि बड़े उद्यम कर दायरे से बाहर थे और केवल कुछ ही लोग पूरे देश की ओर से करों का भुगतान करते थे। भविष्य में, GST यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक व्यक्ति और संगठन कर आधार का हिस्सा होंगे और करों का भुगतान करेंगे। इसका मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए अतिरिक्त आय जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश के लिए विकास और समृद्धि है।
2. **करों में एकरूपता:** चूंकि GST ने कई करों को समाहित कर दिया है, इसलिए GST के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप करों में एकरूपता का मतलब है कम भ्रम, कम अस्पष्टता और यहां तक कि कर व्यवस्था से बाहर रहने के कम कारण। GST को अपने सरल तंत्र के कारण नागरिकों से व्यापक स्वीकृति मिलेगी और सभी को समान स्तर पर लाया जाएगा।
3. **भले ही GST को चार अलग-अलग टैक्स स्लैब के साथ लॉन्च किया गया है, लेकिन अंतिम लक्ष्य उन्हें और कम करना है और पूरे देश के लिए सिर्फ दो या शायद एक ही कर के साथ समाप्त होता है वर्तमान में, कई करों की आवश्यकता देश भर में आय में अंतर के कारण है। नमक का पैकेट खरीदने वाले किसी व्यक्ति को लकजरी कार खरीदने के समान कर का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, एक बार जब प्रणाली व्यवस्थित हो जाती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है और एक व्यवहार्य पैटर्न उभरता है, तो GST दरें कम हो जाएंगी, जिससे 'एक राष्ट्र एक कर' एक वास्तविकता बन जाएगा!**
4. **निवेश और आर्थिक विकास:** स्पष्ट नीतियों और पारदर्शी कर ढांचे के साथ, देश में व्यापार करना आसान हो जाएगा। आर्थिक बाधाएं कम होंगी और देश के भीतर और बाहर दोनों जगहों से अधिक निवेश आएगा। अधिक संगठन भारत के साथ और भारत में व्यापार करने की कोशिश करेंगे और यह देश के आर्थिक विकास के लिए अच्छा है। प्रतिकूल कर व्यवस्था कई संगठनों को ऐसे देशों में व्यवसाय करने से रोकती है। GST के प्रभाव में आने के साथ, यह मल्टीनेशन कंपनियों के लिए दुकान स्थापित करने और भारत की आर्थिक विकास कहानी का हिस्सा बनने के लिए एक अतिरिक्त एसओपी प्रदान करता है।
5. **रोजगार सृजन:** अधिक निवेश, आर्थिक विकास और व्यापार करने में आसानी के साथ, रोजगार सृजन गति पकड़ सकता है। भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था को देखते हुए अधिकांश कार्यबल या तो असंगठित क्षेत्र में है या छोटे और मध्यम क्षेत्र में नियोजित किया जा रहा है। अधिकांश उद्यमों के नई कर व्यवस्था का हिस्सा बनने के साथ, व्यवसाय लंबी अवधि में बढ़ेंगे और इसके परिणामस्वरूप अधिक रोजगार सृजन होगा।
6. **कम काली अर्थव्यवस्था:** काले धन से लड़ना एक कठिन चुनौती और एक सतत प्रक्रिया है। छाया अर्थव्यवस्था, जैसा कि इसे कहा जाता है, कभी गायब नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत कम हो जाएगी क्योंकि करों की चोरी, कर व्यवस्था के बाहर काम करने और असंगठित व्यापार का हिस्सा होने की संभावनाएं काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी।
7. **उपयोगकर्ता के अनुकूल:** GST के बारे में सबसे अच्छी बात जो भविष्य में होगी, वह यह है कि यह अधिक से अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल हो जाएगा क्योंकि सरकार प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने के लिए आम नागरिकों और उद्योग निकायों से लगातार प्रतिक्रिया ले रही है। GST लागू होने के एक चौथाई के भीतर ही जमीनी स्तर पर कई बदलाव हुए हैं, जिनमें विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर कर स्लैब में बदलाव, निर्यातकों को वैश्विक फर्मों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना, पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करना शामिल है। एक बार जब यह कर व्यवस्था अपनी वास्तविक भावना और रूप में लागू हो जाती है, तो सरकार को नागरिकों को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया जाएगा क्योंकि सभी के लिए लाभ इसे अनुकूलित करना अनिवार्य बना देगा।



GST लागू होने से वितरण चैनल के चरणों के माध्यम से कर का निर्बाध प्रवाह होगा, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सभी चीजें कम्प्यूटरीकृत की जाएंगी, जिससे प्रशासनिक प्रणाली को लाभ होगा, और यह लाभ बेहतर बुनियादी ढांचे, भ्रष्टाचार - कम

### HOW GST SOLVES PRESENT PROBLEMS



मामलों की स्थिति और मन की शांति के रूप में आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

अब तक, GST देश में एक उज्ज्वल भविष्य का कारण है। यह उत्पादन बढ़ाने और देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करने की उम्मीद है, यह राष्ट्र के लिए एक गेम चेंजर है और सभी हितधारक एकजुट होंगे और कुछ ऐसा विकसित करेंगे जो पूरे भारतीय उद्योग के लिए फायदेमंद होगा।



## 17 GST के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर



### 17.1 GST क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) देश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक कर है। यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल मूल्य वर्धन पर एक कर है और प्रत्येक चरण में एक आपूर्तिकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र के माध्यम से सेट-ऑफ करने की अनुमति है यानी, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर भुगतान किए जाने वाले कर के खिलाफ सेट ऑफ के लिए उपलब्ध है। अधिनियम, नियम और सभी भारतीय राज्यों में GST की दर एक समान होने की उम्मीद है।

### 17.2 प्रस्तावित GST कैसे काम करता है?

आपूर्ति श्रृंखला के तीन चरणों में GST की लेवी और सेट-ऑफ के लिए एक सांकेतिक उदाहरण नीचे दिया गया है:

आपूर्ति श्रृंखला का चरण	निर्माता	पूरे विक्रेता	खुदरा
इनपुट का क्रय मूल्य (INR)	100	150	175
मूल्य वर्धन (INR)	50	25	15
बिक्री मूल्य (INR)	150	175	190
GST की दर	18%	18%	18%
आउटपुट पर GST (INR)	27	31.5	34.2
इनपुट पर GST (INR)	18	27	31.5
आउटपुट-इनपुट टैक्स क्रेडिट पर शुद्ध GST = GST (यानी, मूल्य वर्धन पर कर) (INR)	$27 - 18 = 9$	$31.55 - 27 = 45$	$33.2 - 31.55 = 2.7$



### 17.3 किसी विशेष राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लेनदेन पर केंद्रीय GST (CGST) और राज्य GST (SGST) के तहत एक साथ कर कैसे लगाया जाएगा?

भारत में प्रस्तावित GST 'दोहरे GST मॉडल' पर आधारित होगा, जिसमें परिकल्पना की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों एक साथ CGST अधिनियम और SGST अधिनियम के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े किसी विशेष राज्य के भीतर सभी लेनदेन पर कर लगाएंगी। ये कर करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाते हैं और सीधे संबंधित सरकार के CGST / SGST खातों में जाएंगे।

मौजूदा व्यवस्था के तहत सेवाओं और विनिर्माण लेनदेन पर कर लगाने की शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं जबकि बिक्री लेनदेन पर कर लगाने की शक्ति विशेष रूप से राज्य सरकारों के पास है।

### 17.4 अंतर-राज्य लेनदेन पर कर लगाने का तंत्र क्या होगा?

वस्तुओं और सेवाओं की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर एकीकृत GST (IGST) अधिनियम के तहत कर लगाया जाएगा। IGST अधिनियम के तहत GST की दर मोटे तौर पर CGST और SGST दरों के कुल योग के बराबर होगी। IGST को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित IGST खाते में जमा किया जाना है और इसे पारस्परिक रूप से सहमत फार्मूले पर केंद्र सरकार और उपभोक्ता राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

IGST का संग्रह तंत्र निम्नानुसार है:

अंतर-राज्य विक्रेता IGST का भुगतान करने के लिए अपनी खरीद पर IGST, CGST और SGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर सकता है।

### 17.5 GST के तहत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित कर क्या हैं?

CGST के तहत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित केंद्रीय करों में शामिल हैं:

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- औषधीय और प्रसाधन सामग्री तैयारी अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क लगाया गया
- वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत लगाया गया सेवा कर
- अतिरिक्त सीमा शुल्क, जिसे आमतौर पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) के रूप में जाना जाता है
- सीमा शुल्क (एसएडी) केंद्रीय बिक्री कर का विशेष अतिरिक्त शुल्क
- अधिभार
- केंद्रीय उपकर।

GST के तहत शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित राज्य कर हैं:

- वैट/बिक्री कर
- मनोरंजन कर (जब तक कि यह स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लगाया जाता है)



- लकजरी टैक्स
- लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर
- राज्य उपकर और अधिभार जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं।
- प्रवेश कर
- ऑक्ट्रोआई /लोकल बॉडी टैक्स

## 17.6 वे कौन से सामान/क्षेत्र हैं जो GST के दायरे से बाहर होंगे?

GST के दायरे से बाहर होने वाले सामानों/क्षेत्रों में अल्कोहल और निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पाद यानी पेट्रोलियम कूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस शामिल हैं। पेट्रोलियम उत्पादों को बाद में GST में शामिल किया जाएगा। शराब पर राज्य उत्पाद शुल्क और वैट लगता रहेगा तंबाकू और तंबाकू आधारित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और GST दोनों लागू होंगे। स्टांप ड्यूटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि टैक्स GST का हिस्सा नहीं होंगे।

## 17.7 GST के तहत दर संरचना क्या होगी?

प्रस्तावित दर संरचना में 5, 12, 18, 28 और 28 प्रतिशत + उपकर के अलावा उन वस्तुओं को शामिल किया गया है जिन पर शून्य दर (पूरी तरह से छूट) पर कर लगाया जाता है, GST टैरिफ को संदर्भित किया जा सकता है, ताकि संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दर का पता चल सके।

## 17.8 GST के तहत थ्रेशोल्ड लिमिट और कंपाउंडेड लेवी क्या होगी?

न्यूनतम सीमा एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार के लिए 2 मिलियन रुपये है। हालांकि, कुछ राज्यों में सीमा घटाकर 1 मिलियन रुपये कर दी गई है, कंपोजिशन योजना 5 मिलियन रुपये तक के कारोबार के लिए उपलब्ध है और कर की दर CGST अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्दिष्ट होगी।

CGST अधिनियम की धारा 23 उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है (उदाहरण के लिए, एक किसान, पूरी तरह से छूट प्राप्त कारोबार वाला व्यक्ति आदि)। CGST अधिनियम की धारा 24 उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें टर्नओवर के बावजूद पंजीकरण लेने की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए, अंतर-राज्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति आदि)। )

## 17.9 GST के तहत आयात पर कैसे लगेगा टैक्स?

प्रस्तावित GST व्यवस्था के तहत, हालांकि माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की लेवी जारी रहेगी, अतिरिक्त सीमा शुल्क, वर्तमान विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) को IGST द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर भुगतान किए गए IGST का पूरा सेट-ऑफ उपलब्ध होगा, जबकि आयात पर भुगतान किया गया बीसीडी सेट-ऑफ के लिए पात्र नहीं होगा। सेवाओं के आयात के मामले में रिवर्स चार्ज के आधार पर IGST लगाया जाएगा और इसका क्रेडिट कानून के अनुसार आयातक-प्राप्तकर्ता को उपलब्ध होगा।



## 17.10 GST के तहत क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे काम करेगा?

CGST और SGST दोनों वस्तुओं और सेवाओं पर एक साथ लगाए गए दोहरे GST शासन के तहत दो समानांतर कर हैं। इसलिए, SGST आउटपुट टैक्स देयता के भुगतान के लिए CGST इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्रॉस उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, GST क्रेडिट पूल CGST और SGST के साथ जुड़ा हुआ है और इसका उपयोग IGST, CGST और SGST के भुगतान के लिए किया जा सकता है। IGST क्रेडिट के उपयोग का क्रम पहले IGST, फिर CGST और शेष SGST देयता के लिए होगा। इसी तरह, SGST क्रेडिट का उपयोग पहले SGST देयता के लिए और फिर IGST के लिए किया जा सकता है, जबकि CGST क्रेडिट का उपयोग पहले CGST और फिर IGST के लिए किया जाएगा।

## 17.11 GST को लागू करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों है?

भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कराधान की शक्तियों का सीमांकन करता है। जबकि केंद्र को उत्पादन के चरण तक सेवाओं और वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार है, राज्यों को माल की बिक्री पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्यों के पास सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने की शक्ति नहीं है जबकि केंद्र के पास वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। प्रस्तावित 'दोहरी GST व्यवस्था' के तहत सभी सेवाओं और वस्तुओं पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा एक साथ कर लगाया जाएगा। इसलिए संविधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में संशोधन करना अनिवार्य है ताकि राज्य और केंद्र सरकारें एक साथ वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगा सकें।

## 17.12 माल की आपूर्ति पर GST लगाने का क्या मतलब होगा?

वर्तमान में, भारत एक मूल-आधारित कर प्रणाली का पालन करता है और इसलिए कराधान का बिंदु बिक्री के मूल में है और मूल राज्य कर को इस तरह एकत्र करता है, चाहे उपभोक्ता कहीं भी स्थित हो। प्रस्तावित GST व्यवस्था के तहत, जो एक बहु-बिंदु लेवी है (यानी, मूल्य श्रृंखला में प्रत्येक मूल्य वर्धन पर लगाया जाता है), कर माल के साथ आगे बढ़ेगा और IGST अधिनियम के तहत निर्धारित आपूर्ति के स्थान के आधार पर गंतव्य राज्य के खाते में जमा किया जाएगा। आपूर्ति पर GST लगाया जाएगा और लेवी का बिंदु CGST अधिनियम की धारा 12 के तहत आपूर्ति के समय के अनुसार निर्धारित किया जाएगा

## 17.13 सेवाओं की आपूर्ति पर GST लगाने का क्या मतलब होगा?

सेवाओं पर GST आपूर्ति पर एक कर होगा और लेवी का बिंदु CGST अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। राजस्व को उस राज्य को भेजा जाएगा जहां IGST अधिनियम के तहत निर्धारित आपूर्ति के स्थान के आधार पर सेवा का उपभोग किया जाता है। डिफॉल्ट रूप से, सेवाओं की आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां सेवा प्राप्तकर्ता बी 2 बी लेनदेन के मामले में स्थित है और बी 2 सी लेनदेन के मामले में सेवा प्रदाता का स्थान है। हालांकि, इस नियम के अपवाद हैं।

## 17.14 नए व्यवसायों / आवेदकों के लिए प्रस्तावित GST व्यवस्था के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी?

प्रत्येक करदाता को राज्यवार स्थायी खाता संख्या (पैन) आधारित 15 अंकों की वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (GSTआईएन) आवंटित की जाएगी। वे करदाता जो पहले से ही वर्तमान राज्य या केंद्रीय कर व्यवस्था के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें सामान्य पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के अनुरोध के साथ GST पंजीकरण का स्वतः संज्ञान



लिया जाता है, जहां आवश्यक हो, एक नए आवेदक को पूर्व नामांकन के बिना सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

### 17.15 मौजूदा व्यवसायों / आवेदकों के लिए GST के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी?

वर्तमान समय के तहत, कर को राज्य और / या केंद्रीय कर प्रशासन के साथ या उनकी व्यावसायिक गतिविधि के आधार पर दोनों के साथ अलग से पंजीकृत किया जाता है। GST व्यवस्था में, एक करदाता को राज्यवार पंजीकरण प्राप्त करना होगा। यहां तक कि एक राज्य के भीतर, करदाता के पास विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के लिए कई पंजीकरण प्राप्त करने का विकल्प होगा।

### 17.16 GST शासन के तहत जारी किए जाने वाले कर चालान की सामग्री क्या है?

कर योग्य वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति करने वाला एक पंजीकृत करदाता आपूर्ति के समय एक कर चालान जारी करेगा, जिसमें लेन-देन का पूरा विवरण अर्थात्, मूल्यांकक का नाम, पता और खरीदार/सेवा प्राप्तकर्ता का GSTआईएन, चालान की तारीख, माल/सेवा का मूल्य, माल सेवा का विवरण, CGST, SGST या IGST की दर और मूल्य, करदाता के हस्ताक्षर, आदि।

### 17.17 रिटर्न कैसे और कब दाखिल किया जाना चाहिए?

मसौदा कानून में CGST, SGST और IGST के लिए एक साझा ई-रिटर्न का प्रस्ताव है। रिटर्न, जो विक्रेताओं से डेटा की ऑटो-आबादी और चालान के स्वचालित मिलान की अनुमति देता है, एक सामान्य / आकस्मिक करदाता द्वारा विभिन्न कट-ऑफ तिथियों के भीतर अनुक्रमिक तरीके से ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा। रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रस्तावित विभिन्न नियत तिथियां इस प्रकार हैं:

नहीं।	रिटर्न/लेजर	लागू प्रपत्र का विवरण	नियत तिथि
1	GSTR-1	करदाता द्वारा की गई बाहरी आपूर्ति (कंपाउंडिंग करदाता और आईएसडी के अलावा)	अगले महीनों में से 10
2	GSTR-2	एक करदाता द्वारा प्राप्त आवक आपूर्ति (एक कंपाउंडिंग करदाता और आईएसडी के अलावा)	अगले महीनों में से 15।
3	GSTR-3	मासिक रिटर्न (कंपाउंडिंग करदाता और आईएसडी के अलावा)	अगले महीनों में से 20
4	GSTR-4	कंपाउंडिंग करदाता के लिए त्रैमासिक रिटर्न	तिमाही के अगले महीनों में से 18 पंजीकरण का अंतिम दिन
5	GSTR-5	अनिवासी विदेशी करदाता द्वारा आवधिक रिटर्न	पंजीकरण की अंतिम तिथि
6	GSTR-6	इनपुट सेवा वितरक (ISD) के लिए वापसी	अगले महीनों में से 13
7	GSTR-7	स्रोत पर काटे गए कर के लिए रिटर्न	अगले महीनों में से 10
8	GSTR-8	GSTR-8 ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा दाखिल किया जाने वाला रिटर्न है, जिन्हें GST के तहत टीसीएस (स्रोत पर कर एकत्र) में कटौती करने की आवश्यकता होती है। GSTR-8 में शामिल हैं	अगले महीने की 10 तारीख
9	GSTR-9	वार्षिक रिटर्न	अगले वित्त वर्ष की 31 दिसंबर



यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिकांश रिटर्न GSTN प्रणाली द्वारा स्वतः उत्पन्न होते हैं, और डीलर से डेटा को सत्यापित करने और लापता डेटा को भरने की उम्मीद की जाती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि GST शासन के तहत वैध रिटर्न दाखिल करने के लिए देय कर का भुगतान आवश्यक है।

### 17.18 कर के भुगतान का तरीका क्या है?

भुगतान के तीन अलग-अलग तरीकों के तहत सभी करों के लिए एक सामान्य 'चालान' (यानी, करों के भुगतान के लिए दस्तावेज) के साथ कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड में है:

- डेबिट कार्ड सहित इंटरनेट बैंकिंग।
- आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान
- नकद चेक या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) में काउंटर भुगतान (प्रति कर अवधि में INR 10,000 / - तक के भुगतान के लिए)

### 17.19 GST के तहत निर्यात पर कर कैसे लगेगा?

GST के तहत निर्यात शून्य रेटेड है, जिसका अर्थ है कि कर नहीं होगा और इनपुट करों को वापस कर दिया जाएगा।

### 17.20 GST व्यवस्था में कोई करदाता कब रिफंड के लिए जा सकता है? प्रस्तावित GST कानून के तहत रिफंड प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

मौजूदा मैनुअल सत्यापन प्रणाली के विपरीत GST के तहत रिफंड व्यवस्था को सरल बनाए जाने की उम्मीद है। धनवापसी निम्नलिखित परिदृश्यों में प्राप्त किया जा सकता है:

- निर्यात पर रिफंड
- कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी केवल उल्टे शुल्क संरचना के मामले में दी जाती है।

### 17.21 प्रस्तावित GST व्यवस्था के तहत विवाद समाधान तंत्र कैसे काम करता है?

GST कानून के तहत एक विस्तृत निर्णय और अपीलीय प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विवादों से निपटने के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण नामक एक अलग अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा।

### 17.22 GST ढांचे के तहत वर्तमान व्यवस्था में दी गई क्षेत्र-आधारित छूटों सहित विभिन्न छूटों का क्या होता है?

GST व्यवस्था के तहत न्यूनतम छूट और रियायतों की उम्मीद है। हालांकि, सरकारों द्वारा दी गई क्षेत्र-आधारित कर छूट जैसी कुछ छूटों की अवधि GST शासन तक विस्तारित होगी और सरकारों को प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना पड़ सकता है।

चूंकि GST व्यवस्था के तहत कर छूट संभव नहीं हो सकती है, इसलिए यह छूट अभी भी कर संग्रह के बाद पोस्ट-टैक्स नकद रिफंड योजनाओं के रूप में दी जा सकती है, ताकि GST श्रृंखला परेशान न हो। हालांकि किसी नई छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी, मौजूदा विशेष औद्योगिक क्षेत्र योजना हो सकती है।



### 17.23 उपभोग पर गंतव्य आधारित कर की अवधारणा वास्तव में क्या है?

कर कर प्राधिकरण को प्राप्त होगा जिसके पास उपभोग के स्थान पर अधिकार क्षेत्र है जिसे आपूर्ति का स्थान भी कहा जाता है।

### 17.24 GST व्यवस्था के तहत विवादों को कैसे हल किया जाएगा?

संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2016 में प्रावधान है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद किसी भी विवाद पर निर्णय लेने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी:

- भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या
- भारत सरकार और एक तरफ किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच; नहीं तो
- दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, परिषद की सिफारिशों या उनके कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है।

### 17.25 अनुपालन रेटिंग तंत्र का उद्देश्य क्या है?

CGST अधिनियम की धारा 149 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को निर्दिष्ट मापदंडों के संबंध में अनुपालन के रिकॉर्ड के आधार पर अनुपालन रेटिंग सौंपी जाएगी। ऐसी रेटिंग को सार्वजनिक डोमेन में भी रखा जाएगा। एक संभावित ग्राहक आपूर्तिकर्ताओं की अनुपालन रेटिंग देखने और निर्णय लेने में सक्षम होगा कि किसी विशेष आपूर्तिकर्ता के साथ सौदा करना है या नहीं। यह कर योग्य व्यक्तियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा।

### 17.26 क्या कार्रवाई योग्य दावे GST के लिए उत्तरदायी हैं?

CGST/SGST अधिनियम की धारा 2 (52) के अनुसार कार्रवाई योग्य दावों को माल माना जाना चाहिए। CGST अधिनियम की धारा 7 के साथ पढ़ी गई अनुसूची उन गतिविधियों या लेनदेन को सूचीबद्ध करती है जिन्हें न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। अनुसूची लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के अलावा कार्रवाई योग्य दावों को ऐसे लेनदेन में से एक के रूप में सूचीबद्ध करती है। इस प्रकार, केवल लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए को GST शासन के तहत आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। अन्य सभी कार्रवाई योग्य दावे आपूर्ति नहीं होंगे।

### 17.27 क्या प्रतिभूतियों में लेनदेन GST में कर योग्य है?

प्रतिभूतियों को विशेष रूप से वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इस प्रकार, प्रतिभूतियों में लेनदेन GST के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

### 17.28 सूचना वापसी की अवधारणा क्या है?

सूचना वापसी स्वतंत्र तृतीय-पक्ष स्रोतों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों के अनुपालन स्तरों को सत्यापित करने के विचार पर आधारित है। CGST/SGST अधिनियम की धारा 150 के अनुसार, कई प्राधिकरण जो पंजीकरण या खातों के विवरण या किसी भी आवधिक रिटर्न या दस्तावेज के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें कर के भुगतान और माल या सेवाओं के लेनदेन के अन्य विवरण या बैंक खाते या बिजली की खपत या खरीद के लेनदेन से संबंधित लेनदेन का विवरण है। माल या संपत्ति की बिक्री या आदान-प्रदान या किसी समय लागू किसी कानून के तहत संपत्ति में अधिकार या ब्याज, ऐसी



अवधि के संबंध में, ऐसे समय के भीतर, ऐसे रूप और तरीके से और ऐसे प्राधिकरण या एजेंसी को जो निर्धारित किया जाए, उसके लिए सूचना विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर धारा 123 के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।

### **17.29 विभिन्न कंपनियों के पास विभिन्न प्रकार के लेखा सॉफ्टवेयर पैकेज हैं और रिकॉर्ड रखने के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप अनिवार्य नहीं है। विभाग इन जटिल सॉफ्टवेयर को कैसे पढ़ सकता है?**

CGST अधिनियम की धारा 153 के अनुसार, किसी मामले की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए और राजस्व के हित में, विभाग किसी भी स्थिति में जांच, पूछताछ, जांच या किसी अन्य कार्यवाही में विशेषज्ञ से सहायता ले सकता है।

### **17.30 क्या प्राप्तकर्ता द्वारा लौटाए गए माल के कर उपचार के लिए GST में कोई प्रावधान है?**

हां, धारा 34 ऐसी स्थितियों से संबंधित है। जहां आपूर्ति किए गए माल प्राप्तकर्ता द्वारा लौटाए जाते हैं, पंजीकृत व्यक्ति (माल का आपूर्तिकर्ता) प्राप्तकर्ता को निर्धारित विवरणों वाला एक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है। क्रेडिट नोट का विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा उस महीने के रिटर्न में घोषित किया जाएगा जिसके दौरान ऐसा क्रेडिट नोट जारी किया गया था, लेकिन उस वर्ष के अंत के बाद सितंबर के बाद नहीं जिसमें ऐसी आपूर्ति की गई थी या संबंधित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तारीख, जो भी पहले हो। क्रेडिट नोट का विवरण प्राप्तकर्ता द्वारा उसी कर अवधि या बाद की किसी भी कर अवधि के लिए अपने वैध रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे में इसी कमी के साथ मिलान किया जाएगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा आउटपुट टैक्स देयता में कमी के लिए दावा जो प्राप्तकर्ता द्वारा ITC के दावे में इसी कमी के साथ मेल खाता है, को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और दोनों पक्षों को सूचित किया जाएगा।

### **17.31 क्या बिना विचार के की गई आपूर्ति भी GST के दायरे में आएगी?**

हां, लेकिन केवल वे गतिविधियां जो CGST अधिनियम/SGST अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट हैं। उक्त प्रावधान को IGST अधिनियम के साथ-साथ UTGST अधिनियम में भी अपनाया गया है।

### **17.32 क्या किसी धर्मार्थ संस्था द्वारा आवश्यक वस्तुओं को देना कर योग्य गतिविधि होगी?**

एक आपूर्ति होने के लिए जो GST के तहत कर योग्य है, लेनदेन व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ने में होना चाहिए। चूंकि धर्मार्थ गतिविधियों के लिए आपूर्ति में कोई लेन-देन शामिल नहीं है, इसलिए यह GST के तहत आपूर्ति नहीं है।

### **17.33 माल या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में लेनदेन को कौन सूचित कर सकता है?**

केंद्र सरकार या राज्य सरकार, GST परिषद की सिफारिशों पर, किसी गतिविधि को माल की आपूर्ति के रूप में अधिसूचित कर सकती है, न कि सेवाओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति और न ही वस्तुओं की आपूर्ति या न तो वस्तुओं की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति।



### 17.34 समग्र आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति क्या हैं? ये दोनों एक-दूसरे से कैसे अलग हैं?

समग्र आपूर्ति एक आपूर्ति है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं या दोनों या उनके किसी भी संयोजन की दो या दो से अधिक कर योग्य आपूर्ति होती है, जो प्राकृतिक पाठ्यक्रम में बंडल की जाती हैं और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में आपूर्ति की जाती हैं और जहां उनमें से एक प्रमुख आपूर्ति है। उदाहरण के लिए, जब कोई उपभोक्ता एक टेलीविजन सेट खरीदता है और उसे टीवी के साथ वारंटी और रखरखाव अनुबंध भी मिलता है, तो यह आपूर्ति एक समग्र आपूर्ति है। इस उदाहरण में, टीवी की आपूर्ति प्रमुख आपूर्ति है, वारंटी और रखरखाव सेवा सहायक हैं।

मिश्रित आपूर्ति वस्तुओं या सेवाओं की एक से अधिक व्यक्तिगत आपूर्ति का संयोजन है, या एक ही कीमत के लिए एक दूसरे के साथ संयोजन में किया गया कोई भी संयोजन है, जिसे आमतौर पर अलग से आपूर्ति की जा सकती है। उदाहरण के लिए, रेफ्रिजरेटर के साथ भंडारण पानी की बोतलें बेचने वाला एक दुकानदार। बोतलों और रेफ्रिजरेटर को आसानी से अलग से कीमत और बेचा जा सकता है।

### 17.35 GST के तहत समग्र आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति का उपचार क्या है?

समग्र आपूर्ति को मूल आपूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। मिश्रित आपूर्ति को उस विशेष वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा जो कर की उच्चतम दर को आकर्षित करता है।

### 17.36 क्या सभी वस्तुएं और सेवाएं GST के तहत कर योग्य हैं?

मानव उपभोग के लिए मादक शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर योग्य है। पेट्रोलियम कूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन की आपूर्ति भविष्य की तारीख से कर योग्य होगी। यह तिथि GST परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

### 17.37 रिवर्स चार्ज से क्या तात्पर्य है?

इसका मतलब है कि कर का भुगतान करने की देयता आपूर्ति की अधिसूचित श्रेणियों के संबंध में ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बजाय वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर है,

### 17.38 क्या रिवर्स चार्ज तंत्र केवल सेवाओं पर लागू है?

नहीं, रिवर्स चार्ज वस्तुओं और सेवाओं दोनों की आपूर्ति पर लागू होता है, जैसा कि GST परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है

### 17.39 अपंजीकृत व्यक्तियों से आपूर्ति प्राप्त होने के मामले में क्या निहितार्थ होंगे?

किसी अपंजीकृत व्यक्ति से आपूर्ति प्राप्त होने के मामले में, पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाएं प्राप्त कर रहा है, रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।



## 17.40 क्या आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति GST के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है?

हां, केंद्र /राज्य सरकार सेवाओं की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा भुगतान किया जाएगा, यदि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति इसके माध्यम से की जाती है और अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।

## 17.41 कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्स चुकाने का विकल्प चुनने की सीमा क्या है?

कंपोजिशन स्कीम के लिए सीमा पिछले वित्त वर्ष में कुल कारोबार का 50 लाख रुपये है। कंपोजिशन स्कीम का लाभ चालू वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये के टर्नओवर तक उठाया जा सकता है।

## 17.42 कंपोजिशन स्कीम के लिए टैक्स की दरें क्या हैं?

अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग-अलग रेट हैं। माल के आपूर्तिकर्ता (यानी व्यापारियों) के सामान्य मामलों में, कंपोजिशन दर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार का 0.5% है। यदि कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति निर्माता है, तो यह दर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार का 1 प्रतिशत है। रेस्तरां सेवाओं के मामले में, यह किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार का 2.5 प्रतिशत है। ये दरें एक अधिनियम के अंतर्गत हैं और यही दर दूसरे अधिनियम में भी लागू होगी। इसलिए, प्रभावी रूप से, कंपोजिशन दरें (CGST और SGST / UTGST के तहत संयुक्त दर) सामान्य आपूर्तिकर्ता, निर्माता और रेस्तरां सेवा के लिए क्रमशः 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 5 प्रतिशत हैं।

## 17.43 एक वित्तीय वर्ष के दौरान कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये के कारोबार को पार कर जाता है यानी वह दिसंबर में 50 लाख रुपये के कारोबार को पार कर जाता है? क्या उसे वर्ष की शेष अवधि यानी 31 मार्च तक कंपोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी?

नहीं। यह विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाएगा, जिस दिन वित्त वर्ष के दौरान उनका कुल कारोबार 50 लाख रुपये से अधिक हो जाएगा।

## 17.44 क्या एक कर योग्य व्यक्ति, जिसके पास कई पंजीकरण हैं, केवल कुछ पंजीकरणों के लिए कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र होंगे?

समान स्थायी खाता संख्या (पैन) रखने वाले सभी पंजीकृत व्यक्तियों को कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनना होगा। यदि एक पंजीकृत व्यक्ति सामान्य योजना का विकल्प चुनता है, तो अन्य कंपोजिशन योजना के लिए अयोग्य हो जाते हैं।

